



वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

2017/8

# शिक्षा में जवाबदेही

अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Sustainable  
Development  
Goals



Global  
Education  
Monitoring  
Report

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का सार

2017/8

# शिक्षा में जवाबदेही

अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए

शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा-पत्र और कार्य ढाचे में इस आदेश का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में “एसडीजी 4 पर तथा अन्य एसडीजी में शिक्षा की निगरानी और रिपोर्ट करने की प्रणाली होनी चाहिए” जिसकी जवाबदेही “राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतियों को लागू करना होगा ताकि संपूर्ण एसडीजी पर बाद में की जाने वाली कार्रवाई एवं समीक्षा के एक भाग के रूप में इससे जुड़े सभी भागीदारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाने में सहायता की जा सके”। इसे यूनेस्को द्वारा गठित एक स्वतंत्र टीम द्वारा तैयार किया गया है।

इस प्रकाशन में दिए गए पदनाम और प्रस्तुत सामग्री का अर्थ किसी देश, प्रादेशिक सीमा, नगर या क्षेत्र या इसके प्राधिकारियों या इसकी सीमाओं का सीमांकन करने के संबंध में यूनेस्को की ओर से कोई राय, जो कोई भी हो, अभिव्यक्ति करना नहीं है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट दल इस रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के चयन और प्रस्तुति तथा इसमें व्यक्त राय के लिए जिम्मेदार है। यह जरूरी नहीं कि इसमें व्यक्त विचार यूनेस्को के हों, और संगठन इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है। रिपोर्ट में व्यक्त विचारों और राय की पूरी जिम्मेदारी इसके निदेशक की है।

## वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम

निदेशक : मैनुस एंटोनिनिस

मेडेलिन बैरी, निकोल बेल्ला, निहान कोसेलेकी बलांकी, एन्ना डी' एडियो, प्रियदर्शिनी जोशी, कटारजायना कुबक्का, लेईला लुपिस, कास्सियानी लिश्रंगोमिटिस, अलासडायर मैकविलियम, अनीसा मेकाटर, ब्रेनवेन मिलर, कलोडइन मुकीजवा, युकी मुराकामी, टाया लुईज ओवेन्स, जूडिथ रन्ड्रिआनाटोआविना, केट रेडमैन, मैरिया रोजनोव, विल स्मिथ एवं रोजा विडरटे।

जीईएम रिपोर्ट दल अपने सेवानिवृत्त निदेशक, एरॉन बेनावोट के कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस रिपोर्ट के अनुसंधान और विकास की अगुवाई की।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन है। जीईएम रिपोर्ट का वित्त-पोषण सरकारों, बहु-स्तरीय एजेसियों और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के एक समूह द्वारा किया जाता है और इसके लिए सहायता और सुविधा यूनेस्को द्वारा प्रदान की जाती है।



यह प्रकाशन ऐट्रिब्यूशन-शेयरएलाइक 3.0 आईजीओ (सीसी-बीवाई-एसए 3.0 आईजीओ) लाइसेंस (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>) के अंतर्गत सभी के लिए उपलब्ध है। इस प्रकाशन की सामग्री का प्रयोग करने पर इसका प्रयोग करने वाला यूनेस्को के सर्व सुलभ संग्रह (<http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en>) के इस्तेमाल की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।



अंग्रेजी में मूल शीर्षक: Global Education Monitoring Report Summary 2017/8: Accountability in education: Meeting our commitments

#### अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

ग्लोबल शिक्षा निगरानी रिपोर्ट टीम  
द्वारा यूनेस्को, 7, प्लेस डे फोनटेनोए  
75352 पैरिस 07 एसपी, फ्रांस  
ई-मेल: [gemreport@unesco.org](mailto:gemreport@unesco.org)  
दूरभाष: +33 145 680741  
[www.unesco.org/gemreport](http://www.unesco.org/gemreport)  
<https://gemreportunesco.wordpress.com>

मुद्रण में बाद में पाई गई किसी भूल-चूक को ऑनलाइन  
पाठ [www.unesco.org/gemreport](http://www.unesco.org/gemreport) में सुधारा जाएगा।

© यूनेस्को, 2017  
सर्वाधिकार सुरक्षित  
प्रथम संस्करण  
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और  
सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2017 में प्रकाशित

7 प्लेस डे फोनटेनोए, 75352  
पैरिस 07 एसपी, फ्रांस

यूनेस्को द्वारा टाइपसेट  
ग्राफिक डिजाइन एफएचआई 360 द्वारा  
लेआउट एफएचआई 360 द्वारा

ED-2017/WS/38/REV

#### नई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

2017/8: शिक्षा में जवाबदेही: अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए  
2016 लोगों और संपूर्ण पृथ्वी के लिए शिक्षा: सभी के लिए सुनिश्चित भविष्य का सृजन

#### ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट श्रृंखला

2015 सभी के लिए 2000-2015 तक शिक्षा: उपलब्धियां और चुनौतियां  
2013/4 अध्यापन और शिक्षण: सभी के लिए गुणवत्ता प्राप्त करना।  
2012 युवा और कौशल: शिक्षा को कार्य से जोड़ना  
2011 छिपा संकट: सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा  
2010 उपेक्षित वर्गों तक पहुंच बनाना  
2009 असमानता दूर करना: ज्ञासन क्यों जरूरी है  
2008 2015 तक सभी के लिए शिक्षा: क्या हम इसे पूरा करेंगे?  
2007 ठोस आधार: शुरुआती बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा  
2006 जीवन के लिए साक्षरता  
2005 सभी के लिए शिक्षा: गुणवत्ता की अनिवार्यता  
2003/4 जेंडर और सभी के लिए शिक्षा: समानता की ओर कदम  
2002 सभी के लिए शिक्षा: क्या दुनिया सही रास्ते पर है?

आवरण पृष्ठ और पिछले आवरण पृष्ठ पर चित्र: डेविड टेट  
कार्टून - गोडफे मवेम्बेवा (जीएडीओ)

सचित्र प्रस्तुति - होस्टोनिक डिजाइन नेटवर्क

आवरण चित्र - वेन्डेल प्राइमरी स्कूल, इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) में किए जा रहे विरोध का है।

यह सारांश रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्रियां: [bitly.com/CountOnME](http://bitly.com/CountOnME) and [gem-report-2017.unesco.org](http://gem-report-2017.unesco.org) से डाउनलोड की जा सकती हैं।

## प्रस्तावना

आज की तारीख में 264 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल नहीं जा रहे हैं - यह एक ऐसी विफलता है जिसका हम सभी को मिलकर समाधान करना चाहिए क्योंकि शिक्षा एक साझा उत्तरदायित्व है और प्रगति केवल संयुक्त प्रयासों से ही चिरस्थायी रह सकती है। यह शिक्षा संबंधी स्थायी विकास (एसडीजी 4) की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जो स्थायी विकास के एजेंडा 2030 का एक भाग है। यहां सरकारों, विद्यालयों और अध्यापकों को विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ मिलकर एक अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक है, यह जानना भी जरूरी है कि इन सीमाओं का कब और कहां उल्लंघन हुआ है और क्या जवाबी कार्रवाई की जानी है - यही जवाबदेही का अर्थ है, जिस पर इस वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में ध्यान केन्द्रित किया गया है। निष्कर्ष बिलकुल साफ है - जवाबदेही न हो तो विकास के रूकने का जोखिम बना रहता है, जिससे शिक्षा प्रणालियों में हानिकारक परिपाटियां जुड़ने लगती हैं। यदि सरकारों द्वारा शिक्षा संबंधी योजनाओं की रूपरेखा स्पष्ट न हो, तो भूमिकाएं धुंधली हो जाती हैं और इसका आशय होगा कि वायदे खोखले हो जाएंगे और नीतियों के लिए धन नहीं मिलेगा। जब सरकारी प्रणालियां बेहतर शिक्षा प्रदान नहीं कर पाती हैं, और जब लाभ कमाने वाले लोग नियमों को ताक पर रखकर इस कमी को पूरा करने लगते हैं, तो उपेक्षित और हाशिए पर रहने वाले लोग दरकिनारा हो जाते हैं। शिक्षा का अधिकार लागू करना सरकारों का मुख्य कार्य है, परंतु इस अधिकार का लगभग आधे देशों द्वारा ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता, और शिकायत करने वालों की अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

शिक्षा में सुधार के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। यह नागरिकों से प्रारम्भ होती है, और इसमें नागरिक सामाजिक संगठनों और अनुसंधान संस्थाओं का सहयोग शामिल होता है, जो उच्च-गुणवत्ता, समान शिक्षा स्तर में व्याप्त कमियों को बतलाते हैं। कई देशों में विद्यार्थी आंदोलनों ने प्रायः एक-समान और सस्ती शिक्षा नीतियां बनाने में कारगर भूमिका निभाई है, जो उन अधिकारों का द्योतक है जो हम सभी को हासिल हैं और हमें एसडीजी4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे समय की जटिल चुनौतियों के अनुरूप नए लक्ष्यों और क्षेत्रों को आकार प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

इस रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि वर्तमान में सभी जवाबदेह प्रणालियां एसडीजी4 को हासिल करने में हमारी मदद नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के कुछ भागों में घटिया परीक्षा परिणाम आने पर गुणवत्तापरक निर्देशों और अध्यापन में सुधार करने के कथित प्रयासों के नाम पर अध्यापकों और स्कूलों पर प्रतिबंध लगाना आम होता जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अवाञ्छित और प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए ऐसा बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए।

इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि गहन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित उच्च कौशल परीक्षा से 'प्रतिस्पर्धा की दौड़' शुरू हो जाएगी, जिसका पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उपेक्षित तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा में असमानता को बढ़ावा देने वाले तथ्यों को उजागर करने के लिए अध्यापन के निष्कर्षों के आंकड़ों का संग्रह करना काफी महत्व रखता है। परन्तु सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए समय, धन और कौशल चाहिए, जो कुछ ही देशों के पास हैं, और गलत निष्कर्ष निकालना बेहद आसान है।

जवाबदेही का अर्थ है, जब कुछ गलत हो रहा हो, तो नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए लोकपाल के माध्यम से या नीतिगत, कानूनी सलाह देकर कार्रवाई करना। हमें हर जगह शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए सुदृढ़ प्रणालियों की आवश्यकता है, तथा साथ ही दानदाताओं एवं सभी सरकारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाना होगा।

'जवाबदेही' शब्द का प्रयोग 2030 शिक्षा कार्य संरचना की पूरी रिपोर्ट में किया गया है, जो यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निरंतर विकास और निगरानी करने के लिए, बाद में की जाने वाली कार्रवाई तथा कार्यों की समीक्षा को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि सभी देशों को राष्ट्रीय शिक्षा निगरानी रिपोर्टें तैयार करनी चाहिए, जिनमें उनकी प्रतिबद्धताओं की तुलना में उनकी प्रगति को दर्शाया जाए - वर्तमान में लगभग आधे देश ही ऐसा कर रहे हैं और उनमें से ज्यादातर देश नियमित तौर पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। जवाबदेही का अर्थ है, साक्ष्यों की व्याख्या करना, समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान करने के लिए तरीके खोजना। यह सभी के लिए एक-समान और बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के हमारे सभी प्रयासों का आधार होना चाहिए।

इरीना बोकोवा  
महानिदेशक, यूनेस्को



# शिक्षा में जवाबदेही

2017/8 जीईएम रिपोर्ट में वैश्विक शिक्षा प्रणालियों के संबंध में यूएन स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी)4: सभी के लिए समग्र, समान और अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा तथा आजीवन शिक्षा सुनिश्चित करना' के विजन की उपलब्धियों के संबंध में जवाबदेही की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।

बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षा उपलब्ध कराना, तथा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के साक्ष्य ने प्रावधानों और गुणवत्ता में निरंतर कमियों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा, सीमित शिक्षा बजट और दुनिया भर में धन को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण देश इनका समाधान निकालने को बाध्य हुए हैं। जवाबदेही बढ़ाना इस सूची में हमेशा सबसे ऊपर रहा है।

जवाबदेही एक नैतिक गुण हो सकता है, जो गुणवत्ता को उत्तरदायी और विश्वसनीय रूप में परिभाषित करता है। इस रिपोर्ट में, इसे एक प्रणाली के तौर पर परिभाषित किया गया है। विधिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा नैतिक आधार पर सरकारें और अन्य शिक्षा कार्यकर्ता अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होते हैं।

चूंकि, महत्वाकांक्षी शिक्षा परिणाम प्रायः कई प्रकार के कार्यकर्ताओं पर निर्भर होते हैं, जो सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, अतः जवाबदेही किसी एक कार्यकर्ता पर निर्भर नहीं हो सकती। जैसाकि इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, एसडीजी4 लक्ष्य को प्राप्त करना और समग्र, समान और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना प्रायः एक सामूहिक प्रयास होता है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संगठित प्रयास करते हैं (चित्र 1)। इसे अमल में लाने के लिए राजनैतिक और आर्थिक हितों में तालमेल स्थापित करना होता है। शिक्षा नीतियां और कार्यकर्ता अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं होते।

“

समग्र, समान और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना प्रायः एक सामूहिक प्रयास होता है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संगठित प्रयास करते हैं

”

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी जवाबदेही दृष्टिकोण तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कार्यकर्ताओं को अनुकूल माहौल न मिले अथवा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन न हों। स्पष्ट सूचना, पर्याप्त संसाधन और क्षमता न होने के कारण उनके प्रयास में रूकावट उत्पन्न होगी। एक-दूसरे पर दोषारोपण करने वाली परिपाटियों में सुधार करने से एक-समान, समग्र, उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रणालियां सृजित होने की संभावना है।

एक दूसरे पर दोषारोपण बंद करो  
शिक्षा एक सारी जिम्मेदारी है



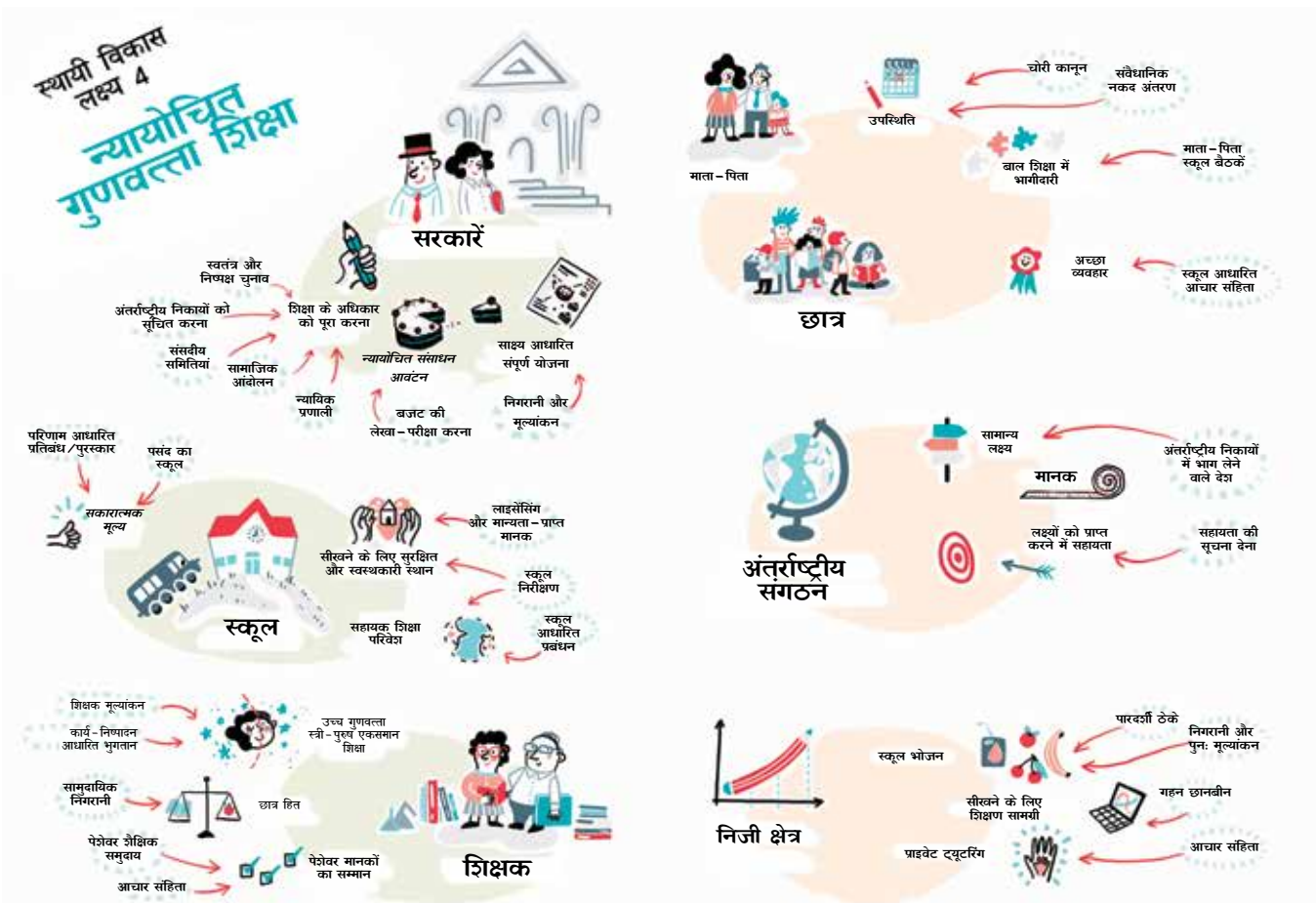
व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग और संवाद की आवश्यकता होती है। लोगों का विश्वास और समर्थन उन लक्ष्यों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है जिन्हें तर्कसंगत माना जाता है और जिन्हें सीमित संसाधनों के भीतर प्राप्त किया जा सकता हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो लोगों की रुचि न होने से वे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे और अभिभावक विमुख हो जाएंगे। जिन प्रणालियों के प्रति आस्था नहीं होती, वहां शिक्षा में सुधार के धीमा और सतही होने की संभावना रहती है। विश्वास कायम करने के लिए यह जरूरी है कि साझा लक्ष्यों में कई हितधारक शामिल हों और परस्पर जवाबदेही के माध्यम से कार्यकर्ताओं की एक-दूसरे पर निर्भरता को पहचाना जाए।

विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक रुझानों ने शिक्षा नीतियों में जवाबदेही पर अत्यधिक बल दिए जाने की हिमायत की है। 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में शिक्षा का तेजी से विस्तार होने के कारण शिक्षा प्रणालियों का प्रबंधन करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उच्च आय वाले देशों में इस चुनौती के प्रति सरकारी प्राधिकारियों की एक प्रतिक्रिया यह रही है कि न केवल शिक्षा जगत में, अपितु अन्य क्षेत्रों में भी 'प्रबंधन निवेश' की बजाय 'प्रबंधन परिणाम' पर ध्यान दिया जाए। स्थानीय सरकारों और विद्यालयों की तुलना करने के लिए ऐसे पैमाने और मानक बनाए गए हैं जिनसे नतीजों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि स्थानीय नियंत्रण को बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रावधानों का विकेन्द्रीकरण किया गया, जबकि केन्द्र सरकार ने वित्तपोषण, निगरानी और विनियमन का उत्तरदायित्व अपने पास रखा। इसके अलावा, कुछ देशों में सरकारी शिक्षा से असंतुष्ट होने के कारण ऐसी नीतियां अस्तित्व में आईं जिनमें प्रावधानों का विस्तार करते हुए एक ऐसे शिक्षा 'बाजार' का सृजन किया गया, जहां अभिभावक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और गुणवत्ता प्राप्त करने के आशय से प्रकाशित स्कूलों की रैंकिंग के आधार पर स्कूलों का चयन कर सकते थे। इसके अतिरिक्त, सूचना की उपलब्धता ने नागरिकों को और अधिक पारदर्शिता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

**चित्र 1:**

शिक्षा क्षेत्र में, वर्तमान में, सभी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही कैसे तय की जाती है



स्रोत: जीईएम रिपोर्ट

कुछ उच्च आय वाले देशों में ऐसी जवाबदेही नीतियों को अपनाया गया है, जो कार्य निष्पादन को आंकने और मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों के परीक्षा अंकों का इस्तेमाल करती हैं। विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। यह अध्यापकों के कार्य-निष्पादन और स्कूल की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए भी एक आधार के रूप में कार्य करता है।

किंतु, यदि जवाबदेही से ही अधिक समग्र, एक-समान और उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रणालियां सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, तो लचीले दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी, जो उपलब्ध सूचना का तर्कसंगत उपयोग कर सकेंगे। जवाबदेही प्रणाली, कुछ संदर्भों और शिक्षा के कुछ पहलुओं, में प्रभावी हो सकती है, तथा कुछ में और अन्यो के लिए अहितकर हो सकती है।

शिक्षा प्रणालियों में सुधार करने के लिए जवाबदेही का अत्यधिक महत्व है, परन्तु कुछ अनुमानों पर विचार किए जाने की जरूरत है। जवाबदेही के लिए जवाबदेही का राग अलापना गुमराह करना है। जवाबदेही को इस अंतिम उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए कि - यह एसडीजी4 लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन हो - न कि स्वयं शिक्षा प्रणाली में कोई एक लक्ष्य।

2017/8 की जीईएम रिपोर्ट में प्रायः एक-दूसरे पर निर्भर ऐसी प्रणालियों की विश्व स्तर पर समीक्षा की गई है, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है, इनके लागू होने पर एसडीजी4 के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तथा कार्यकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।

## जवाबदेह सरकारें

अंत में, सरकारें ही वैश्विक शिक्षा लक्ष्यों संबंधी प्रगति के लिए उत्तरदायी होती हैं। गरीब और अमीर देशों में सरकारों को समान तौर पर शिक्षा प्रतिबद्धताओं, योजनाओं, कार्यान्वयन और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

### सरकारों का शिक्षा के प्रति कानूनी उत्तदायित्व है

सभी देशों ने शिक्षा के अधिकार के मुद्दे का समाधान करने के लिए कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कानूनी तौर पर बाध्यकारी संधि का समर्थन किया है। सरकारों की इस अधिकार का सम्मान करने, संरक्षण करने और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी है। वर्तमान में, 82 प्रतिशत राष्ट्रों ने शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया है। केवल आधे से थोड़े अधिक देशों में, यह अधिकार न्यायोचित है, जहां नागरिकों को इसके उल्लंघन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया गया है। (चित्र 2)

### अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सरकार की जवाबदेही के विविध प्रभावों को दिरवाया गया है

जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा संबंधी सात मुख्य मानवाधिकार संधियों में से किसी एक की भी पुष्टि की है, उन्हें अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की समय-समय पर रिपोर्ट भेजनी होती है। सात मुख्य संधियों में से एक निःशक्तजन अधिकारों संबंधी यूएन समझौता (सीआरपीडी) है, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर समग्र प्रणाली के विकास का आह्वान किया गया है। इसमें निःशक्तजनों की शिक्षा के लिए अधिकार - आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है, और सरकार की जवाबदेही के लिए ठोस आधार प्रदान किया गया है। सीआरपीडी ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी प्रणालियों के गठन का प्रावधान किया है। राष्ट्रों को आंकड़े एकत्रित करके अपनी जानकारी संयुक्त राष्ट्र निःशक्तजन अधिकार समिति को भेजनी चाहिए।

जबकि 86 में से ज्यादातर राष्ट्रों ने आज की तारीख तक भेजी गई अपनी रिपोर्ट में निःशक्तजनों के शिक्षा के अधिकार का विशिष्ट तौर पर उल्लेख करते हुए कानूनों अथवा नीतियों का उल्लेख किया है, जबकि कुछ राष्ट्रों ने निःशक्तता को परिभाषित भी किया है। इसकी कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा न होने के कारण, कोई कार्यक्रम तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना मुश्किल होता है। इसी प्रकार, 42 राष्ट्रों के सविधानों, कानूनों अथवा नीतियों में समग्र शिक्षा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नियमित स्कूलों में समग्र कार्यक्रमों का समर्थन करते हुए विशेष स्कूलों की प्रवृत्ति को समाप्त करने का सुझाव दिया है। हालांकि, नीति हमेशा व्यवहारिकता के अनुरूप नहीं होती।

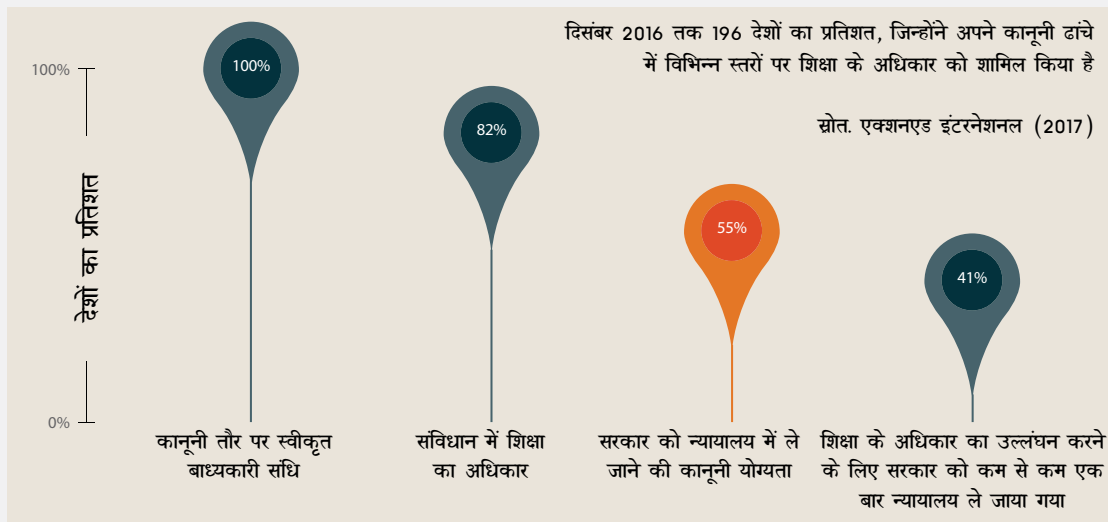
गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समानांतर रिपोर्टिंग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि समितियों के निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, फिलीपीन्स में कम वित्त पोषित सरकारी शिक्षा और अनियंत्रित गैर-सरकारी स्कूलों की समानांतर रिपोर्टिंग को समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है।

“ जवाबदेही को इस अंतिम उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए कि - यह एसडीजी4 लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन हो - न कि स्वयं शिक्षा प्रणाली में कोई एक लक्ष्य ”



**चित्र 2:**

नागरिकों को शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने पर अपनी सरकारों को न्यायालय में ले जाने का अधिकार होना चाहिए।



राष्ट्र एसडीजी के संबंध में हुई प्रगति को भी रिपोर्ट में दर्शाते हैं, हालांकि यह रिपोर्टिंग स्वेच्छा पर आधारित होती है। आज की तारीख तक, 44 राष्ट्रों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 'लोगों को सशक्त करना और समग्रता सुनिश्चित करना' विषय पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक विषयक समीक्षा, 2019 में एसडीजी4 की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। बदलाव लाने में स्वैच्छिक राष्ट्र-आधारित दृष्टिकोण के असर को अभी देखा जाना है; बाहरी प्रभावशाली प्रणालियां न होने से इसकी प्रगति में विलम्ब हो सकता है।

“ 86 देशों में से 42 देशों के सविधानों, कानूनों या नीतियों में संपूर्ण शिक्षा के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है ”

## नागरिक राजनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकारों पर उनके वायदों को पूरा करने का दबाव बना सकते हैं

राजनैतिक प्रक्रिया अधिकारियों को लोगों की मांग के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। 1975 और 2011 के बीच 169 देशों ने राष्ट्रीय नेताओं के हुए 890 चुनावों में से 469 चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है। यह प्रतिशत 1975-85 में 70 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2001-2011 में 45 प्रतिशत तक पहुंच गया, आंशिक तौर पर ऐसा “नए” लोकतंत्रों में चुनाव होने के कारण हुआ है (चित्र 3)।

लोकतंत्र और खुले समाज की तरफ झुकाव के कारण सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय बढ़ता है। फिर भी, मतदाताओं के लिए विफल अथवा निष्प्रभावी शिक्षा नीति के लिए चुने हुए पदों पर लोगों की पहचान करना और उनको जिम्मेदार ठहराना मुश्किल होता है। साधारण चुनावी वायदे और निवेश शिक्षा के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटका सकते हैं। सरकारें कम मूर्त शिक्षा इनपुट्स जैसे व्यवसायिक विकास की बजाय प्रत्यक्ष शिक्षा ढांचे पर ध्यान देते हुए कार्य करने की इच्छुक रहती हैं।

कुछ लोगों का तर्क है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्तरदायी कार्य को प्रोत्साहित करती है, परन्तु इसके मिले-जुले प्रमाण मिले हैं। ब्राजील में पुनः चुनाव का सामना करने वाले मेयर्स ने सीमित अवधि कार्यकाल वाले मेयर्स की तुलना में 27% कम संसाधनों का दुरुपयोग किया। इसके विपरीत, कोरिया गणराज्य में अधीक्षकों के प्रत्यक्ष चुनाव के कारण शिक्षा व्यय अथवा कार्य पूरा करने की दर या नामांकन में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं किया गया।

## नागरिक सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं

चुनाव एकमात्र राजनैतिक प्रणाली नहीं है जो सरकार को जवाबदेह बनाती है। नागरिकों की सक्रियता भी सरकार पर दबाव बना सकती है, जैसा कि चिली और दक्षिण अफ्रीका में विश्वविद्यालय शुल्क कम करने के लिए विद्यार्थियों के सफल आंदोलनों के मामले में हुआ था।

## चित्र 3:

यदि सरकारें अपने वायदों को पूरा नहीं करती हैं तो प्रायः उन्हें मताधिकार से हटाना सम्भव नहीं होता

### 1975 और 2011 के बीच राष्ट्रीय नेताओं के लिए नि:शुल्क और निष्पक्ष चुनाव का क्षेत्रीय प्रतिशत

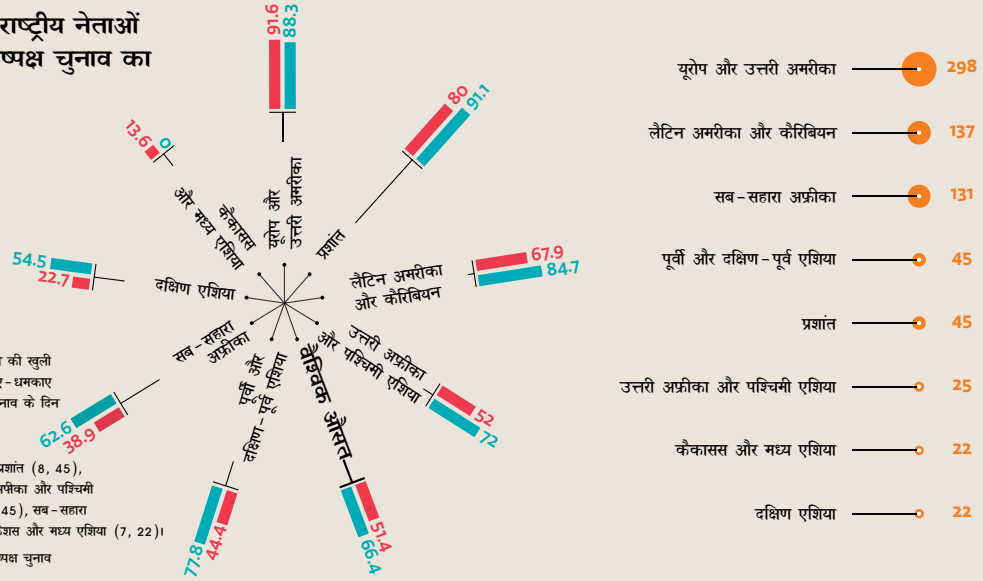
- निष्पक्ष चुनाव (%)
- नि:शुल्क चुनाव (%)
- चुनावों की कुल संख्या

टिप्पणी: स्पष्ट रूप से स्वतंत्र चुनाव हुए और भाग लेने की खुली प्रक्रिया से चुनाव हुए। निष्पक्ष चुनाव मतदाता को डर-धमकाए बिना हुए, उन्होंने स्वतंत्र रूप से मतदान किया और चुनाव के दिन

मतपत्रों की सही गणना हुई। क्षेत्रीय नमूना आकार:

यूरोप और उत्तरी अमेरिका (42 देश, 298 चुनाव), प्रशांत (8, 45), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (29, 137), उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया (8, 25), पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया (11, 45), सब-सहारा अफ्रीका (40, 131), दक्षिणी एशिया (9, 22), काकेशस और मध्य एशिया (7, 22)।

स्रोत: विश्व और डोएफ्लर (2016, नि:शुल्क और निष्पक्ष चुनाव डेटाबेस (सीएसईई, एन.डी.)।



सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) ने कानूनी प्रणालियों, सर्वेक्षण और अन्य अनुसंधान, सार्वजनिक आंकड़ों, गठबंधन निर्माण और मीडिया अभियानों सहित कई प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग किया। अर्जेंटीना के समानता और न्याय के सिविल संघ बाल्यकाल शिक्षा के संबंध में सूचना प्रदान न करने पर ब्लूनस आयरस सिटी सरकार को न्यायालय में ले गई थी।

सर्वेक्षणों में ऐसी सूचना एकत्रित की जाती है, जो नीतियों में कमियों को दर्शाते हुए बदलाव का समर्थन करती हैं। केन्या, पाकिस्तान और सेनेगल सहित कई राष्ट्रों में नागरिकों द्वारा बच्चों की बुनियादी पढ़ने और गणितीय क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों का शिक्षा प्रदानगी में सुधार लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किया गया है।

सीएसओ गठबंधन, जैसे बांग्लादेश में लोकप्रिय शिक्षा अभियान ने सरकार पर शिक्षा के लिए संसाधन बढ़ाने के लिए दबाव बनाने में कारगर भूमिका निभाई। नागरिक रिपोर्ट कार्ड, जिसका पहली बार 1994 में बंगलोर में प्रयोग किया गया था, को रवांडा सहित और जगह भी अपनाया गया है।

भारत और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहित कुछ देशों में, सीएसओ ने सरकार द्वारा वितरित धनराशि और व्यय की निगरानी के लिए बजट की निगरानी और विश्लेषण द्वारा भ्रष्ट प्रक्रियाओं से निपटने और यह आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि क्या संसाधनों का आबंटन और व्यय बजट और योजनाओं के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं।

दिव्यांगजन संगठन सरकार पर बदलाव लाने के लिए दबाव बना सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन और स्वतंत्र मानवाधिकार संस्थाएं सूचना प्रदान करके जागरूकता पैदा कर सकती हैं। दिव्यांगजन संगठनों ने 86 रिपोर्टिंग देशों में से 50 देशों में सीआरपीडी कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता की है, लेकिन केवल 29 देशों में ही राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लिया। क्षमता की कमी भागीदारी में एक बाधा है।

“  
दिव्यांगजन संगठनों ने 86 रिपोर्टिंग देशों में से 50 देशों में सीआरपीडी के कार्यान्वयन की निगरानी में भाग लिया है  
”

शिक्षक संघ व्यापक सिविल सोसायटी का एक हिस्सा हैं, लेकिन उनकी विशिष्ट आवाज और भूमिका होती है। वे शिक्षा सुधारों का समर्थन करके अथवा विरोध जताकर, और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संवाद करके सरकार को जवाबदेह बनाने में सहायता कर सकते हैं, जिन पर सरकार बोलने में हिचकती है। नीति-निर्माण में संघों को औपचारिक तौर पर शामिल करके जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है और संघ-सरकार के बीच संबंधों को सुधारते हुए अध्यापकों को इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघों में सुधारों पर नियमित परामर्श

नहीं किया जाता है। 50 से अधिक देशों में 70 संघों में से, 60 प्रतिशत संघों से शिक्षण सामग्रियों के चयन और विकास के संबंध में कभी भी परामर्श नहीं किया गया अथवा बहुत ही कम किया गया।

## महत्वपूर्ण शिक्षा मुद्दे उठाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है

सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए नागरिकों के पास वैध सूचना होनी चाहिए। मीडिया सरकार के कार्य- निष्पादन का मूल्यांकन करने में नागरिकों की सहायता करते हुए सरकार के निगरानीकर्ता के तौर पर कार्य कर सकता है। यह सीएसओ के कार्यों के प्रचार-प्रसार के एक चैनल के तौर पर कार्य करने के साथ ही समानता जैसे मुद्दों को लोगों के एजेंडा में शामिल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया ने सभी बच्चों के लिए बुनियादी कौशल सुनिश्चित करने की चुनौती को दर्शाने के लिए नागरिक-आधारित मूल्यांकनों के परिणामों को प्रकाशित किया है।

मीडिया विचारकों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों के निष्कर्षों की जानकारी भी प्रदान करता है। सार्वजनिक निधियों को व्यय करने के तरीकों के बारे में व्यापक मीडिया सूचना नागरिकों को सशक्त करने और शिक्षा अधिकारियों द्वारा उत्तरदायी ढंग से कार्य करने के लिए दबाव बनाने में सहायता कर सकती है। युगांडा में अखबार केन्द्र की दूरी में 2.2 किलोमीटर की कमी ने स्कूल में पहुंचने वाली निधियों में लगभग 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की।

जबकि परम्परागत मीडिया अभी भी लोगों को जटिल मुद्दों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सोशल मीडिया पाठकों को सूचना को सम्पादन के बिना, पत्रकारों द्वारा कांट-छांट किए बिना अथवा कुछ मामलों में सरकार की सेंसरशिप के बिना व्यापक स्तर पर साझा करने में सहायता करता है। शिक्षा नीतियों में प्रायः तेजी से किए जा रहे बदलाव को देखते हुए सोशल मीडिया द्वारा पूरे किए जाने वाले कार्य महत्वपूर्ण हैं।

फिर भी मीडिया को स्वतंत्र, जवाबदेह और संगत सूचना प्रदान करने और विविध सामाजिक विचारों को दर्शाने वाला होना चाहिए। अनुसंधान, विश्लेषण, आयोजन और लेखन या समाचार प्रसारण कार्यों में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल मीडिया कर्मियों के पास शिक्षा मुद्दों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता होनी चाहिए और वह विश्वसनीय होनी चाहिए।

## उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण वाली विश्वसनीय शिक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण साधन हैं

सरकारों के सत्तासीन होने के बाद, उनके शिक्षा योजना दस्तावेजों में सरकारी प्रतिबद्धताओं को शामिल करके और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए जवाबदेही तय की जाती है। सरकारें प्रायः शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुवर्षीय रणनीतिक योजनाएं बनाती हैं लेकिन योजना एवं समन्वय के लिए वार्षिक तौर पर परिचलित की जाने वाली योजनाएं महत्वपूर्ण हैं।

सभी हितधारकों को और अधिक औपचारिक शक्तियां प्रदान करने वाली सांस्थानिक प्रक्रियाएं जवाबदेही को सुदृढ़ कर सकती हैं। इस क्षेत्र की योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों की एक संयुक्त संचालन समिति की सिफारिश की गई है। हालांकि, जहां क्षमता एक चुनौती हो, वहां हितधारक हर बार सभी घटकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

“ जो सरकारें योजनाओं के मसौदा को तैयार करने की जल्दी में विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं अथवा दानदाताओं को कार्य सौंप देती हैं वे स्थानीय स्वामित्व और प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज़ करने का जोखिम उठाती हैं ”

यह सही है कि सहभागितापूर्ण शिक्षा योजना में काफी समय लग सकता है। सरकारें व्यापक परामर्श किए बिना योजनाओं का मसौदा शीघ्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं अथवा दानदाताओं को कार्य सौंपने की ओर आकर्षित हो सकती हैं। ऐसी जल्दबाजी स्थानीय स्वामित्व और प्रतिबद्धता को कम कर सकती है। सहायता प्राप्त करने वाले देशों को योजनाओं पर दानदाताओं के एकाधिकार से बचने का ध्यान रखना चाहिए।

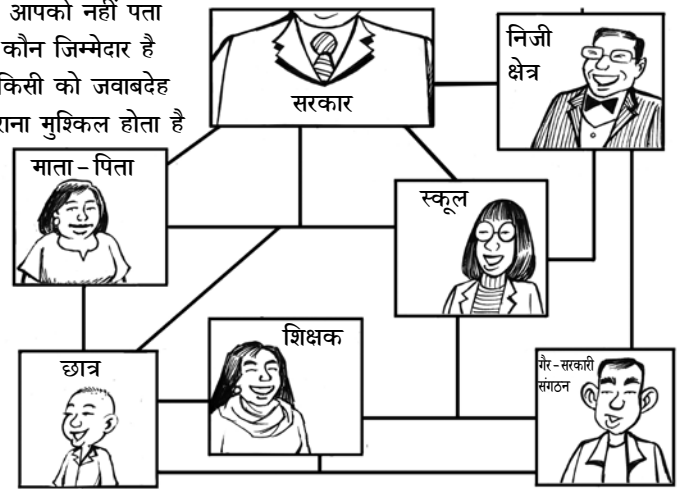
स्पष्ट तौर पर उल्लिखित उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष तौर पर विकेन्द्रीकृत प्रणालियां, जहां उत्तरदायित्व प्रायः परिभाषित नहीं होते, उनमें दोहरापन होता है तथा जवाबदेही की सीमाएं स्पष्ट नहीं होतीं।

विकेन्द्रीकृत प्रशासन, खासकर निम्न आय वाले और कमजोर देशों में, रणनीतिक योजना के लिए प्रायः क्षमता का अभाव होता है।

स्थानीय शासन की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्य-निष्पादन आधारित सशर्त अनुदानों का प्रयोग किए जाने से कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वित्तीय प्रबंधन में सुधार हुआ है। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में, अनुदान पात्रता की न्यूनतम शर्तों को पूरा करने वाले प्राधिकरणों की संख्या तीन वर्षों में 50 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच गई।

परंतु, केन्द्रीय तौर पर निर्धारित परिणामों के लिए सख्त स्थानीय जवाबदेही का निर्देश दिए जाने के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। व्यापक लेखा-परीक्षा की संस्कृति उत्तरदायित्वों में बाधा डाल सकती है, सहयोग को कम कर सकती है, नई खोज को हतोत्साहित कर सकती है और सेवा प्रदाताओं को सुधारों की बजाय लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

यदि आपको नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है तो किसी को जवाबदेह ठहराना मुश्किल होता है



## बजट निर्माण के दौरान ज्यादा निगरानी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निधियों का आबंटन सुनिश्चित कर सकती है

हितधारकों को बजट निर्माण और योजनागत व्यय की समीक्षा प्रक्रिया में शामिल करने का अधिकार प्रदान करने से संसाधन आबंटन में समानता की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

बजट जांच विधान-मंडलों का मुख्य कार्य है, जिसके लिए समय और विशेषज्ञ इनपुट की आवश्यकता होती है। सीएसओ प्रस्तावित बजटों का मूल्यांकन करने और विचार-विमर्श की जानकारी प्रदान करने में उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसाकि इंडोनेशिया और केन्या में किया गया है। पवित्रबद्ध मद-वार बजट की बजाय कार्यक्रम आधारित बजट कानून निर्माताओं को व्यय का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में सहायता कर सकते हैं।

## समस्तरीय जवाबदेही अधिक प्रभावी हो सकती है

विधायी समितियां, लोकपाल कार्यालय और न्यायालय ऐसे समस्तरीय जवाबदेही साधनों के उदाहरण हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कार्यकारी शक्तियों के विस्तार को चुनौती देते हैं। आंतरिक और बाह्य लेखा-परीक्षाएं प्रभावी बजट कार्यान्वयन जवाबदेही साधन हैं और ये समय की बर्बादी, गलत आवंटन और भ्रष्टाचार को कम करते हैं। हालांकि, इसके लिए पर्याप्त क्षमता की आवश्यकता होती है।

“

न्यूजीलैंड, नार्वे, पेरू, अमेरिका और जाबिया के विधानमंडलों में स्थायी शिक्षा समितियां हैं, जो सरकार के कार्यों की समीक्षा करती हैं, कानूनों की समीक्षा करती हैं और बदलाव की सिफारिश करती हैं

”

विधायी समितियां महत्वपूर्ण निगरानी कार्य करती हैं। स्वतंत्रता, क्षमता अथवा प्राधिकार की कमी बदलाव लाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है, परंतु विशिष्ट शिक्षा विशेषज्ञता के साथ कानून-निर्माताओं के बीच विचार-विमर्श कम विभाजन वाले मुद्दों पर नीतिगत प्रस्तावों में सुधार कर सकता है। न्यूजीलैंड, नार्वे, पेरू, अमेरिका और जाबिया के विधानमंडलों में स्थायी शिक्षा समितियां हैं, जो सरकार के कार्यों की समीक्षा करती हैं, कानूनों की समीक्षा करती हैं और बदलाव की सिफारिश करती हैं। यूनाइटेड किंगडम में समिति की सिफारिशें 86 में से 20 मामलों में, विशेष तौर पर निरीक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कानून बनाने के लिए, सरकार के नीतिगत उपायों के समान ही अथवा उनके जैसी ही थीं।

लोकपाल कार्यालय सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के इच्छुक नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करता है। वे उस समय विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जब नागरिक सरकार के अधिकारियों के समक्ष अपनी बात कहने में असहज स्थिति का सामना करते हैं। वर्ष 2010 में, 118 देशों में लोकपाल था। लोकपाल कार्यालय प्रायः राजनैतिक तौर पर विवादास्पद ऐसे मुद्दों को देखता है, जो सरकार के साथ इसके टकराव को बढ़ा सकते हैं। लेटिन अमेरिका में, लोकपाल की नियुक्ति, संवैधानिक अधिकारों के बिना भी, ने 1982 से 2011 के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुलभता बढ़ाने में सहायता की। इंडोनेशिया में, लोकपाल कार्यालय ने विद्यार्थियों को बेचे जा रहे प्रश्नों और मोबाइल फोन पर उत्तर साझा किए जाने संबंधी जालसाजी का पर्दाफाश किया।

सीएसओ और नागरिक बाह्य लेखा-परीक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं। चिली और कोरिया गणराज्य में नागरिकों की ऑनलाइन शिकायतों और सुझावों में लेखा-परीक्षकों द्वारा ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक व्यय निगरानी सर्वेक्षण, सीएसओ को व्यय की सामाजिक लेखा-परीक्षा करवाने में सहायता करते हैं। हालांकि, ये कभी-कभार होने वाले और दान-दाताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी और स्थायी परिवर्तन बहुत कम होते हैं।

## भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत संस्कृति का निर्माण करना महत्वपूर्ण है

भ्रष्टाचार वित्त और सेवा प्राप्ति से लेकर संस्थागत मान्यता तक, अध्यापक प्रबंधन, परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों, अनुसंधान और पाठ्य-पुस्तकों सहित शिक्षा प्रावधानों के सभी पहलुओं में हो सकता है। चाहे यह सुर्खियां बटोरने के लिए धन का दुरुपयोग हो अथवा आरोपित कोई निम्न स्तरीय प्रक्रिया हो, इसकी प्रतिक्रिया धन के नुकसान से कहीं अधिक होती है और ये शिक्षा की उपलब्धता और सेवा गुणवत्ता को प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार सरकार के संसाधन आबंटन निर्णयों को पक्षपाती बनाता है, उत्पादकता को कम करता है और सरकारी राजस्व में कमी लाता है।

हालांकि केन्द्र सरकार से स्थानीय सरकार और इसके बाद विद्यालयों को निधियों के अंतरण में चोरी संबंधी विश्व बैंक के अध्ययनों ने इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, किंतु सेवा स्थल पर निधियों की प्राप्ति की निगरानी करना एक चुनौती बना हुआ है, खासकर जब आवंटनों के लिए कोई स्पष्ट नियम न हों। 'नकली' अध्यापक और स्कूल एक पेचिदा और विवादास्पद विषय बना हुआ है। नाइजीरिया में वर्ष 2016 के पूर्वार्द्ध में 'नकली' अध्यापकों या अपने सरकारी वेतन से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापकों की 8,000 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

ब्राजील में शिक्षा समानता निधि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों के बाद, केन्द्रीय महानियंत्रक द्वारा 120 नगरपालिकाओं और 4 राज्यों में किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि 49 मामलों में नियम विरुद्ध बोली प्रक्रियाओं को अपनाया गया, 28 मामलों में नियम विरुद्ध अनुबंधों का कार्यान्वयन किया गया और 21 मामलों में खाते से 'नकदी निकाली' गई।

बेहद खराब प्रक्रियाओं का बाहरी निरीक्षक जायजा नहीं ले सकते और उनके पैमाने का सत्यापन करना मुश्किल होता है, उदाहरण के लिए, टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों को चुनौती देना। घोर प्रांत, अफगानिस्तान के 740 स्कूलों में से लगभग 80% स्कूल कार्य नहीं कर रहे थे, जबकि शिक्षा विभाग अध्यापकों को वेतन का भुगतान कर रहा था।

भ्रष्टाचार के कुछ मामले इतने अधिक गहरे होते हैं कि प्रायः वे पकड़ में नहीं आते। बांग्लादेश में सार्वजनिक व्यय निगरानी सर्वेक्षण में लगभग 40% जिला और उप-जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने व्यय की प्रतिपूर्ति का 'शीघ्र भुगतान' करने के लिए लेखा अधिकारियों को भुगतान किया। हालांकि इन भुगतानों में सरकारी खजाने से वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष चोरी शामिल नहीं होती, परंतु वे अधिकारियों को दूसरे तरीकों से लागत को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

अनियमितताओं को उजागर करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके साथ ठोस और स्वतंत्र लेखा-परीक्षा संस्थाओं, मुक्त सूचना प्रणालियों और मीडिया निगरानी के लिए अनुकूल माहौल और गैर-सरकारी संगठनों सहित उन्नत निगरानी प्रणालियों सहित कानूनी मानदंड और ढांचा होना आवश्यक है। जब भ्रष्टाचार के मामलों का पता चलता है, तो पुलिस और न्यायालय बाद की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## शिक्षा की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए

निगरानी और मूल्यांकन सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा दे सकते हैं। निगरानी को कारगर बनाने के लिए, निगरानी में वांछित परिणामों की जानकारी प्रदान करने के साथ ही डाटा सटीक होना चाहिए और इसे नियमित तौर पर जमा किया जाना चाहिए। हालांकि, निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियां प्रायः अलग-अलग होती हैं। एजेंसियों की कार्य पद्धति और डाटा संग्रह करने की अवधि

“

209 देशों में से 108 देशों ने वर्ष 2010 के बाद से कम से कम एक बार राष्ट्रीय शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का प्रकाशन किया है, परंतु पूरी दुनिया में 6 देशों में से लगभग 1 देश नियमित तौर पर ऐसा करता है

अलग-अलग होती है और डाटा का केन्द्रीय तौर पर संकलन नहीं किया जाता, यह तुलनात्मक अथवा सुलभ नहीं होता।

सूचना समेकित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि सरकारों के लिए विधान मंडलों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संगठनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा निगरानी रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य किया जाए तथा सरकारों को जवाबदेह बनाने में नागरिकों की सहायता करनी चाहिए। 209 देशों में से 108 देशों ने वर्ष 2010 के बाद से कम से कम एक बार राष्ट्रीय शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का प्रकाशन किया है, परंतु पूरी दुनिया में 6 देशों में से लगभग 1 देश नियमित तौर पर ऐसा करता है।

”

“

मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा निगरानी रिपोर्टों के अनुसार केवल एक-तिहाई में प्रौढ़ शिक्षा को शामिल किया गया है

”

राष्ट्रीय शिक्षा निगरानी रिपोर्ट अमीर देशों में ज्यादा सामान्य बात है परंतु मध्यम आय वाले देशों जैसे डोमिनिसिएन गणराज्य और मोलदोवा गणराज्य और कुछ निम्न आय वाले देश जैसे युगांडा भी रिपोर्ट तैयार करते हैं। लगभग सभी रिपोर्टों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को शामिल किया गया है। लगभग तीन-चौथाई रिपोर्ट में बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा को शामिल किया गया है, दो-तिहाई भाग में उच्चतर शिक्षा और एक-तिहाई रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा को शामिल किया गया है।

रिपोर्टों में अलग-अलग बातों पर बल दिया गया है। लगभग 60 प्रतिशत रिपोर्टों में मुख्य तौर पर की गई कार्रवाई और 25 प्रतिशत में स्थिति का मूल्यांकन करने, विभिन्न घरेलू संदर्भों सहित संबंधित जवाबदेही को दर्शाया गया है। रिपोर्टों में व्यय के लिए जवाबदेही पर भी ध्यान दिया गया है।

कुछ, जैसे जर्मनी की बिल्डुंग्सबेरिट (शिक्षा रिपोर्ट) आम लोगों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य है और इनमें सामान्य तौर पर कार्यों अथवा व्यय के लिए लेखा-विधि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। पनामा का शिक्षा मंत्रालय सार्वजनिक प्रबंधन में पारदर्शिता संबंधी कानून में उल्लिखित अनुसार एक वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। फिलीपींस में, बजट कानून का 'पारदर्शिता सील' प्रावधान 'पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही लागू करने के लिए' सभी राष्ट्रीय सरकार की एजेंसियों की सरकारी वेबसाइटों पर राष्ट्रीय बजट परिपत्र में दिए गए उपयुक्त निर्देशों के अनुसार गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों को डाला जाना अनिवार्य है।

कुछ निगरानी सूचना को बाहरी तौर पर किसी ऐसी एजेंसी द्वारा प्रमाणित अथवा तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है, जिनका कार्य मान्यता-प्राप्त हो और जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। पिछले दशक में, कोलम्बिया, इक्वाडोर एवं मेक्सिको सहित लेटिन अमेरिकी देशों में स्वायत्तशासी मूल्यांकन एजेंसियों की स्थापना की गई है और उनके उत्तरदायित्वों को प्रक्रिया अथवा नए कानूनी प्रावधानों द्वारा सुदृढ़ किया गया है। उन्हें उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए स्थायी वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सहायता प्राप्त करने वाले देशों में, वार्षिक संयुक्त क्षेत्र समीक्षा जो सरकार, दानदाताओं, सिविल सोसायटी और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाती है, एक आम बात है। हालांकि, उनकी अपनी कमजोरियां हैं क्योंकि उनकी सहभागिता व्यापक नहीं है, सिफारिश के लिए कार्यान्वयन योजनाओं का अभाव है और उनकी कार्यसूची प्रायः दानदाताओं द्वारा संचालित होती है।

## जवाबदेह विद्यालय

विद्यालय और अन्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाएं औपचारिक तौर पर सरकार के प्रति जवाबदेह हैं और अनौपचारिक तौर पर अभिभावकों और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेह हैं। कई देश निर्णय करने का अधिकार क्षेत्रीय और स्थानीय स्कूल प्राधिकारियों को सौंप देते हैं और इस प्रकार ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। जवाबदेही पर बल दिए जाने से विद्यालयों को कई प्रकार की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है।

### सरकारी नियंत्रण स्कूल की गुणवत्ता की निगरानी में सहायक होता है

शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण दुनिया भर में अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, जीईएम रिपोर्ट में समीक्षा की गई लगभग सभी 71 प्रणालियों में अध्यापक की योग्यता के विनियम थे, 40 प्रतिशत से कम में छात्र/अध्यापक अनुपात अधिकतम था (चित्र 4)। नियम शिक्षा प्रदाताओं को जवाबदेह बना सकते हैं, परंतु व्यावहारिक तौर पर ऐसा प्रभावी नहीं होता। गरीब देशों में, कई स्कूल मौजूदा नियमों का अनुपालन नहीं करते, क्योंकि वे उनके नियंत्रण नहीं होते। उदाहरण के लिए, कम निधियां प्रदान किए जाने का अर्थ है कि नियमों के बावजूद तजाकिस्तान में कई स्कूलों को सर्दियों में उपयुक्त तौर पर गर्म नहीं रखा जाता है।

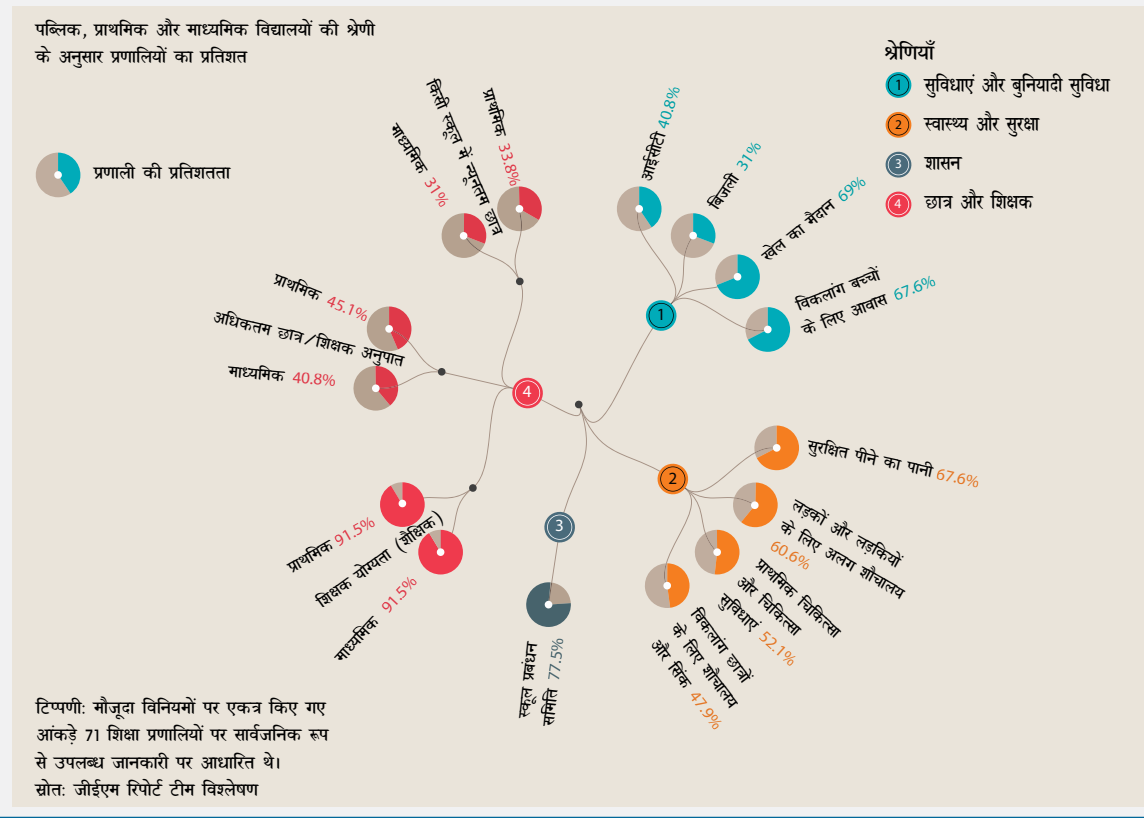
परम्परागत तौर पर स्कूल निरीक्षकों ने नियमों के अनुपालन की निगरानी की, जिसकी कार्यशीलता निरीक्षक के कौशल पर निर्भर करती है। कुछ अनुसंधानों से पता चलता है कि जिन प्रधानाचार्यों पर निरीक्षकों ने जवाबदेही का दबाव बनाया था, उन्होंने कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कार्य किया है।

### गरीब देशों में कई गैर-सरकारी विद्यालयों को विनियमित नहीं किया जाता है

गैर-सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है। 20 प्रतिशत से अधिक गैर-सरकारी क्षेत्र में दारखिला वाले देशों की संख्या में वर्ष 2005 और 2015 में वृद्धि हुई है (चित्र 5)। उप-सहारा अफ्रीकी और दक्षिणी एशिया के कुछ देशों में कई गैर-सरकारी विद्यालय विनियमित नहीं हैं, विशेष तौर पर गरीब जनसंख्या की सेवा करने वाले और कम शुल्क वसूलने वाले विद्यालय, जिनकी संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है कि सरकार के लिए उन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं है। कुछ विद्यालयों ने बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक विनियमों से बचने के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है। समानता में सुधार करने के लिए गैर-सरकारी विद्यालयों के विनियमन हेतु संगठित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

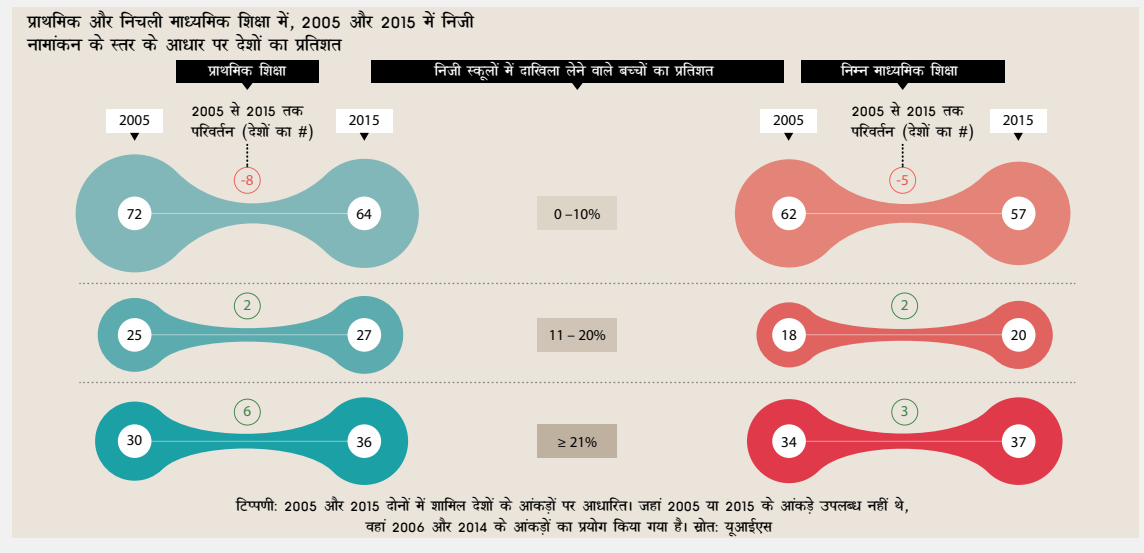
चित्र 4:

शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण दुनिया भर में अलग-अलग है



चित्र 5:

प्राथमिक और निम्न माध्यमिक शिक्षा में गैर-सरकारी क्षेत्र के दाखिलों में वृद्धि हुई है





प्रायः स्कूल के निरीक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

कमजोर विनियामक परिवेश उस समय समस्या बन जाते हैं, जब शक्तिशाली गैर-सरकारी श्रृंखला का तेजी से विस्तार होता है। ब्रिज इंटरनेशनल अकादमी 5 देशों में 500 से अधिक विद्यालयों का संचालन करती है। केन्या और युगांडा में निरीक्षण के दौरान अदक्ष अध्यापकों, अपर्याप्त अवसंरचना और अनधिकृत पाठ्यक्रमों की जानकारी मिली है तथा न्यायालयों ने मंत्री द्वारा कुछ विद्यालयों को बंद करने के कदम का समर्थन किया है।

## शिक्षा गुणवत्ता पर निरीक्षण का स्वागत किया जाता है किंतु इसे लागू किया जाना मुश्किल है

विशेष तौर पर अमीर देशों में यह प्रचलन बढ़ रहा है कि निरीक्षण का उद्देश्य विनियामक मानकों का अनुपालन न होकर विद्यालयों में होने वाले शिक्षण और पढ़ाई की

गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। हालांकि, इस सहायक कार्य को भली-भांति पूरा करना मुश्किल है। गरीब देशों में निरीक्षण प्रणाली को संसाधन और क्षमता सीमाओं का सामना करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में निरीक्षकों ने निरीक्षण सुधारों का विरोध किया, जो आंशिक तौर पर रंगभेद नीति निरीक्षणों की स्मृति के कारण था। कई संदर्भों में, निरीक्षण में सुधार करने में समय लगता है। वर्ष 2015 तक, अंगोला में केवल 45 प्रतिशत निरीक्षकों को 2010 में प्रारंभ हुए सुधारों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

## बाल्यकाल शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन का अभिप्राय आसानी से दिरवाई देने वाले पहलू होता है

बच्चों के समग्र विकास में बाल्यकाल शिक्षा के महत्व के बावजूद, वर्ष 2010 और 2015 के बीच बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए विश्व बैंक के प्रणालीगत दृष्टिकोण से पता चलता है कि 34 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से केवल 14 देशों ने बाल्यकाल शिक्षा मानकों और अनुपालन निगरानी प्रणालियों की स्थापना की थी।

गुणवत्ता आश्वासन में देश प्रायः आसानी से मापने योग्य और दिरवाई देने वाली प्रचलन संबंधी विशेषताओं जैसे आधारभूत ढांचा और छात्र/ अध्यापक अनुपात का ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी, देश प्रायः सुव्यवस्थित तौर पर निगरानी अनुपालन के लिए संघर्षशील रहते हैं, जैसाकि बेलीज, इंडोनेशिया, नेपाल और स्वीजरलैंड के उदाहरणों से पता चलता है।

अन्य प्रणालियों में शिक्षण के और अधिक सूक्ष्म पहलुओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। चिली में, सभी नगरपालिका विद्यालयों के शिक्षकों का प्रत्येक चार वर्ष में एक बार बेहतर शिक्षण संरचना मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वः मूल्यांकन, बाह्य निरीक्षण, समकक्ष व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाना और एक पोर्टफोलियो शामिल होता है। जिन अध्यापकों का कार्य 'असंतोषजनक' पाया जाता है, उनका आगामी वर्ष में पुनः मूल्यांकन किया जाता है और यदि इसमें कोई प्रगति नहीं पाई जाती है तो उन्हें शिक्षण कार्य करने से रोक दिया जाता है।

कुछ उपकरण जैसे बाल्यकाल पर्यावरण रेटिंग स्केल अध्यापकों और बच्चों के बीच संवाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। अमेरिका में विकसित और व्यापक तौर पर उपयोग लाई जाने वाली इस स्केल का उपयोग जर्मनी और इटली सहित अन्य उच्च आय वाले देशों में भी किया जाता है।

बाल्यकाल विकास के प्रत्यक्ष उपाय गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में सहायक हो सकते हैं। स्काटलैंड में आद्योपांत अध्ययन का उद्देश्य तीन समूहों में 14,000 बच्चों के बीच प्रारंभिक दौर के अनुभवों को बाद के परिणामों के साथ जोड़ना है, जिसके परिणामों का उपयोग बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा नीति की रूपरेखा पुनः बनाते समय किया जाएगा।

सामुदायिक योगदान, विशेष तौर पर अभिभावकों का योगदान, बाल्यकाल देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस में, राष्ट्रीय परिवार आबंटन कोष अभिभावक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर एक नियमित बैरोमीटर तैयार करता है, और चयनित अभिभावक प्रतिनिधि सामान्य परिषद के बाल्यकाल आयोग को जानकारी प्रदान करता है।

“ 34 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से केवल 14 देशों ने बाल्यकाल शिक्षा मानकों और अनुपालन निगरानी प्रणालियों की स्थापना की थी ”



## उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया विविध उद्देश्यों को दर्शाती है

देशों के कानूनी ढांचों में उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए एकल अथवा बहु राष्ट्रीय एजेंसियों को उत्तरदायी बनाया गया है, हालांकि कई निम्न आय वाले देशों ने अभी राष्ट्रीय प्रणालियों की स्थापना नहीं की है। क्षेत्रीय प्रबंध जैसे लिस्बन सम्मेलन ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों के विकास का प्रसार किया है, जिसमें देश क्षेत्रीय मानकों को राष्ट्रीय कानून में शामिल कर रहे हैं।

गुणवत्ता आश्वासन मूल्यांकन में मानक स्थापित करना, संस्थागत तौर पर स्व: मूल्यांकन, बाहरी विशेषज्ञ और समकक्ष समूह, मूल्यांकन रिपोर्टें और अपील करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। मानकों में, चाहे निर्देशात्मक हों अथवा परामर्शी, उच्चतर शिक्षा के इनपुट्स, कार्यकलाप और परिणाम शामिल हैं। चीन के अवर स्नातक शिक्षा मानकों के गुणवत्ता मूल्यांकन में 8 मुख्य क्षेत्रों के 19 संकेतकों को शामिल किया गया है: विश्वविद्यालय मिशन, शिक्षण स्टाफ, सुविधाएं, अकादमिक पाठ्यक्रम, प्रबंधन, माहौल, शिक्षण रूपरेखा और मुख्य कार्यक्रम।

गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां वार्षिक रिपोर्टों, डाटाबेस, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रजिस्ट्रों और राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों के माध्यम से स्वयं को उत्तरदायी बनाती हैं। उच्चतर शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी नेटवर्क जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की एक पुस्तिका प्रकाशित करता है : कोस्टा रिका से यूनाईटेड अरब अमीरात तक 18 सदस्यों ने अपने दिशा-निर्देशों को श्रेष्ठ प्रक्रियाओं से संबद्ध किया है। हालांकि, जवाबदेही रिपोर्टों में ज्यादातर सूचनाओं का उच्चतर शिक्षा विशेषज्ञों के अतिरिक्त व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता है।

राष्ट्रों की सीमा के पार उच्चतर शिक्षा को समाहित करने वाले विनियामक ढांचों में मुख्य ध्यान संस्थाओं की सहायता करना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को प्रायः अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और उनके लिए सूचना प्राप्त करना मुश्किल होता है। राष्ट्रों को अप्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं की पहचान करने और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के कार्य को वरीयता प्रदान करनी चाहिए और विद्यार्थी निकायों को बेहतर गुणवत्ता प्रदाताओं के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

कई छात्रवृत्ति कार्यक्रम व्यय किए गए संसाधनों के लिए नियमित तौर पर दानदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं परंतु यदि वे विद्यार्थियों, अभिभावकों और विश्वविद्यालयों को समय पर सूचना भी प्रदान करें तो उनकी रिपोर्टें अधिक लाभदायक होंगी। कार्यक्रम का प्रभाव मापने के लिए 'आद्योपांत' अध्ययन और विश्वविद्यालयों तथा पूर्व विद्यार्थियों की फीडबैक प्राप्त करना उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, यूनाईटेड किंगडम में राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति आयोग पुरस्कार धारकों का सर्वेक्षण करता है और इनके परिणामों का उपयोग भावी कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सूचना देने के तौर पर करता है।

## सस्ती उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए

उच्चतर शिक्षा में नामांकन निरंतर बढ़ रहा है, जो विद्यार्थियों की अच्छी प्रगति दर और अंशकालिक विद्यार्थियों की संख्या के बढ़ने के कारण संभव हुआ है।

सरकारें उच्चतर शिक्षा में समानता और वहनीयता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विधायी संरचनाओं का प्रयोग करती हैं, परंतु कुछ राष्ट्र वैश्विक उपलब्धता की गारंटी देते हैं। ऐसा करने वाले देशों में इक्वाडोर, ग्रीस और ट्यूनिशिया शामिल हैं। ब्राजील और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सहित उच्चतर शिक्षा की गारंटी देने वाले कई कानूनों में भेदभाव को निषेध करती हैं और अल्पसंख्यकों तथा उपेक्षित और वंचित समूहों के लिए शिक्षा उपलब्धता को प्रोत्साहित करती हैं।

जैसा कि उच्चतर शिक्षा की मांग में वृद्धि हुई है, सरकारों ने लागत का कुछ भार या तो ट्यूशन शुल्क बढ़ाकर अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रावधान को प्रोत्साहित करते हुए लोगों पर डाला है। हालांकि, जहां कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वहां इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है। अतिरिक्त सहायता के बिना, शिक्षा की निःशुल्क वैश्विक उपलब्धता अमीर लोगों को राजसहायता प्रदान करने का माध्यम बन सकती है। उदाहरण के लिए, फिलीपींस ने वर्ष 2016 में सरकारी महाविद्यालयों में शुल्क समाप्त कर दिया, परंतु इनमें पहले ही समृद्ध पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चे आ रहे थे।

६६

ट्यूशन शुल्क को वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें अनुदान, ऋण और कर लाभ शामिल हैं

ट्यूशन शुल्क को वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें अनुदान, ऋण और कर लाभ शामिल हैं। निम्न आय वाले विद्यार्थियों के लिए ऋण चुकौती सहायता उनकी उपलब्धता के विकल्प को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। निम्न आय वाली जनसंख्या को लक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है, परंतु घरेलू वित्तीय स्थिति को मापने के लिए कम विश्वसनीय उपाय वाले देशों में यह कार्य मुश्किल हो सकता है, जैसाकि कई निम्न आय वाले देशों में हुआ है।

## कौशल प्रदाता और प्रमाणकर्ता प्रशिक्षार्थियों तथा नियोक्ताओं के प्रति जवाबदेह हैं

व्यावसायिक कौशल विकास के लिए बेहतर गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली प्राधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को लाभार्थियों के प्रति जवाबदेह बनाती है, जैसे कि कामगार एवं नियोक्ता, जो एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाती हैं।

लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली कौशल विकास योग्यता प्रणालियों के संयुक्त ढांचे का शासन के साथ सामंजस्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। श्रम बाजार की मांग और सेवा प्रदाता एवं आपूर्तिकर्ताओं को आपस में जोड़ने का एक तरीका ढांचों को विकसित करते समय नियोक्ताओं और सामाजिक भागीदारों को इसमें शामिल करना है, हालांकि यह हमेशा आसान नहीं होता, जैसे कि पोलैंड और ट्यूनिशिया में।

गैर-सरकारी प्रशिक्षण प्रदाताओं की बढ़ती हुई संख्या को मान्यता देने और संचालित किए जाने वाले विनियामक मानकों तथा प्रक्रिया-विधियों का अनुपालन किया जाना चाहिए। जैसाकि उच्चतर शिक्षा के मामले में होता है, मान्यता देना एक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है, जिसमें प्रायः बाहरी सरकार अथवा व्यावसायिक प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सेवा प्रदाताओं ने मानकों को पूरा किया है।

वर्ष 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ भारत के महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणन पारदर्शी हो, प्रशिक्षार्थियों को पूरा लाभ मिले, पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा एक विशिष्ट पहचान संख्या का प्रयोग किया जाए और गैर-प्रत्यायित सेवा प्रदाताओं को कोई अवैध उप-ठेका न दिया जाए। सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थियों को उन्हें रोजगार प्रदान करने और शुल्क का वापस भुगतान करने संबंधी झूठे वायदों से बचाए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, ऑस्ट्रेलिया में एक सीनेट जांच में यह पता लगाया गया कि क्या गैर-सरकारी प्रशिक्षण प्रदाताओं की मार्केटिंग ने अभ्यर्थियों, विशेष तौर पर लाभ वंचित विद्यार्थियों को प्राप्त की जाने वाली योग्यता के बारे में गलत जानकारी प्रदान की थी।

## निगरानी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में जवाबदेही को बढ़ा सकती है

प्रौढ़ शिक्षा और संख्यात्मक कार्यक्रमों में जवाबदेही विभिन्न कार्यक्रमों, सेवा प्रदाताओं, निधियन प्रणालियों और कथित लक्ष्यों के कारण जटिल बन जाती है। इसके बावजूद, राष्ट्र परिणामों के लिए गुणवत्ता मानकों और आकांक्षाओं का निर्धारण कर रहे हैं। निगरानी प्रणालियां सामान्य हो रही हैं: यूनेस्को की प्रभावी साक्षरता और संख्यात्मक प्रक्रियाएं डाटाबेस में 200 से अधिक प्रौढ़ शिक्षा और संख्यात्मक कार्यक्रमों के लिए सामानता कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन के एक भाग के तौर पर किसी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया गया है।

वित्तीय आंकड़े एकत्रित किए जाने से सरकारों को गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं को गुणवत्ता और संसाधन आबंटन करने के लिए जवाबदेह बनाने में सहायता मिलती है। दक्षिण अफ्रीका का 'खा री गुडे' (आइए सीखें) साक्षरता कार्यक्रम में वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली में विद्यार्थियों तथा शिक्षक डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए एक गैर-सरकारी कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। अध्यापकों का भुगतान व्यय और उपस्थिति डाटा प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होता है। वर्ष 2016 में की गई लेखा-परीक्षा में यह पाया गया कि स्वयंसेवकों ने कथित तौर पर दर्शाए गए दावों से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया था।

साक्षरता कार्यक्रम की निगरानी के परिणाम जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं। क्षेत्रीय दौरा मूल्यांकन भी एक पद्धति हो सकती है, उदाहरण के लिए इसका प्रयोग पाकिस्तान में किया जाता है। अन्य पद्धतियों में रचनात्मक और योगात्मक रणनीतियां शामिल हैं, जैसे कि परीक्षाएं, मौखिक प्रस्तुतियां और स्वयं-मूल्यांकन।

उच्च आय वाले देश प्रायः मानक राष्ट्रीय मूल्यांकन संरचनाओं और उपकरणों का प्रयोग करते हुए उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं, जो कई बार सार्वजनिक वित्त-पोषण से जुड़ा हुआ होता है जैसाकि अमेरिका में किया जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और मेक्सिको सहित कुछ मध्यम आय वाले देश प्रत्येक जिले के लिए स्वतः सृजित ऑनलाइन अंतिम चरण की परीक्षा लेते हैं। अन्य देश रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के लिए कक्षा की सुगमता पर अधिक निर्भर होते हैं और विश्लेषण के लिए सुव्यवस्थित तरीके से आंकड़ों का संकलन नहीं करते हैं। और कुछ कार्यक्रमों में अध्यापन उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए गहन साक्षरता कौशलों के अतिरिक्त साधनों का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस की निरक्षरता के खिलाफ लड़ाई में प्रतिभागियों का मूल्यांकन स्वायत्ता, विश्वास, प्रेरणा, दैनिक जीवन के संवादों और ज्ञान संबंधी विकास के आधार पर किया जाता है।

## विद्यालयों को जवाबदेह बनाने के लिए विद्यार्थी-स्तरीय शिक्षण आंकड़ों का प्रयोग करना महंगा है ....

सरकारों की विद्यालय और विद्यार्थी शिक्षा परिणामों संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने में रुचि बढ़ रही है। सैद्धांतिक तौर पर, इस सूचना से राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और स्कूल स्तर पर शिक्षा नेताओं को प्रमाण-आधारित निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए, जब तक कि सूचना बेहतर गुणवत्ता वाली हो और उनमें राजनैतिक हितों से हटकर निर्णय लेने का सामर्थ्य हो।

“ यूनेस्को डाटाबेस में 200 से अधिक प्रौढ़ शिक्षा और संख्यात्मक कार्यक्रमों में कुछ निगरानी और मूल्यांकन किया गया है ”

योगात्मक मूल्यांकन परिणामों का प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान करने और प्रगति संबंधी निर्णयों के लिए किया जाता है और संस्थागत स्तर पर इनका प्रयोग एक-दूसरे से जुड़े विद्यालयों को उनके सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए किया जाता है। प्रणालीगत स्तर पर, योगात्मक मूल्यांकन परिणाम यह निगरानी करने में सहायक हो सकते हैं कि मानकों को पूरा किया गया है अथवा नहीं।

व्यक्तिगत शिक्षा आंकड़ों का प्रयोग अलग-अलग देशों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रणालियां जैसे जापान में राष्ट्रीय परीक्षाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जो किसी विशिष्ट वर्ष में विभिन्न स्तरों के बीच हुई प्रगति का निर्धारण करती हैं, परंतु इससे एक समय अंतराल की शिक्षा की तुलना नहीं की जा सकती।

अन्य प्रणालियों में अपेक्षित शिक्षा के मानकों को परिभाषित किया जाता है और उनकी तुलना में मूल्यांकनों का आयोजन किया जाता है। इंग्लैंड की शिक्षा संबंधी जटिल और व्यापक प्रणाली राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, जो व्यापक विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली और बाहरी मूल्यांकन प्रणाली का विस्तृत रूप है। संकलित किए गए आंकड़ों का प्रयोग स्कूल का दौरा किए जाने के पूर्व निरीक्षक तैयार करने, अभिभावकों को सूचित करने, स्कूल नेतृत्व को लक्ष्य निर्धारित करने, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान करने और स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकारियों को जवाबदेही के प्रयोजनार्थ कार्य-निष्पादन की निगरानी करने के लिए किया जाता है।

अलग-अलग राष्ट्रों में विभिन्न शिक्षा परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि कुछ राष्ट्रों में विशेष तौर पर भाषा और गणित तथा अन्य राष्ट्रों में व्यापक विषयों पर ध्यान दिया जाता है। अलग-अलग राष्ट्रों में स्कूलों के प्रकार और प्रासंगिक तुलना के लिए विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि की सूचना एकत्रित करने के तरीके भी भिन्न-भिन्न होते हैं। आस्ट्रेलिया में वित्त, जनसांख्यिकीय संरचना और सामाजिक-शैक्षिक लाभ सहित विद्यालयों संबंधी संदर्भ 'माई स्कूल' वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। डेनमार्क में, शिक्षा और गुणवत्ता एजेंसी ने एक विद्यार्थी कल्याण संकेतक लागू किया है।

66

शिक्षा निष्कर्षों से सूचना का प्रबंधन करना शिक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उच्च आय वाले देशों को भी सामान्य व्याख्या से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है

परंतु इन सभी सूचनाओं का प्रबंधन करना शिक्षा प्रणालियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उच्च आय वाले देशों में भी विद्यालयों के लिए समायोजन द्वारा सामान्य व्याख्या और विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक सूचना एकत्रित करने तथा यह निर्धारण करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि गत समय में विद्यालयों और विद्यार्थियों में कुछ सुधार हुआ है अथवा नहीं। राष्ट्रों में ऐसे मूल्य आधारित उपायों को लागू करने का प्रचलन बढ़ रहा है, परंतु वे पर्याप्त तौर पर सटीक नहीं होते और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है।

”

ये समस्याएं मध्यम और निम्न आय वाले राष्ट्रों में ज्यादा हैं। विश्वसनीय तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिणामों की सूचना तैयार

करना काफी महंगा कार्य है और इसकी क्षमता में आवश्यक निवेश प्रतिषेधात्मक हो सकता है। ये राष्ट्र प्रायः मानकों के आधार पर तुलना की बजाय फाइनल परीक्षाओं के परिणामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए जार्डन की राष्ट्रीय परीक्षा में प्रत्येक तीन वर्ष में प्रत्येक ग्रेड का मूल्यांकन किया जाता है परंतु परिणामों की तुलना गत वर्षों से नहीं की जा सकती क्योंकि परीक्षा मर्दों में नियमित तौर पर बदलाव होता है। प्रकाशित किए गए प्रतिवेदनों में अधिकांश विवरणात्मक सारणियां होती हैं, जिनमें नीति संबंधी कोई विश्लेषण नहीं किया जाता है और अध्यापकों को - विज्ञान संबंधी सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के बावजूद परिणामों को समझने में कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

**....और यह प्रमाण कि कार्य-निष्पादन आधारित जवाबदेही अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है, मिश्रित है**

समीक्षा की गई 101 शिक्षा प्रणालियों में से 51 प्रणालियों में विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें 17 प्रणालियां ऐसी हैं, जहां उनका प्रयोग विद्यालयों और शिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया। हालांकि, परीक्षा के अंक मुख्य तौर पर ऐसे कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिन पर स्कूल का कोई नियंत्रण नहीं होता।

इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि परीक्षा अंकों के लिए स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान किए जाने से उनकी शिक्षा में सुधार हुआ है: आंकड़ों से विशिष्ट तौर पर यह पता चलता है कि इसका या तो बिल्कुल नहीं अथवा थोड़ा बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के 'नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट' में घटिया कार्य-निष्पादन वाले विद्यालयों को बंद करने की धमकी दी गई है। इससे विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन पर बेहद कम सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लिखित तौर पर उपलब्धि अंतर और बढ़ा है तथा विद्यार्थियों की कमियां उजागर हुई हैं, विशेष तौर पर निम्न कार्य-निष्पादन वाले विद्यालयों में पाठ्यक्रमों को और सीमित किया गया है क्योंकि विद्यालयों ने प्राथमिकता वाले परीक्षण विषयों को वरीयता प्रदान की है।

66

कार्य-निष्पादन आधारित जवाबदेही से विद्यालय नकारात्मक तरीके अपना सकते हैं, प्रणाली का अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और दीर्घकालिक सुधारों को रोकने पर प्रतिबंध लगाने से बच सकते हैं

”

विद्यालय कार्य-निष्पादन आधारित जवाबदेही प्रणालियों को नकारात्मक ढंग से समायोजित कर सकते हैं, प्रणाली को अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और दीर्घकालिक सुधारों को रोकने पर प्रतिबंध लगाने से बच सकते हैं। आस्ट्रेलिया, चिली, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया और अन्यत्र स्थानों पर परीक्षा सामग्री को पुनः आकार प्रदान करने, पाठ्यक्रमों को सीमित करने, परीक्षा के अनुसार शिक्षण और नकल करने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने लाभ वंचित विद्यालयों और विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रभावित किया है।

## शिक्षा में बाजार प्रतिस्पर्धा सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकती है

एक संभावित जवाबदेही प्रणाली प्रतिस्पर्धा है। इसके पीछे यह विचारधारा है कि यदि अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल का चयन कर सकते हैं, तो इससे विद्यालयों पर विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए बेहतर कार्य-निष्पादन दबाव बनता है।

अभिभावकों के लिए स्कूल का चयन करने और बाजार के कार्य करने के लिए स्कूल की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराना और इसे बोधगम्य बनाना, इसकी पूर्वपिछा है। कई मध्यम और उच्च आय वाले देशों में शिक्षा प्रणालियों और स्कूल-स्तरीय परीक्षा परिणामों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, गरीब देशों में वांछित प्रयोक्ताओं के लिए सूचना आसानी से उपलब्ध अथवा बोधगम्य नहीं होती। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड बहुत ही कम उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है। केन्या में, 72% अभिभावकों को यह जानकारी नहीं है कि साक्षरता और संख्यात्मक सूचना का उपयोग कैसे किया जाए।

कुछ मध्यम और उच्च आय वाले देश विद्यालयों के लिए बाजार तैयार करने में सक्रिय रहे हैं। गत 25 वर्षों में आर्थिक सहयोग विकास संगठन के सदस्य देशों

में दो-तिहाई देशों में स्कूल चुनने का विकल्प संबंधी नीतियां बढ़ी हैं। हालांकि, प्रमाणों से पता चलता है कि स्कूल विकल्प नीतियों से लाभान्वित जनसंख्या को ही अधिक लाभ हुआ है। अभिभावक प्रायः जनसांख्यिकीय संरचना जैसे कारकों के आधार पर स्कूल का विकल्प चुनते हैं, जिससे विविधता कम होने के साथ ही सामाजिक-आर्थिक विभाजन को भी बल मिलता है। फिनलैंड में, स्कूल विकल्प का प्रयोग मुख्य तौर पर उन शिक्षित परिवारों द्वारा किया गया, जिनके बच्चे शैक्षिक तौर पर श्रेष्ठ थे। सेंटागो, चिली में ग्रेड प्रथम के विद्यार्थियों के चार अभिभावकों में से एक अभिभावक ने अपनी लघु-सूची में से उच्चतम कार्य-निष्पादन वाले स्कूल का चयन किया और लगभग 70% ने धर्म से जुड़े स्कूल का चयन किया।

वाउचर कार्यक्रम स्कूल विकल्प को एक समान कर सकते हैं, परंतु शिक्षा पर उनका प्रभाव मिश्रित होता है। कोलंबिया के निम्न आय वाले पड़ोसियों को लक्षित करके तैयार किए गए कार्यक्रमों ने गैर-सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के साथ ही वाउचर प्राप्त करने वालों के उपलब्धि स्तरों और स्नातक दरों को बढ़ाया है। हालांकि, सार्वभौमिक स्तर पर वाउचर उपलब्ध कराने और विद्यालयों को शुल्क वसूलने की अनुमति प्रदान करने से विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन में सुधार किए बिना असमानता बढ़ सकती है। स्वीडन के सार्वभौमिक वाउचर कार्यक्रम को बढ़ते हुए अलगाव के साथ जोड़ा गया है। चिली में उच्च स्तरीय प्रणाली है। इसके वाउचर कार्यक्रम ने उच्च उपलब्धि और उच्च आय वाले विद्यार्थियों के चयनित दारिवले को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2008 में प्रयोजनों को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों से समानता में बहुत कम सुधार हुआ है।

## समुदाय विद्यालयों की नीतियों और प्रक्रियाओं को आकार देने और उनकी निगरानी करने में सहायता कर सकते हैं

समुदायों द्वारा सामाजिक जवाबदेही स्कूल की प्रतिक्रियाशीलता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। सामुदायिक निगरानी का फोकस प्रायः अवसंरचना, स्टाफ की उपस्थिति और बजट पर होता है, परंतु एक-बारगी कार्यक्रम का प्रभाव अस्थायी होता है। इथोपिया में, स्कूल डाटा संकलित करने और सामुदायिक संवाद बढ़ाने में समुदाय की सरकार के साथ भागीदारी के सकारात्मक परिणाम रहे हैं। हालांकि, संसाधनों की कमी ऐसी परियोजनाओं को चलाए रखने के लिए खतरा बन सकती है।

सामुदायिक हितधारक स्कूल-आधारित प्रबंधन (एसबीएम) में भाग लेते हैं, जिसमें निर्णय लेने का प्राधिकार और उत्तरदायित्व स्थानीय कार्यकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है। एसबीएम ने इंडोनेशिया और मेक्सिको सहित कई देशों में विद्यार्थी की उपलब्धि और उपस्थिति में सुधार किया है। हालांकि, सामुदायिक सदस्यों के साथ उत्तरदायित्व को साझा करने की अनिच्छा से एसबीएम के कुछ प्रयासों ने गतिरोध पैदा किया है, जैसे कि हांगकांग और चीन में हुआ है। कई बार समुदाय के प्रतिनिधित्व में हाशिए पर रहने वाले समूहों को शामिल नहीं किया जाता। नेपाल में कुछ एसबीएम समितियों के लिए विशिष्ट वर्ग को अधिकृत किए जाने से समस्या पैदा हुई है।



क्या वास्तव में स्कूल चुनने का विकल्प मौजूद है?

“

अभिभावक प्रायः जनसांख्यिकीय संरचना जैसे कारकों के आधार पर स्कूल चुनते हैं, जिससे विविधता कम होने के साथ ही सामाजिक-आर्थिक विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है

”

# जवाबदेह अध्यापक

विद्यार्थियों को शिक्षित करना अध्यापकों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। कई देशों में, उन्हें बढ़ते हुए दबाव का सामना करना पड़ता है। उनके कार्यों की जटिलता और विविधता उनके समय में विरोधाभासी मांगें पैदा कर सकती है, उनको जवाबदेह ठहराने के लिए प्रयासों की जटिलता बढ़ सकती है।

## उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है

अधिकांश देश अध्यापकों का ज्यादातर कार्य समय अध्यापन के लिए रखते हैं। कुछ देशों में औपचारिक शिक्षा मुख्य विषयों से आगे बढ़कर पाठ्यक्रम से इतर कौशलों और सामाजिक, व्यवहारगत एवं भावनात्मक दक्षताओं तक पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण और शिक्षा सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले अध्यापकों ने एक सप्ताह में लगभग दो घंटे का समय पाठ्यचर्या बाहरी कार्यकलापों में व्यतीत किया, जिसमें औसतन स्वीडन में एक घंटा बिताने से लेकर जापान में आठ घंटे बिताना जाना शामिल है। अध्यापकों के ऐसे उत्तरदायित्व भी होते हैं, जिन्हें प्रायः मान्यता प्रदान नहीं की जाती अथवा पुरस्कृत नहीं किया जाता, जिससे प्रोत्साहन में कमी आ सकती है।

2000 के दशक के पूर्वार्द्ध में छह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के अध्ययन से यह पता चला कि औसतन अध्यापकों की अनुपस्थिति 19% थी। हालांकि, अनुपस्थित रहने के लिए अध्यापकों के उत्तरदायित्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। वर्ष 2007 और 2014 के बीच सेनेगल के विद्यार्थियों को औसतन 188 सरकारी वार्षिक स्कूल कार्य दिवसों में से 108 स्कूल कार्य दिवस मिले। अनुपस्थिति के ज्यादातर कारणों पर अध्यापकों का कोई नियंत्रण नहीं था (चित्र 6)। इंडोनेशिया में वर्ष 2013 और 2014 में प्राथमिक स्कूलों के 10% अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। इनमें से लगभग आधे अनुपस्थित अध्यापकों को अध्ययन के लिए समय प्रदान किया गया था।

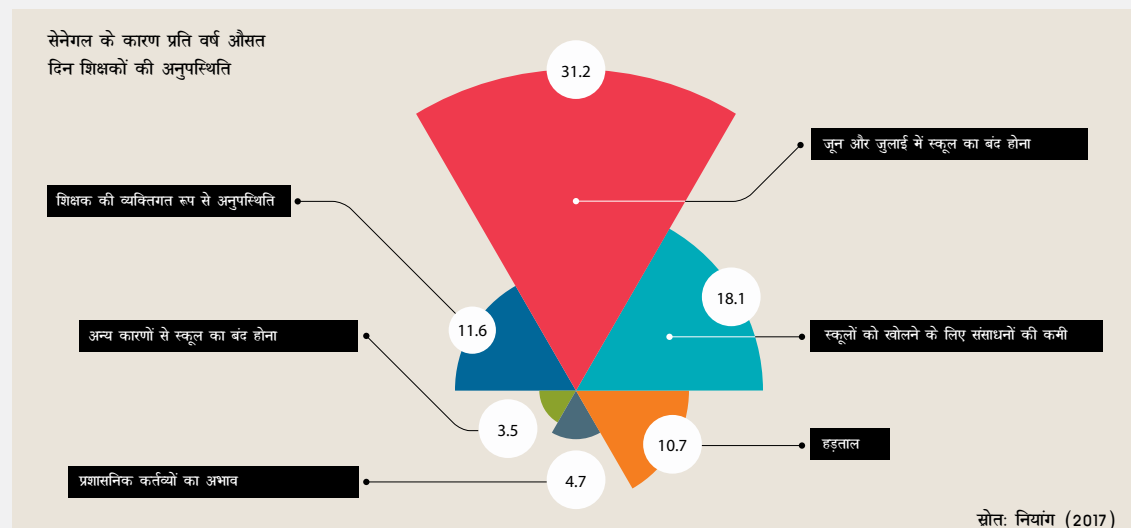
“ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण और शिक्षा सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले अध्यापकों ने एक सप्ताह में औसतन लगभग दो घंटे का समय पाठ्यचर्या बाहरी कार्यकलापों में व्यतीत किया ”

## शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अध्यापकों का मूल्यांकन कठिन हो सकता है और इसके कई रूप होते हैं

सरकार और आम लोग शिक्षण व्यवसाय में विश्वास रखते हैं और अध्यापकों का विश्वास मूल्यांकन प्रक्रिया में होता है, जो जवाबदेही दृष्टिकोणों को अत्यधिक प्रभावित करती है। फिनलैंड में अध्यापक अपनी स्वयं की जवाबदेही नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं, जो हितधारकों के बीच आपसी विश्वास का प्रमाण है। इसके विपरीत, जापान के अध्यापकों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकनों के संबंध में कम कार्य-निष्पादन के कारण विश्वास घटा है और बाहरी जवाबदेही प्रणालियों में बढ़ोतरी के कारण औसतन 54 घंटा प्रति सप्ताह के कार्यभार में रिपोर्टिंग करने के उत्तरदायित्व को और बढ़ा दिया है।

### चित्र 6:

सेनेगल के विद्यार्थियों को स्कूल बंद होने के कारण वार्षिक तौर पर 50 से अधिक स्कूल दिवसों की क्षति हुई



अनुबंध पर अध्यापन करना प्रारंभ में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए एक कामचलाऊ व्यवस्था थी, परंतु अल्पावधि अध्यापक अनुबंध का प्रचलन कम विश्वास वाले परिवेश में बढ़ रहा है जिसमें अनुबंध नवीनीकरण का तात्पर्य बेहतर कार्य-निष्पादन को प्रेरित करना होता है। निश्चित कार्यकाल वाले पदों पर अध्यापकों की कमी से प्रायः स्टाफ पर कार्यभार बढ़ जाता है, सार्वजनिक वित्त-पोषण में कमी आती है और स्टाफ तथा संगठन के अधिकारों में कटौती होती है। अनुबंध अध्यापक प्रायः कम योग्यता प्राप्त असंतुष्ट और कम वेतन प्राप्त करने वाले होते हैं।

## अध्यापकों को जवाबदेह बनाने के लिए औपचारिक मूल्यांकन सबसे सामान्य प्रणाली है

ज्यादातर देश अध्यापकों का मूल्यांकन विविध दृष्टिकोणों के आधार पर करते हैं। सबसे अमीर देशों, जिन्होंने 2013 टीएलआईएस में भाग लिया था, में 96% अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु कक्षा अवलोकन प्रणाली का उपयोग किया गया। अवलोकन प्रायः प्रधानाचार्यों अथवा प्रबंधन टीम के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसके परिणाम अलग-अलग होते हैं। सिंगापुर में, सूचना का उपयोग मुख्यतः रचनात्मक प्रयोजन के लिए किया जाता है, इजराइल में अवलोकनों का प्रयोग पदोन्नति में किया जाता है। अमेरिका में अध्यापकों की विशिष्टता वाली रेटिंग प्रायः खराब रही है। विश्वसनीय और उपयोगी अवलोकन के लिए सुव्यवस्थित और कार्य करने योग्य फीडबैक होनी चाहिए। समान समूह सहित विषय और शिक्षा-शास्त्र विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षित पर्यवेक्षक ज्यादा सतत् फीडबैक प्रदान करते हैं।

2013 में टीएलआईएस में, 83 प्रतिशत अध्यापकों ने यह सूचना प्रदान की कि विद्यार्थियों का सर्वेक्षण मूल्यांकनों का भाग था। विद्यार्थियों के मूल्यांकनों का उपयोग किए जाने से यह अवधारणा बनी कि विद्यार्थी अच्छे शिक्षण की पहचान करके इसकी सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं। विश्वसनीयता मुख्यतः मूल्यांकन प्रयोजन और अभिकल्पना पर निर्भर होती है और विद्यार्थियों के पूर्वाग्रह से इसमें अवरोध पैदा हो सकता है। फ्रांस और इटली में जिन अध्यापकों ने उच्च ग्रेड प्रदान किए, उन्हें बेहतर मूल्यांकन मिला। अध्यापकों का महिला या पुरुष होना भी विद्यार्थियों की अवधारणा को प्रभावित कर सकता है।

“ शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के मूल्यांकनों की विश्वसनीयता मुख्यतः मूल्यांकन के उद्देश्य और उसकी रूपरेखा पर निर्भर करती है और विद्यार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह रखने से इसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है ”

2013 टीएलआईएस में विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक अध्यापकों के मूल्यांकन का सबसे सामान्य घटक था, जैसाकि 97% अध्यापकों द्वारा जानकारी प्रदान की गई है। हालांकि, परीक्षा के अंक शामिल किए गए पाठ्यक्रमों, विद्यार्थी की क्षमता, अभिभावकों की भागीदारी तथा स्कूल की संस्कृति और संसाधनों सहित कई कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अध्यापक की प्रभावशीलता के लिए केवल अंक कम विश्वसनीय संकेतक हैं। ज्यादा सटीक मूल्यांकनों में बहु-स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जो कम संसाधन वाली प्रणालियों में बहुत मुश्किल होते हैं।

अध्यापक का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर लगातार बढ़ रहा है। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि जवाबदेही का यह दृष्टिकोण कथित शिक्षा समस्याओं के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करता है, वे विशिष्ट तौर पर यह मानते हैं (क) सभी शिक्षा कार्यकर्ता ऐसे वांछित परिणामों पर सहमत होते हैं, जिन्हें सटीक तौर पर मापा जा सकता है (ख) उत्तरदायित्वों को स्पष्ट परिभाषित करते हुए सूचित किया जाता है और उत्तरदायी कार्यकर्ताओं के पास स्वयं वांछित परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता होती है तथा (ग) चयनित प्रोत्साहन ऐसे कार्य को प्रेरित करते हैं, जो वांछित परिणाम प्रदान करते हैं। परंतु कार्य-निष्पादन आधारित भुगतान का शिक्षा परिणामों पर मिला-जुला प्रभाव होता है जो समानता के लिए हानिकारक हो सकता है। यह प्रतिस्पर्धी माहौल को भी बढ़ावा दे सकता है, जो इसके आशय के विपरीत अध्यापकों की प्रेरणा को कम कर सकता है। कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि यह महिला अध्यापकों को पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा अधिक नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। अमीर देशों में उच्च-सिद्धांतों वाली अध्यापक मूल्यांकन प्रणालियों में निष्कर्षों का सुधार करने की सीमित क्षमता होती है। कार्रवाई योग्य फीडबैक की कमी और सुधार संबंधी निगरानी पर ध्यान न दिए जाने से अध्यापकों की संतुष्टि कम हो सकती है और कई लोग मूल्यांकन को मात्र प्रशासनिक कार्य समझने लगते हैं।

## जवाबदेही पर केन्द्रित शिक्षा प्रणालियां पर्याप्त तौर पर अध्यापक तैयार नहीं करतीं

शिक्षा संबंधी और प्रबंधन उत्तरदायित्व स्कूलों को सौंपे जाने की प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतीत होती है। सुदृढ़ जवाबदेही प्रणालियां लागू किए जाने से इस प्रवृत्ति के कार्यभार में वृद्धि हुई है और अध्यापकों तथा स्कूल नेतृत्व की ओर से अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे शिकायतें बढ़ सकती हैं (यूनाइटेड किंगडम में 56 प्रतिशत अध्यापकों ने यह सूचित किया कि डाटा संकलन और प्रबंधन से अनावश्यक कार्य बढ़ गया है।

अध्यापकों के पास विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने और उन्हें अनुदेश के तौर पर प्रयोग करने का कौशल होना चाहिए। परंतु कई अध्यापक डाटा प्रयोग में असहाय महसूस करते हैं। अमेरिका में एक अध्ययन से यह पता चला है कि दो-तिहाई अध्यापकों के पास अनुदेश में सुधार लाने के लिए आंकड़ों को प्रयोग करने की सुविधा नहीं थी और प्रायः यह देखा गया कि इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

“ मूल्यांकन प्रक्रिया में अध्यापकों का विश्वास जवाबदेही दृष्टिकोणों को अत्यधिक प्रभावित करता है ”

कई उच्च आय वाले देश डाटा साक्षरता को अध्यापक और प्रधानाचार्य तैयार करने और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे कार्यक्रमों में रिपोर्टों को समझने पर ध्यान दिया जाता है और कुछ कार्यक्रमों में शिक्षण के लिए डाटा का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों का जोर प्रायः डाटा साक्षरता कौशल की बजाय प्रौद्योगिकी पर होता है।

डाटा संकलन के दोहरेपन को कम करने से अध्यापकों और प्रधानाचार्यों पर भार कम हो सकता है। परंतु, शिक्षा प्रबंधन के लिए डाटा प्रयोग करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से और अधिक सामान्य प्रश्न पैदा होते हैं। प्रथम, यह विचार कि शिक्षा स्तर में सुधार संबंधी कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं, वह शिक्षा के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की अवहेलना करता है। दूसरा, निगरानी किए जाने वाले शिक्षा परिणामों पर बल दिए जाने से मुख्यतः जवाबदेही प्रणाली का प्रयोजन पूरा होता है, जो बहुत ही सीमित शिक्षा परिणामों के सेट पर आधारित होता है। इसलिए, उनकी उपयोगिता के बावजूद डाटा को प्रत्यक्ष तौर पर लिए जाने के लिए संरक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है। डाटा का परीक्षण करने के बाद ही उपयोग किए जाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

## व्यावसायिक जवाबदेही शिक्षण संस्कृति को आकार दे सकती है

व्यावसायिक जवाबदेही की परिकल्पना अध्यापकों की सहभागिता के आधार पर की गई है और यह उनकी विशेषज्ञता और व्यावसायिक दक्षता पर निर्भर होती है। व्यावसायिक जवाबदेही को निगमित करने वाली प्रणालियां प्रायः उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में शिक्षण व्यवसाय में आम लोगों के विश्वास के कारण तैयार की जाती हैं।

समकक्ष समूह में शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। विशेष तौर पर जैसाकि मध्यम और उच्च आय वाले देशों में देखा गया है, व्यावसायिक शिक्षा समुदाय समकक्षों में अनुभवों को साझा करने सहित सहयोगात्मक शिक्षा ढांचा प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, यूनाईटेड किंगडम और अमेरिका में प्रयोग किए गए अनुभव अध्ययन मॉडल में सहयोगात्मक योजना, अवलोकन, विश्लेषण तथा अनुभव प्रदान करने और विद्यार्थी की शिक्षा को सुधारने के लिए उन्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। इंग्लैंड में, पाठ अध्ययन ने अनुदेशात्मक जोखिम लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए अध्यापकों में अलगवर्ग की भावना को कम किया है। प्रभावी समकक्ष समूह शिक्षा के लिए अध्यापकों की स्वायत्ता और व्यापक समय तथा संसाधन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।



अधिकांश देशों में व्यवस्थागत व्यावसायिक मानदंडों के माध्यम से स्वः अनुशासनात्मक दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए अध्यापकों द्वारा एक आचार संहिता विकसित की गई है। 24 देशों में आचार संहिता की समीक्षा में यह पाया गया कि कई अध्यापकों को उनकी जानकारी नहीं थी। स्पष्ट प्रवर्तन प्रणाली के अभाव में इसकी प्रभावशीलता अवरोधित हो सकती है। रिपोर्टिंग प्रणाली और प्रतिबंध भी सदैव परिभाषित नहीं होते। कदाचार का मूल्यांकन करने वालों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

## नागरिक अध्यापकों को जवाबदेह बनाने में सहायता कर सकते हैं

सामुदायिक निगरानी विशेष तौर पर अध्यापकों की अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति का समाधान कर सकती है। युगांडा में, समुदाय द्वारा परिकल्पित रिपोर्ट कार्डों ने अध्यापकों की अनुपस्थिति को कम किया है। हालांकि, अध्यापकों को जवाबदेह बनाने के लिए अभिभावकों पर निर्भरता स्थायी नहीं है। केन्या में, अभिभावकों द्वारा निगरानी और अध्यापकों का मूल्यांकन किए जाने की प्रक्रिया से प्राप्त शिक्षण को कार्यक्रम समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही हटा दिया गया।

विश्वास और दखल देने संबंधी चिंताओं के बावजूद अधिकतर प्रणालियों में अध्यापकों की निगरानी हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान में 26,200 विद्यालयों में 210,000 शिक्षा कर्मियों की उपस्थिति की निगरानी बायोमीट्रिक का प्रयोग करते हुए की गई है। फरवरी, 2017 तक 40,000 अनुपस्थित अध्यापकों और 6,000 भगौड़े कर्मियों को अनुशासित किया गया है। चीन में हजारों कक्षाओं का सजीव प्रसारण होता है, जिससे अभिभावकों और आम नागरिकों को अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-विधियों और विद्यार्थियों के व्यवहार की निगरानी करने और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मिला है। आलोचक इस बात पर चिंतित हैं कि सतत निगरानी से अध्यापकों और विद्यार्थियों के निजता के अधिकारों का उल्लंघन होता है और इससे शिक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

“

24 देशों में आचार संहिता की समीक्षा में यह पाया गया कि कई अध्यापकों को उनकी जानकारी नहीं थी

”

अध्यापकों की निगरानी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत क्षमता और अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकती है। लाभचिंत अभिभावकों में प्रायः कौशल, ज्ञान अथवा अध्यापकों के साथ संवाद करने के विश्वास की कमी होती है। ऐसी निगरानी को सफल बनाने के लिए समुदाय के सदस्यों और अध्यापक दोनों को निर्धारित मानदंडों और जवाबदेही प्रणालियों की ऐसी परिकल्पना में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो।

# जवाबदेह अभिभावक और विद्यार्थी

जवाबदेही नीतियों में प्रायः अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा के अधिकार के लिए सरकारों, विद्यालयों और अध्यापकों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। परंतु, चूंकि शिक्षा साझा सामाजिक प्रयास है, इसलिए अभिभावकों और विद्यार्थियों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावक न केवल घर में प्रेरणादायी माहौल प्रदान करने अपितु अपने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, प्रयास और व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। विद्यार्थी बड़े होने के साथ ही इन उत्तरदायित्वों के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं।

## अकारण गैर-हाजिर रहने संबंधी विधियों में अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए दण्ड का निर्धारण किया गया है।

स्कूल से अकारण गैर-हाजिर रहना - विश्व भर की एक व्यापक समस्या है। औसतन, वैश्विक स्कूल-आधारित विद्यार्थी स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 33 देशों में 13-17 आयु के 3 किशोरों में से एक किशोर गत तीस दिनों में अकारण गैर-हाजिर रहा, यह दर बहमास में 20 प्रतिशत से लेकर कुवैत, ओमान और तोकलाऊ में 40 प्रतिशत तक है, अकारण गैर-हाजिर रहने का विद्यार्थियों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक तौर पर नकारात्मक प्रभाव होता है, इसे ग्रेड में फेल होने और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के साथ ही न्यायिक प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है।

उपेक्षित विद्यार्थियों में अकारण अनुपस्थित रहने की संभावना अधिक रहती है। जबकि अकारण गैर-हाजिर रहना एक बहु-आयामी घटनाक्रम है, जिसमें विभिन्न कारक शामिल होते हैं और इसे रोकने में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

कई देशों में अकारण अनुपस्थित रहने संबंधी कानून हैं, जिनमें उपस्थिति के लिए अभिभावकों को जवाबदेह बनाया गया है। जर्मनी लगाया जाना सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला दंड है, हालांकि कुछ देशों में अपराधिक आरोप लगाए जाते हैं (चित्र 7)। कड़े प्रतिबंध ऐसे निम्न आय वाले परिवारों और महिलाओं को प्रभावित करते हैं, जो एकल माता-पिता वाले घरों को संचालित करते हैं।

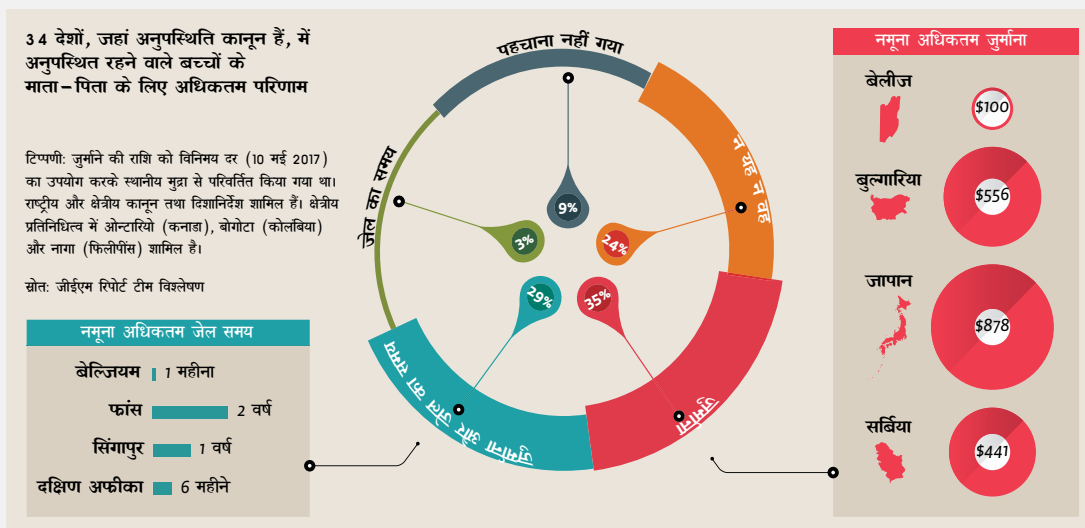
इसलिए, अकारण गैर-हाजिर रहने का कानून, हालांकि कानूनी ढांचा प्रदान करने, के साथ निवारण हेतु सहायक ढांचा स्थापित किया जाना आवश्यक है। अभिभावकों की जवाबदेही बढ़ाने का कार्य स्कूल-अभिभावक संबंध की जानकारी प्राप्त करके तथा इसमें सुधार करके प्रारंभ किया जाता है, उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और आयरलैंड में ऐसा किया गया है।

## सशर्त नकदी हस्तांतरण का लक्ष्य गरीब परिवार होने चाहिए

सशर्त नकदी हस्तांतरण (सीसीटी) में गरीब परिवारों के लिए राजसहायता को इस शर्त के साथ जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको सहित लेटिन अमेरिका देशों में अग्रणी भूमिका निभाई है और इसका विस्तार मध्यम और निम्न आय वाले एशियाई तथा उप-सहारा अफ्रीकी देशों में भी किया गया है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, सीसीटी को प्रायः नकारात्मक प्रोत्साहन के तौर पर लागू किया जाता है, जो जर्मनी की तरह होता है। उदाहरण के लिए रोमानिया में कई बार अकारण अनुपस्थिति के बाद गरीब परिवारों का बाल भत्ता बंद कर दिया जाता है।

### चित्र 7 :

अकारण गैर-हाजिर रहने के लिए सर्वाधिक जुर्माना लगाया जाता है।





सीसीटी ने बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया है, विशेष तौर पर बांग्लादेश, कम्बोडिया, निकारगुआ और अन्य स्थानों पर बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ी है। 34 उच्च आय वाले देशों में सीसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा में भी इसी प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। उनकी प्रभावशीलता उनके लक्ष्यों, स्कूल पहुंचने की सुलभता और अंतरित राशि की मात्रा पर निर्भर होती है, अंतरित की जाने वाली राशि उपस्थिति के अवसर को भुनाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

## सुरक्षित शिक्षा परिवेश को प्रोत्साहित करने में अभिभावकों और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है

शिक्षा के लिए, बच्चों और किशोरों को उनके शिक्षा परिवेश में सुरक्षित और समर्थित महसूस कराए जाने की आवश्यकता है। इस परिवेश को तैयार करने में सक्रिय भागीदारों के तौर पर विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि उनका व्यवहार अन्य विद्यार्थियों के लिए ऐसी सुरक्षा और सहायता के अधिकार का हनन न करे।

“ स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वीकार्य संवाद रणनीतियों की जानकारी देने संबंधी आचरण संहिता से स्कूलों में हिंसा कम हुई है। ”

विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वीकार्य संवाद रणनीतियां सिखाने के लिए आचरण संहिता के प्रयोग का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसी संहिताएं स्कूलों में हिंसा कम करने में प्रभावी पाई गई है जबकि ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपनाए जाने वाला यह दृष्टिकोण सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में भी लागू किया गया है।

स्कूलों में हिंसा कम करने के लिए विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट और अनवरत नियमावली और अनुशासनात्मक मानकों के अतिरिक्त अभिभावकों की बैठकें और प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण संघटक है। अभिभावकों का उनके बच्चों उनके सहपाठियों के साथ संबंध, प्रत्यक्ष (उदाहरण के लिए बच्चों को सहपाठियों के साथ संबंध विकसित करने में सहायता करना) और अप्रत्यक्ष (उदाहरण के लिए अभिभावक के दृष्टिकोण) दोनों प्रकार से, विकसित करने में योगदान होता है।

अमेरिका में, ऐसे घरों के माहौल को डराने-धमकाने की घटनाओं के साथ जोड़ा गया है, जहां अभिभावक अनावश्यक तौर पर अपने बच्चों की आलोचना करते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और एक-दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। मिस्र, मोरक्को और ट्यूनिशिया में बेहतर अभिभावक प्रोत्साहन, भावनात्मक सहयोग और अभिभावक, बच्चे की बातचीत को बच्चों की आपस में झगड़ने की संभावना को कम करने के साथ जोड़ा गया है।

## जवाबदेह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय, ट्रांसनेशनल और बड़े राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय मानक पूरा करने में गतिशीलता और सहायता प्रदान करते हैं। परंतु, उन्हें जवाबदेह ठहराना मुश्किल है, क्योंकि वे बहु-हितधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों और उन लोगों के लिए भी जवाबदेह है, जिनके अधिकारों का सदस्य देशों द्वारा उल्लंघन किया जाता है।

### अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सामान्य लक्ष्यों का निर्धारण करने में सहायता करते हैं

“ स्थायी विकास कार्यसूची के मद्देनज़र विविध हितों को समायोजित करने का तात्पर्य जटिल लक्ष्य, अस्पष्ट वरीयता क्षेत्र और अपेक्षाकृत कमजोर निगरानी है ”

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सामान्य शिक्षा लक्ष्यों का निर्धारण करने और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की स्थापना करने में सदस्य देशों और अन्य हितधारकों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए कि शिक्षा मसौदों और करारों में विविध प्रकार के विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, उदाहरण के लिए स्थायी विकास मसौदे के लिए विविध हितों को समायोजित करने का तात्पर्य होगा जटिल लक्ष्य, अस्पष्ट वरीयता क्षेत्र और अपेक्षाकृत कमजोर निगरानी। ‘जवाबदेही’ को एसडीपी फाउंडेशन दस्तावेज में स्पष्ट तौर पर शामिल नहीं किया गया है।



इस बात का स्पष्ट निर्धारण न होने के अभाव में कि कौन किसके लिए उत्तरदायी है, न केवल अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने वाले देशों अपितु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भी जवाबदेही की कमी है। सभी समन्वित प्रणालियों के लिए शिक्षा के मूल्यांकन में यह पता चला है कि भागीदारों और पक्षकारों की भूमिकाएं अस्पष्ट थीं और जवाबदेही प्रक्रियाओं की कमी थी। बहु-भूमिकाओं और प्रतिस्पर्धी मसौदों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां अस्पष्ट उत्तरदायित्वों के कारण किसी कार्यकर्ता को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो गया। संगठनों को जवाबदेह ठहराने के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती है जो सीमित होते हैं।

जबकि लक्ष्यों के निर्धारण और उनकी प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के उत्तरदायित्व को वैश्विक स्तर पर काफी कम किया गया है, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर यह स्थिति भिन्न है। यूरोप में ईटी 2020 कार्यनीतिक संरचना में शिक्षा का इसकी समग्र विकास रणनीति के तौर पर उल्लेख किया गया है। यूरोपीयन यूनियन अपने संस्थागत ढांचों का प्रयोग कार्यों को सौंपने के लिए करता है। यूरोपीयन आयोग लक्ष्यों और उत्कृष्ट मानकों की तुलना में देशों द्वारा की गई प्रगति का पता लगाते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और यूरोपीयन परिषद के साथ प्रत्येक पांच वर्ष में सहयोग द्वारा श्रेष्ठ तरीके से निर्धारित की गई प्राथमिकताओं और सामान्य चुनौतियों संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। परंतु सुदृढ़ संस्थागत और संगठन क्षमता के बावजूद समन्वित कार्यों के लिए उत्तरदायित्व अलग-अलग होता है।

## मानकों का निर्धारण करते समय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को पारदर्शी होना चाहिए

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन समन्वय, आम सहमति और समानता में सहायता प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा प्रक्रियाओं के मानकों का निर्धारण करते हैं। एसडीजी संकेतक संरचना का विकास, जिस पर व्यापक विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है, इसका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बोलोगना प्रक्रिया है, जिसमें संयुक्त अर्हता संरचना, क्रेडिट प्रणाली, गुणवत्ता आश्वासन मानकों और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन उपकरणों के साथ 48 देशों को आपस में जोड़ते हुए यूरोपीयन उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की गई है। इसमें राष्ट्रीय कार्यान्वयन पर दबाव बनाए बिना जवाबदेही प्रणाली स्थापित करने के लिए इसकी सराहना की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने औपचारिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त तैयार किए गए शिक्षा मानकों का भी प्रचार-प्रसार किया है, उदाहरण के लिए, शिक्षा मानक। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु ओईसीडी कार्यक्रम ने शिक्षा नीति को परिणाम आधारित बना दिया है परंतु गैर-ओईसीडी देशों की प्रणालियों को प्रभावित करने, जिसके लिए यह जवाबदेह नहीं है, इसकी आलोचना भी की जाती है।

## दानदाताओं को उनकी सहायता प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए

66

सहायता का अनुमान वर्ष 2010 और 2015 के बीच कम हुआ है और समावेशिता संबंधी आपसी जवाबदेही शर्तों को पूरा नहीं किया गया

कई संगठनों के मिशनों में वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से गरीब देशों की शिक्षा प्रणालियों में सुधार करने का उत्तरदायित्व शामिल किया गया है। दानदाता एजेंसियां दान देने वाले देश के नागरिकों और सहायता प्राप्त करने वाले देश के नागरिकों, दोनों के प्रति जवाबदेह हैं, जो संभावित प्रतिस्पर्धी उत्तरदायित्वों को प्रस्तुत करती हैं।

दानदाताओं को सहायता प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई प्रणालियों का अभाव है। वर्ष 2015 में, 28 ओईसीडी विकास सहायता समिति (डीएसी) सदस्य देशों में से केवल 6 देशों ने ही अपनी राष्ट्रीय आय का 0.7 प्रतिशत सहायता हेतु आबंटित करने संबंधी प्रतिबद्धता को पूरा किया। संगठनों को औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सहायता की मात्रा के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, जैसे ओईसीडी समकक्ष समूह समीक्षा प्रणाली और अनौपचारिक माध्यम जैसे मीडिया और गैर-सरकारी संगठन।

केवल सहायता की मात्र ही नहीं अपितु इसकी प्रभावशीलता भी महत्वपूर्ण होती है। प्रभावी विकास सहयोग हेतु वैश्विक भागीदारी द्वारा विकास सहभागी कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है। इसकी वर्ष 2016 की निगरानी रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि सहायता की जानकारी प्रदान करने संबंधी पारदर्शिता में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि, सहायता का अनुमान वर्ष 2010 और 2015 के बीच कम हुआ है और समावेशिता संबंधी आपसी जवाबदेही शर्तों को पूरा नहीं किया गया। सुदृढ़ निगरानी प्रक्रियाओं से न तो सहायता राशि की मात्रा में वृद्धि हुई है और न ही सर्वाधिक जरूरतमंद देशों का लक्ष्य निर्धारित करने में सुधार हुआ है, हालांकि यह बता पाना मुश्किल है कि इन प्रक्रियाओं के बिना सामूहिक रिकार्ड क्या होता।

बहु-स्तरीय दानदाता कुल शिक्षा सहायता का लगभग एक-तिहाई प्रदान करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि नागरिकों को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर लिए जाते हैं। विश्व बैंक दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता है। वर्ष 2015 की शेरधारिता समीक्षा के बाद विकासशील देशों में सुधार प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के एक भाग के तौर पर उनका वोट शेयर 50 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

## परिणाम आधारित सहायता से प्रभावशीलता और जवाबदेही प्राप्त किया जाना प्रत्येक बार संभव नहीं होता

सहायता प्रभावशीलता के संबंध में 2005 का पेरिस घोषणापत्र दानदाता और भागीदार राष्ट्र के नागरिकों और विधानमंडलों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने का एक प्रयास था। इसकी एक प्रतिबद्धता परिणाम-आधारित प्रबंधन को बढ़ाना थी। 'परिणामों द्वारा भुगतान' इस अभियान का एक भाग है, जो आदर्श तौर पर सहायता प्राप्त करने वाले देशों को ज्यादा स्वायत्ता प्रदान करने के साथ ही प्रक्रियाओं से हटकर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। व्यावहारिक तौर पर चीजें अधिक जटिल हैं।

परिणाम आधारित कार्यक्रमों का लक्ष्य परिणाम और प्रभाव होता है, यह उन पूर्व की शर्तों की तरह नहीं है जिनमें सहायता को नीतियां स्वीकार करने के साथ जोड़ा गया है उनके कई प्रारूप होते हैं। विश्व बैंक के परिणाम आधारित वित्त पोषण कार्यक्रम सवितरण को प्रत्यक्ष तौर पर परिणामों से जोड़ा गया है। इसका एक बड़ा शिक्षा उदाहरण यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में छात्र/अध्यापक अनुपात के संकेतकों सहित शिक्षा कार्यक्रम है, जिसमें पढ़ने संबंधी कौशलों का भी विकास हुआ है।

कुछ कार्यक्रमों में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के साथ भी अनुबंध किया गया है। दानदाता प्रति विद्यार्थी सेवा प्रदान करने की लागत और कई बार विविध प्रोत्साहन-आधारित भुगतानों को भी शामिल करता है। चुनौती कोष संगठनों को सहायता आवंटन करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसका लक्ष्य प्रदाता की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। यूनाइटेड किंगडम विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा चुनौती कोष विकास शिक्षा क्षेत्र में इस तरह का सबसे बड़ा उदाहरण है।

ऐसे कार्यक्रमों के कुछ मूल्यांकन किए गए हैं। प्रक्रिया-विधि मूल्यांकन में 'प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट' उपकरणों को भी शामिल किया गया है, जिनसे यह पता चला है कि आशा के विपरीत परिणाम ज्यादातर संस्थागत स्तर पर प्राप्त किए गए थे न कि परिणाम स्तर पर। इसके अतिरिक्त, प्रभाव मूल्यांकन को परिणाम आधारित कार्यक्रमों में किए गए बदलावों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ऐसा आंशिक तौर पर इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादातर कार्यक्रमों में कई परिणामों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, भुगतान दृष्टिकोण के प्रभाव संबंधी निष्कर्षों के लिए जटिल प्रयास किए गए हैं। अंत में आंकड़े उपलब्ध करवाने और परिणाम दर्शाने में समय लगता है। दानदाता वर्तमान में प्रमाण आधार को बेहतर बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं।

उपलब्ध प्रमाण कुछ प्रश्नों की ओर इशारा करते हैं। बाहरी प्रोत्साहनों के लिए अत्यधिक दबाव बनाए जाने से प्रदाता की स्वाभाविक प्रेरणा प्रभावित हो सकती है। चूंकि सहायता का स्तर अनिश्चित है, इसलिए इसे प्राप्त करने वाले भी जोखिम मान कर चलते हैं, जिसमें युक्तिसंगत होने के भाव को कम करके आंका जाता है। सहायता प्रदाताओं को परिणाम-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से नई खोज करने की स्वायत्ता प्रदान करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ने की संभावना होती है, परंतु यदि सहायता प्रदाताओं को भुगतान के लिए परिणाम सुनिश्चित करना हो तो वे विश्वसनीय प्रणालियों में परिवर्तन करने के इच्छुक नहीं होते।

मापने योग्य और किफायती लागत प्रमाणित किए जाने वाले संकेतकों का विकास करना कठिन कार्य है। संकेतकों को दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। समानता की अनदेखी करने वाले अनुपयुक्त संकेतक सबसे आसानी से उपलब्ध प्राप्तकर्ताओं को लक्षित करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, परिणामों के आधार पर भुगतान किए जाने से देश का स्वामित्व कम हो सकता है, चूंकि इस दृष्टिकोण का उद्भव दानदाता देशों में होता है और यह हमेशा देश की प्रणालियों के अनुरूप नहीं होता। दानदाता प्रायः गैर-सरकारी सहायता प्रदाताओं के पक्ष में कार्य करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए निवेश की अनदेखी करते हैं। परिणामों के आधार पर सहायता वितरण करने से संसाधनों के आवागमन के बारे में अनुमान लगाने में भी व्यवधान पैदा होता है। वास्तव में, यह दृष्टिकोण वहां श्रेष्ठ ढंग से कार्य कर सकता है जहां इसकी आवश्यकता सबसे कम होती है: ऐसी शिक्षा प्रणालियां जहां प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख हो और सुसंबद्ध उद्देश्य हो और जिसमें जोखिम लेने का साहस हो।

“ परिणाम आधारित वित्त-पोषण में प्रयुक्त संकेतकों को दीर्घावधि लक्ष्यों के साथ अवश्य समायोजित किया जाना चाहिए, और इक्विटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ”

# जवाबदेह गैर – सरकारी, लाभ कमाने वाले कार्यकर्ता

गैर-सरकारी, लाभ कमाने वाले कार्यकर्ता प्रमुख शिक्षा और आनुशंगिक सेवाएं जैसे पोषण कार्यक्रम और अनुदेशात्मक सामग्री दोनों प्रदान करते हैं। शिक्षा में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उन्हें प्रभावी तौर पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

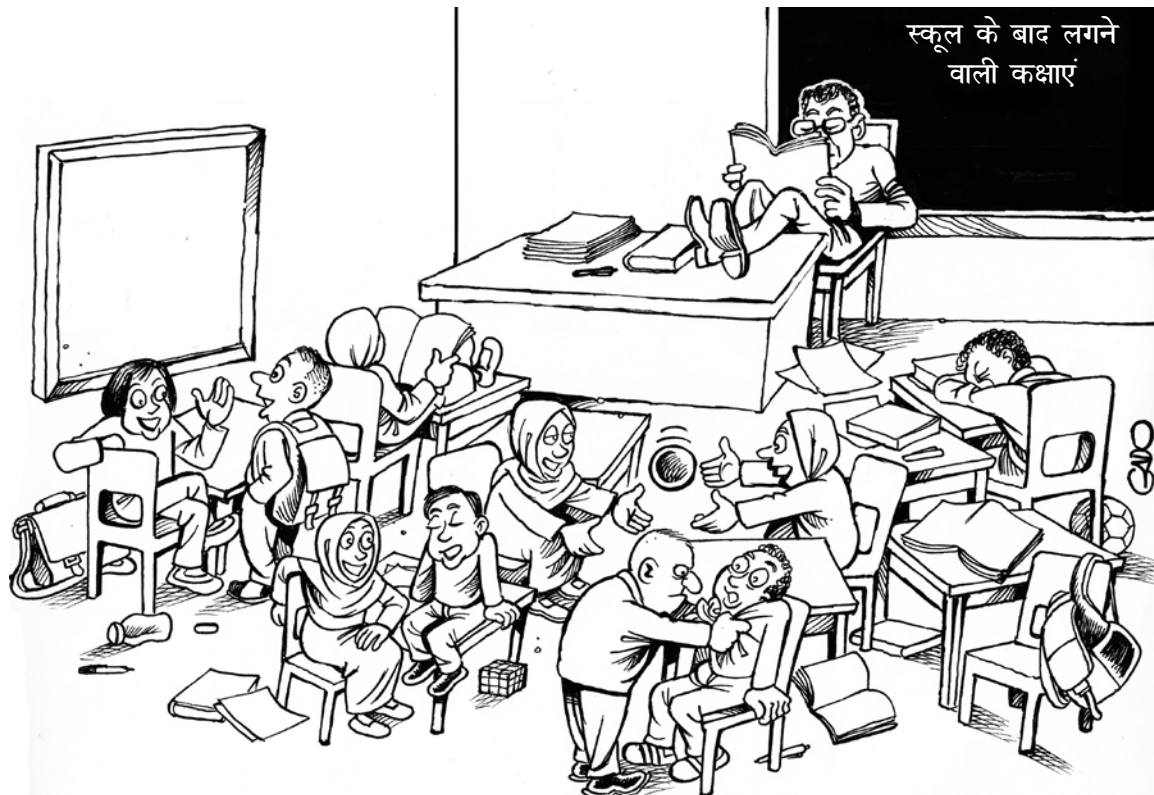
## प्रभावी स्कूल पोषण कार्यक्रमों के लिए सरकार की निगरानी आवश्यक है

स्कूल भोजन विश्व में सबसे ज्यादा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का रूप है। पांच में से एक बच्चा रोजाना स्कूल में भोजन करता है। कई देशों में, भोजन प्रदान करने का कार्य आंशिक अथवा पूर्ण तौर पर गैर-सरकारी कंपनियों को ठेके पर दिया गया है, इसे प्रभावी बनाने के लिए, गैर-सरकारी अनुबंध के संबंध में स्पष्ट सरकारी और गैर-सरकारी उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और पर्याप्त वित्त-पोषण होना चाहिए। प्रभावी सरकारी निगरानी यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकती है कि भोजन प्रदान करने वालों का लक्ष्य जरूरतमंद होना चाहिए। चिली और घाना में, सम्पूर्ण स्कूल पोषण आपूर्ति श्रृंखला को आऊटसोर्स किया गया है। परंतु, जबकि चिली के पोषण कार्यक्रम की बेहतर निगरानी करते हुए इसका लक्ष्य गरीब विद्यार्थियों को रखा गया है, घाना में भोजन का लक्ष्य उपयुक्त तौर पर गरीब समुदायों को नहीं रखा गया है, इसमें काफी ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप है और निगरानी के लिए सरकारी निधियां अपर्याप्त हैं।

“ कई देशों में, भोजन उपलब्ध कराने का कार्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से गैर-सरकारी कंपनियों को ठेके पर दिया गया है ”

## गैर-सरकारी (निजी) शिक्षण, शिक्षा समानता को प्रभावित कर सकता है

गैर-सरकारी शिक्षण एक वैश्विक घटनाक्रम है जिसमें अजरबैजान, चीन और स्पेन जैसे विविध देशों के सर्वेक्षण में कम से कम आधे उच्च स्कूलों के विद्यार्थी शामिल पाए गए हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, वर्ष 2014 में अनुमानित तौर पर 81 प्रतिशत प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों और 56 प्रतिशत उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने गैर-सरकारी स्तर पर शिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2022 तक इसका वैश्विक व्यापार 227 अमेरिकी डालर होने का अनुमान है, गैर-सरकारी शिक्षण विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ाने के साथ ही घरेलू बजट को बिगाड़ सकता है। सरकार मुख्यतः उपभोक्ता को सूचना प्रदान करके और मानकों के विकास के लिए स्कूलों के साथ भागीदारी और अध्यापक संघों के साथ कार्य करते हुए जवाबदेही को बढ़ावा देती है। हांगकांग, चीन में ट्यूटोरियल केन्द्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। इससे पंजीकृत केन्द्रों की ऑनलाइन सूची के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और गैर-पंजीकृत केन्द्रों को अभियोजित किया जाता है।



“ निजी ट्यूटोरिंग के वैश्विक बाजार के 2022 तक 227 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचने की संभावना है ”

अध्यापकों को ट्यूटोरिंग (शिक्षण) प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने से हितों का टकराव हो सकता है। नेपाल में, अध्यापकों ने ट्यूटोरिंग की मांग बढ़ाने के लिए स्कूलों में कम पाठ्य सामग्री को पूरा किया। हालांकि, कई अध्यापक कम वेतन को पूरा करने और पर्याप्त शिक्षण समय की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट ट्यूटोरिंग प्रदान करते हैं। कुछ देशों में प्राइवेट ट्यूटोरिंग में शामिल अध्यापकों को अभिशासित करने के लिए विनियम बनाए गए हैं। जार्जिया में 2010 की अध्यापक नैतिक संहिता में अध्यापकों को अपने ही विद्यार्थियों की ट्यूटोरिंग करने से हतोत्साहित किया गया है, जबकि जापान में पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूटोरिंग पर रोक लगाई गई है। इसके विपरीत, उजबेकिस्तान में अध्यापकों को अपने ही विद्यार्थियों के ट्यूटर बनने की अनुमति प्रदान की गई है।

## सरकारों और सीएसओ को अनुदेशात्मक सामग्री प्रदाताओं को जवाबदेह बनाना चाहिए

कई सरकारें प्रकाशन और वितरण लागत कम करने के लिए गैर-सरकारी पाठ्य-पुस्तक प्रदाताओं का उपयोग करती हैं। कुछ सरकारी-निजी भागीदारी प्रणालियां भी लागत प्रभावी रही हैं, युगांडा में ऐसी ही प्रणाली से पाठ्यपुस्तकों की लागत दो-तिहाई तक कम हुई है। स्पष्ट उत्तरदायित्व, मीडिया कवरेज, सरकार की प्रतिबद्धता और सामाजिक सक्रियता पाठ्य-पुस्तक परिक्षण और विकास को बेहतर बना सकती है। फिलीपींस में वर्ष 2002 और 2005 के बीच सरकार की कार्रवाई और सिविल सोसायटी की सहभागिता ने पाठ्य-पुस्तक वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, औसत मूल्य को कम करने तथा विकास तथा आपूर्ति समय को आधा करने में सहायता की है। सीएसओ भी पाठ्य-पुस्तक विषय-वस्तु की निगरानी में सहायता कर सकते हैं। टेक्सास में, जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई ने प्रकाशकों को ऐसी पाठ्य-पुस्तकों को संशोधित करने के लिए बाध्य किया, जिनमें जलवायु परिवर्तन के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था।

गैर-सरकारी निगम केवल अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं, जो शिक्षा जैसा नागरिक बेहतरी का कार्य करने में नागरिकों के प्रति जवाबदेही के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। व्यक्तियों, बड़ी संख्या में शिक्षा सेवा प्रदाता कंपनियों को शिक्षा बाजार में एकाधिकार स्थापित करने से रोकने के लिए 'एंटीट्रस्ट लॉसूईट' दाखिल किए गए हैं। इसके प्रत्युत्तर में, कंपनी ने आंतरिक जवाबदेही पहल प्रारंभ की है, जिसके परिणामों के बारे में वर्ष 2018 में औपचारिक रिपोर्टिंग प्रारंभ किए जाने के बाद जानकारी मिलेगी।

सरकारों ने विद्यार्थियों और विद्यालयों के बीच 'डिजिटल विभाजन' को दूर करने के लिए प्राइवेट टैबलेट और लैपटॉप प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है। हालांकि, घटिया खरीद और अनुबंध करने के कारण ऐसी कई पहलों से विक्रेताओं को लाभ हुआ है न कि विद्यार्थियों को, जैसाकि थाइलैंड में हुआ है। भारत ने लक्ष्यों को पूरा किए बिना ही वर्ष 2015 में अपने आकाश कार्यक्रम का परित्याग कर दिया। इसी दौरान, विक्रेता डाटाविंड ने कम लागत के टैबलेट नवाचार में अग्रणी स्थान बना लिया।

“ गैर-सरकारी निगम केवल अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं, जो शिक्षा जैसा नागरिक बेहतरी का कार्य करने में नागरिकों के प्रति जवाबदेही के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं ”



यदि बाजार का एकाधिकार हो जाए तो सरकारों का उन पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रह जाता।

अमेजन राज्य, ब्राजील में  
मनाउस के नजदीक एक  
स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थी

चित्रण: जीईएम रिपोर्ट / एंड्रेस पासकोई



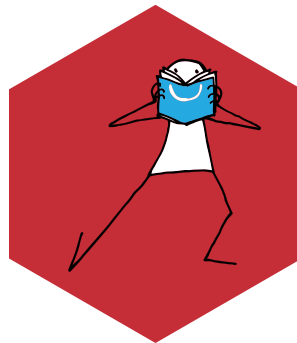
# एसडीजी4 में निगरानी प्रगति

स्थायी विकास कार्यसूची से शिक्षा में एक नई निगरानी संरचना का सूत्रपात हुआ है। इसका उद्देश्य सही मायनों में वैश्विक, लक्ष्यों की महत्वाकांक्षा के अनुरूप और शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणालियों की परम्परागत सीमाओं से आगे बढ़ना है। अभी भी, जैसाकि 2016 जीईएम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, इसका कोर शिक्षा की बाहरी परत और जीवन पर्यन्त शिक्षा प्रश्नों, विशेष तौर पर स्थायी विकास से जुड़े हुए प्रश्नों, पर बहुत कम प्रभाव है।

इसके बावजूद, नई निगरानी प्रणाली का फोकस मानकों के निर्धारण हेतु संसाधनों के व्यापक संग्रह तथा समानता, गुणवत्ता और शिक्षण के लिए प्रासंगिक उपकरणों को लागू करने की मांग पर आधारित है। वास्तविक अर्थों में देशों की सहभागिता वाले समन्वित प्रयास महंगे हैं। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक कार्यों जैसे सार्विकी और अनुसंधान के वित्त-पोषण हेतु अत्यधिक कम खर्च के इस दौर में यह कार्य प्रारंभ करना आसान नहीं है।

कुछ संस्थागत प्रतिष्ठानों, विशेष तौर पर एसडीजी4 - शिक्षा 2030 के लिए संकेतकों संबंधी तकनीकी सहायता समूह, को स्थापित किया गया है, जिसका सचिवालय यूनेस्को सार्विकी संस्थान में है। इसका उद्देश्य संकेतकों की परिभाषा के संबंध में आम सहमति बनाना और प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय स्वामित्व स्थापित करना है। फिर भी, जैसाकि समीक्षा में पता चलता है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता है कि सभी संकेतक सुपरिभाषित हों और उनकी निगरानी हो।

## लक्ष्य 4 सभी के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना



10 लक्ष्य





## लक्ष्य 4.1

# प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

लक्ष्य 4.1 के लिए वैश्विक संकेतक प्रारंभिक ग्रेड, प्राथमिक स्तर की समाप्ति, और निम्न माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर पढ़ने और गणित में दक्षता का उपाय है। अभी तक दक्षता के लिए कोई वैश्विक मानक नहीं है, हालांकि यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा समन्वित शिक्षा की निगरानी हेतु वैश्विक गठबंधन के माध्यम से इस दिशा में अभी हाल ही में कदम उठाए गए हैं।

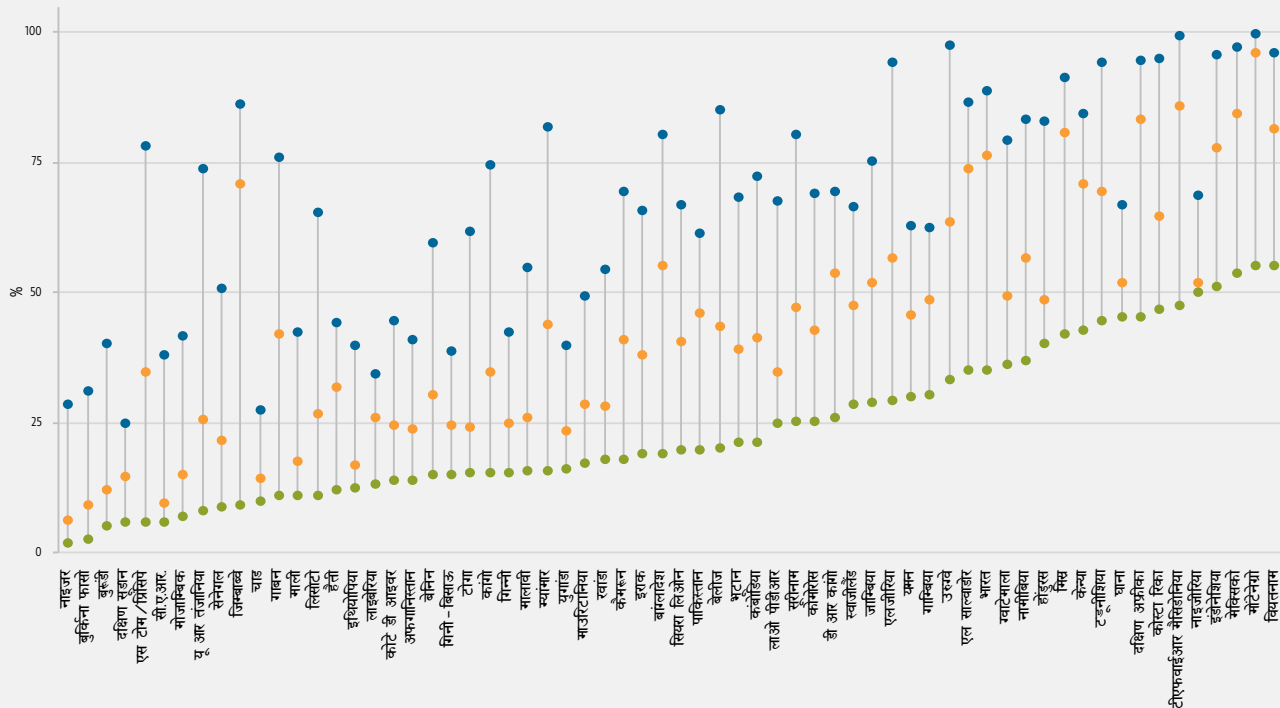
मौटे तौर पर आधे देश प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर पढ़ने और गणित में राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन करते हैं। फिर भी, 2017 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकनों में भाग लेने वाले केवल 25 प्रतिशत से 38 प्रतिशत देशों ने ही वैश्विक संकेतक के लिए डाटा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, परिणामों की जानकारी प्रत्येक सर्वेक्षण में परिभाषित दक्षता स्तरों के अर्थों में प्रदान की जाती है, जो तुलनीय नहीं है।

ई9 समूह के देशों, एसडीजी4 की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समूह जो विश्व की आधी जनसंख्या के लिए जवाबदेह है, की शिक्षा परिणामों की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया और मेक्सिको ने तीन शिक्षा स्तरों पर कुछ आंकड़े प्रदान किए हैं जबकि बांग्लादेश, चीन, भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान ने किसी भी स्तर पर इस संकेतक के लिए आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी 9 देश या तो अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भाग लें अथवा रिपोर्टिंग करने के लिए अपने राष्ट्रीय मूल्यांकनों का प्रयोग करें, बशर्ते कि वे गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों।

## चित्र 8:

लगभग आधे देशों में दो में से एक से भी कम युवा ने माध्यमिक स्कूल की शिक्षा पूरी की है।

चयनित देशों में शिक्षा स्तर द्वारा पढ़ाई पूरी करने की दर, 2010-2015



स्रोत: घरेलू स्तर के सर्वेक्षणों का प्रयोग करते हुए जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण

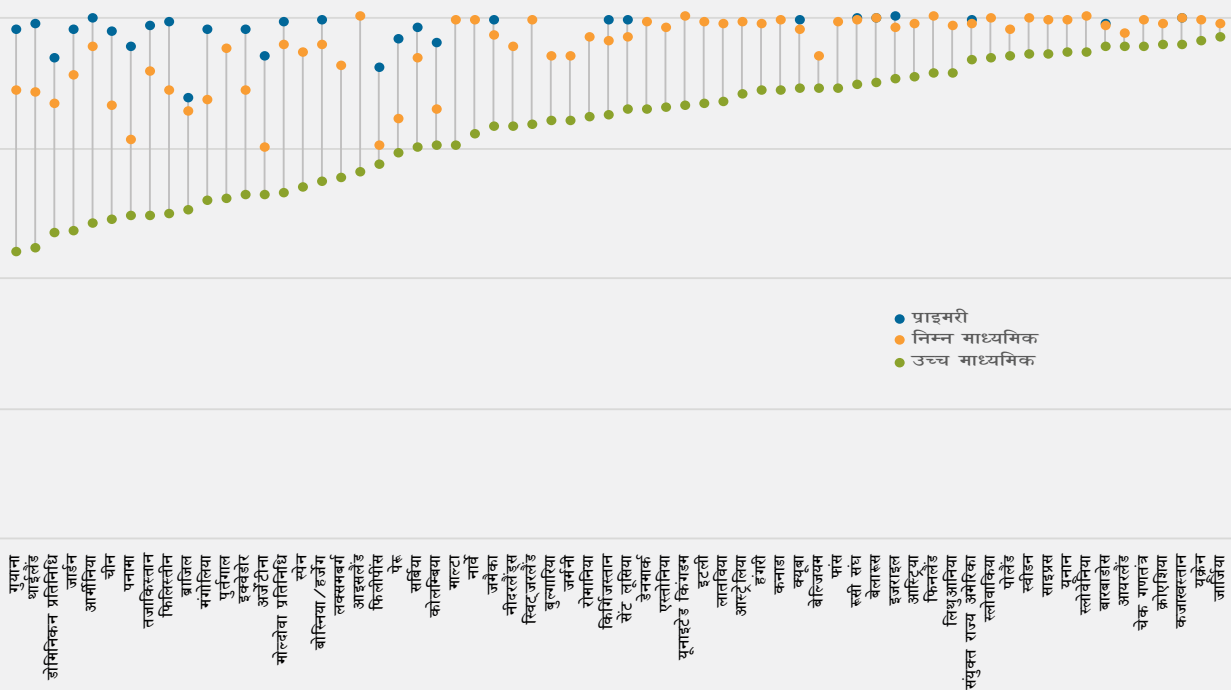


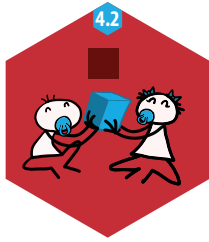
इन चुनौतियों के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकनों के आंकड़ों से पता चलता है कि कई देशों में, विशेष तौर पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कई विद्यार्थी न्यूनतम दक्षता स्तरों को पूरा नहीं करते हैं। चाड, कुवैत और निकारगुआ में गणित में, प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर एक-तिहाई विद्यार्थी न्यूनतम बेंचमार्क को भी पूरा नहीं कर पाए तथा अलजीरिया, इंडोनेशिया और पूर्व युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसीडोनिया में निम्न माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर एक-तिहाई विद्यार्थी न्यूनतम बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाए। पढ़ने में, कैमरून, कांगो और टोगो में प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर और अलबानिया, जार्जिया और लेबनान में निम्न माध्यमिक स्तर पर आधे विद्यार्थी न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर पाए।

ये बेंचमार्क उन विद्यार्थियों में उपलब्धि को नहीं आंकते, जो संबंधित ग्रेड में पहुंचे हैं। यह मानकर कि जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है अथवा कभी दाखिला नहीं करवाया, वे बेंचमार्क को पूरा नहीं करते, न्यूनतम दक्षता स्तर तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों का और नीचे समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आयु समूह के 264 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल शिक्षा से बाहर थे। वर्ष 2000 के दशक के पूर्वार्द्ध में गिरावट के बाद वर्ष 2008 से प्राथमिक शिक्षा और 2012 से निम्न माध्यमिक तथा 2013 से उच्चतर माध्यमिक में स्कूल न जाने वालों की दर स्थिर रही है।

स्कूल में जाने का अर्थ स्नातक होने की गारंटी नहीं है। 2010-2015 के लिए घरेलू स्तर के सर्वेक्षण के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा दर 83 प्रतिशत, निम्न माध्यमिक स्तर के लिए 69 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए यह दर 45 प्रतिशत थी। वर्ष 2010-2015 के बीच 128 देशों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर, जो माध्यमिक विद्यालय आयु की आधी वैश्विक जनसंख्या को दर्शाते हैं, 40 देशों में चार में से एक से भी कम और 60 देशों में दो में से एक से भी कम युवा ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी की है। केवल 14 देशों में यह शिक्षा पूरी करने की दर कम से कम 90 प्रतिशत थी। (चित्र 8)

बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर रोक लगाने का एक तरीका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना है। लगभग 70% देशों, परंतु सब-सहारा अफ्रीका में केवल 40% देशों में, कम से कम 9 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। वैश्विक स्तर पर, पांच में से एक से भी कम देश 12 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। लेटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (देशों का 47%) तथा कोकासस और मध्य एशिया (देशों का 38%) में यह गारंटी ज्यादातर सामान्य है, जबकि किसी भी निम्न आय वाले राष्ट्र ने ऐसा प्रावधान नहीं किया है।





## बाल्यावस्था

बाल्यावस्था शिक्षा के संबंध में, विश्व भर के केवल एक-तिहाई देशों ने कानूनी तौर पर केवल एक वर्ष के लिए निःशुल्क प्रावधान किया है, 21 प्रतिशत देशों ने एक वर्षीय अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है और 17 प्रतिशत देशों ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दोनों का प्रावधान किया है।

इसके बावजूद, वर्ष 2015 में प्राथमिक शिक्षा प्रवेश आयु के स्तर के एक वर्ष 69% छोटे बच्चों ने संभावित अध्यापन में भाग लिया, जो लक्ष्य 4.2 का प्रथम वैश्विक संकेतक है। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी तथा लेटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के क्षेत्रीय भागीदारी 95% रही जबकि सब-सहारा अफ्रीकी देशों में यह भागीदारी 42% थी। कई देशों में वर्ष 2000 के बाद से दाखिले में व्यापक वृद्धि हुई है। (चित्र 9)

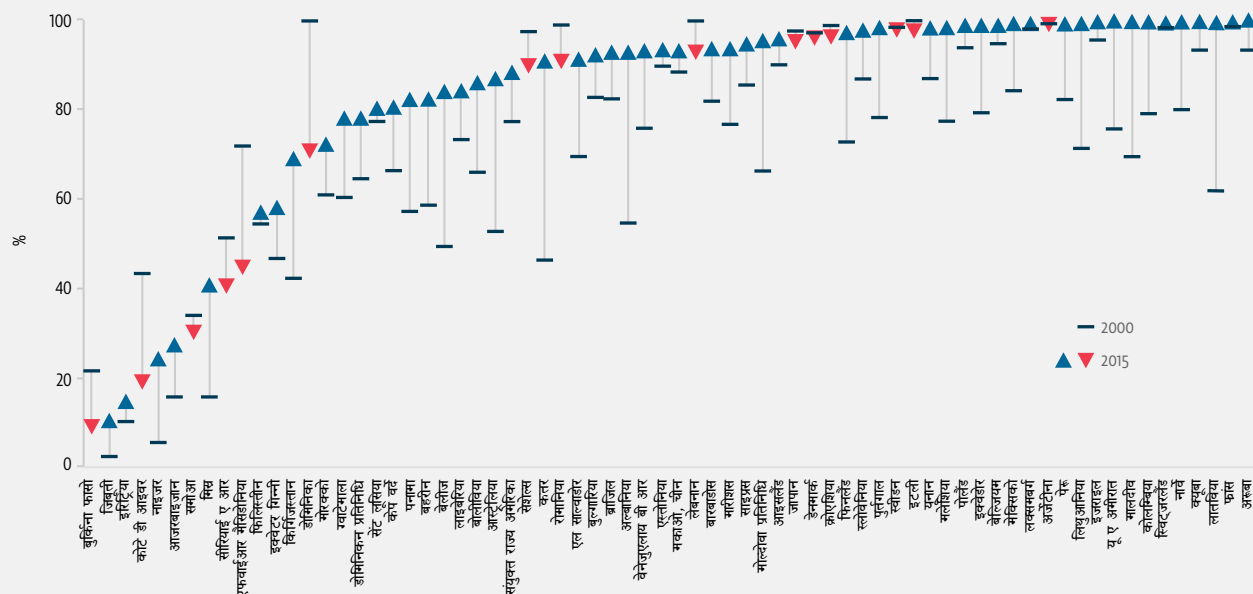
अधिकांश दुनिया में, शुरूआती बाल शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। 2010 और 2015 के बीच कम और मध्यम आय वाले 52 देशों में, सबसे गरीब परिवारों में प्रत्येक 5 परिवारों के 3 से 4 साल के लगभग दो बच्चों ने व्यवस्थित शिक्षा कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि सबसे अमीर 5 परिवारों में से दस बच्चों ने संगठित शिक्षा कार्यक्रम में भाग लिया। सर्बिया और नाइजीरिया में, अमीर बच्चों के लिए यह दर 80% थी और गरीब बच्चों के लिए यह दर 10% से अधिक नहीं थी।

ग्रामीण-शहरी उपस्थिति दर में अंतर, तुनिशिया और तुर्कमेनिस्तान में 40 प्रतिशत के अंक को पार कर गया, जबकि बांग्लादेश, जमैका, मेक्सिको, फिलिस्तीन, सेंट लूसिया, साओ टोम और प्रिंसिपे और थाईलैंड में ग्रामीण बच्चों में समानता थी और यहां तक कि ग्रामीण बच्चे शहरों की तुलना में थोड़ा अधिक फायदे में थे।

### चित्र 9:

कई देशों में प्रारंभिक बाल शिक्षा भागीदारी तेजी से बढ़ी है

व्यवस्थित शिक्षा में भागीदारी दर (सरकारी प्राथमिक दाखिले की आयु से एक वर्ष पूर्व), चयनित देश, 2000 - 2015



स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

दूसरे वैश्विक सूचक का उद्देश्य बच्चों का बचपन से ही विकास करना है, लेकिन विचारों में यह भिन्नता बनी रहती है कि स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और सीखने-सीखाने के आयाम क्या होने चाहिए। यूनिसेफ के अनुसार, शुरुआती बाल विकास सूचकांक, जो आंकड़ों का मुख्य स्रोत है, के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कांगो, मारिटानिया और नेपाल के लोकतांत्रिक गणराज्य सहित देशों में 36 से 59 माह के दो-तिहाई से कम बच्चों का ही विकास हो रहा था। परोक्ष रूप से आकलन की जा रही इस प्रणाली को आगे और विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

घर का माहौल बाल्यकाल के विकास पर गहरी छाप छोड़ता है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग आधे देशों में 36 से 59 माह के कम से कम एक-तिहाई बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जहां उनकी देखभाल करने वाले शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल के लिए तैयार करने के लिए चार या अधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते, जैसे तस्वीर वाली पुस्तकें पढ़ना, या उन्हें देखना, गाना गाना, गिनना या ड्राइंग करना। इस तरह के कार्यक्रमों में अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में गरीब परिवारों के बच्चों के शामिल होने की कम संभावना थी।



## तकनीकी, व्यावसायिक, उच्च स्तरीय और प्रौढ़ शिक्षा

लक्ष्य 4.3 के लिए वैश्विक संकेतक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में युवा और वयस्क भागीदारी दर है। श्रम बल सर्वेक्षण से आंकड़ों के स्रोत का पता चलता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ श्रम बल सर्वेक्षण, जिसमें दोनों औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में भाग लेने को शामिल किया गया, से पता चलता है कि महिलाओं और युवा लोगों के भाग लेने की संभावना अधिक रहती है। दुनिया के राष्ट्रों की एक दूसरे से तुलना करने और पूर्णता के लिए, दुनिया में कहीं भी श्रम बल सर्वेक्षण डिजाइन का एक आम माड्यूल विकसित करने की आवश्यकता है जिससे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

2015 में दुनिया भर में 6 करोड़ से अधिक माध्यमिक छात्रों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला लिया था - जो सभी माध्यमिक छात्रों का लगभग 10% है - जो मुख्यतः ऊपरी माध्यमिक स्तर में हैं। 2000 के बाद से अधिकांश क्षेत्रों में इस दर में थोड़ा परिवर्तन देखा गया, हालांकि प्रशांत क्षेत्र में काकेशस और मध्य एशिया में भागीदारी बढ़ी है जबकि प्रशांत में घटी है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में पुरुषों की प्रधानता रही है जबकि लड़कियों का नामांकन 43% रहा।

2015 में, 213 मिलियन छात्रों ने उच्च स्तरीय शिक्षा में दाखिला लिया। 2000 के बाद से, सकल नामांकन अनुपात उच्च मध्यम आय वाले देशों में लगभग 30 प्रतिशत अंक बढ़कर 17% से 46% तक पहुंच गया। हालांकि, काकेशस और मध्य एशिया उप सहरा अफ्रीका में नामांकन वृद्धि लगभग स्थिर रही। निजी नामांकन की हिस्सेदारी बढ़ रही है।

महिलाओं ने उच्च स्तरीय शिक्षा में दाखिला लेने में पुरुषों से आगे निकल गई हैं। उप सहरा अफ्रीका एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पुरुषों की तुलना में कम महिलाओं ने दाखिला लिया है। फिर भी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की डिग्री पूरी करने में महिलाएं पुरुषों से पिछड़ रही हैं।

घरेलू सर्वेक्षणों का इस्तेमाल माध्यमिक शिक्षा के बाद प्राप्त की जाने वाली शिक्षा में व्याप्त असमानता को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में लगाए गए नए अनुमान से पता चला है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 18 से 22 वर्ष के छात्रों की उपस्थिति दर अमीर पांच परिवारों में बढ़ी है जबकि सबसे गरीब पांच परिवारों में शून्य के करीब है। अल साल्वाडोर में, सबसे अमीर पांच परिवारों के 51% और सबसे गरीब परिवारों के 2% से कम बच्चों ने किसी न किसी रूप में माध्यमिक शिक्षा में

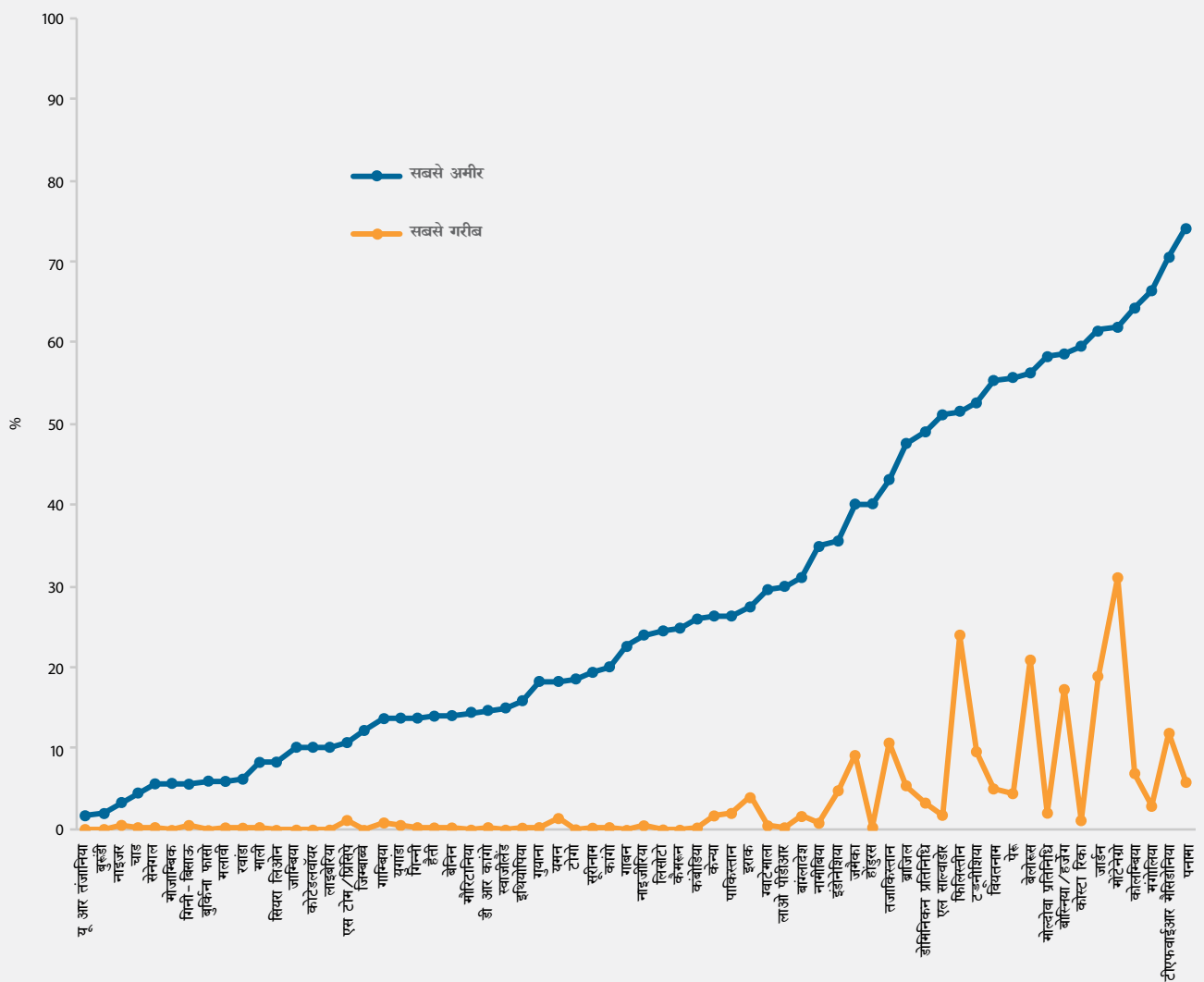
“ 2015 में दुनिया भर में 6 करोड़ से अधिक माध्यमिक छात्रों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला लिया था, और 21 करोड़ 30 लाख छात्रों ने उच्च स्तरीय शिक्षा में दाखिला लिया है ”

दारखिला लिया, जबकि मंगोलिया में, यह प्रतिशत 67% और 3% था, जो यह सुझाता है कि कई मध्यम आय वाले देशों के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा उपलब्ध कराने की नीतियां लागू करने की नितांत आवश्यकता है (चित्र 10)।

कम और मध्यम आय वाले देशों में वयस्क आबादी का एक बड़े हिस्से ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पूरी नहीं की है। यहां तक कि उनके बुनियादी शिक्षा पूरी करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में वापस जाने की भी कोई संभावना नहीं है। केन्या में, दो वयस्कों में से केवल एक ने ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा पूर्ण की है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में दारखिला कराने में वयस्कों का हिस्सा केवल 3% है। इन आंकड़ों में औपचारिक प्रणाली के बाहर शिक्षा जारी रखने वाले वयस्कों का ब्यौरा नहीं है।

चित्र 10:

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे गरीब लोगों के लिए शायद ही उच्च माध्यमिक शिक्षा के कोई अवसर उपलब्ध होते हैं  
संपन्न, चुनिंदा देशों में 2010-2015 के दौरान माध्यमिक शिक्षा के बाद उपस्थिति दर



स्रोत: जीईएम रिपोर्ट टीम की गणना परिवार सर्वेक्षणों पर आधारित है।



# कार्य के लिए कौशल

काम के लिए ऐसे कौशल की पहचान करना, जो सभी संदर्भों में प्रासंगिक बना रहे, बेहद जटिल है, इसलिए लक्ष्य 4.4 के निगरानी ढांचे में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल साक्षरता कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसी विशेष कौशल के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने से नीति निर्माताओं का ध्यान उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों पर हो सकता है। आमतौर पर ये औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं होते।

कौशल प्राप्त करने का आकलन प्रत्यक्ष हो सकता है - लेकिन, महंगा - या अप्रत्यक्ष हो सकता है, उदाहरण के लिए घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों के माध्यम से। यूरोस्टेट आंकड़ों और ओईसीडी के अंतर्राष्ट्रीय वयस्क दक्षता आकलन कार्यक्रम (पीआईएएसी) के परिणामों का उपयोग करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपायों की तुलना करने से पता चला है कि दो प्रकार के उपाय सकारात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े थे, हालांकि निचले कौशल स्तर पर परस्पर-संबंध काफी अच्छे थे।

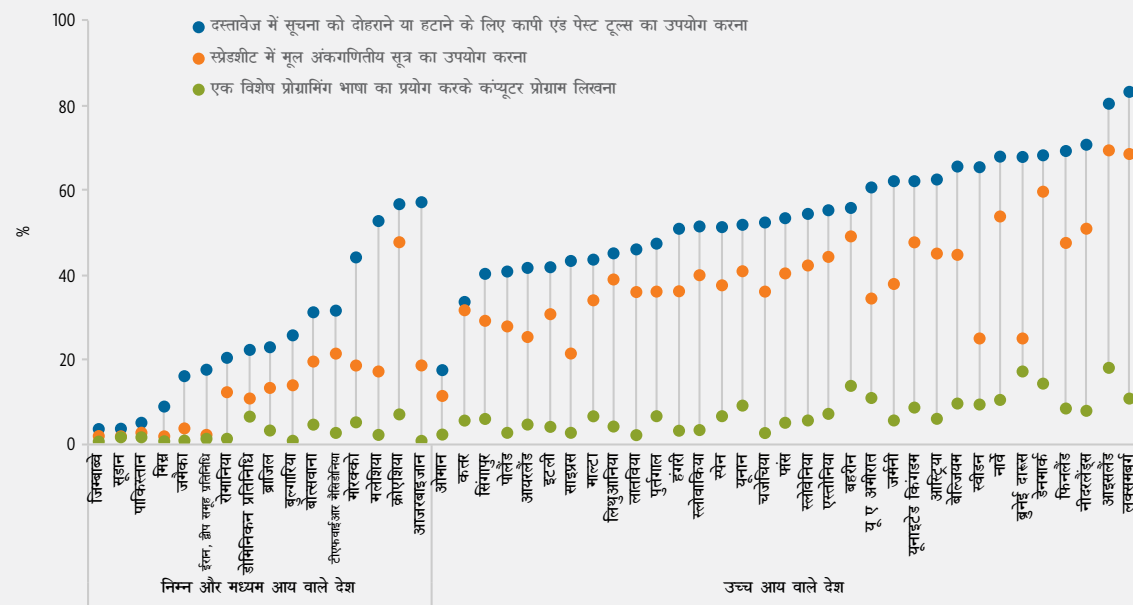
वैश्विक संकेतक पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वयस्क मुखिया को बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा भी प्राप्त नहीं थी। उदाहरण के लिए, सूडान और जिम्बाब्वे में केवल 4% वयस्क ही फाइलों को कॉपी-पेस्ट कर सकते थे (चित्र 11)।

और अधिक परिष्कृत कौशल के बारे में, देशों में काफी असमानता व्याप्त है। यूरोपीय संघ में, डेनमार्क में 14% की तुलना में केवल 1% बल्गेरियाई वयस्क कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। लिंग भेदभाव और असमानता भी अधिक है। चेक गणराज्य और हंगरी में, प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में 25 महिलाओं को प्रोग्रामिंग कौशल प्राप्त था। कुछ देशों ने साधारण कौशल में समानता प्राप्त कर ली थी: जैसे इटली, जर्मनी और नीदरलैंड में, प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में लगभग 75 महिलाओं को स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का उपयोग करने की जानकारी थी।

**चित्र 11:**

**निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी आईसीटी कौशल का प्रसार बहुत सीमित है**

वर्ष 2014-2016 के दौरान चुनिंदा देशों में विगत तीन महीनों में कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले वयस्कों का प्रतिशत



स्रोत: अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन डेटाबेस।



## निष्पक्षता

सतत विकास के एजेडे में व्यक्तिगत विशेषताओं, इनपुट और परिणाम, और शिक्षा के विभिन्न स्तरों में इक्विटी पर नज़र रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

दुनिया ने औसतन, उच्च स्तरीय शिक्षा को छोड़कर सभी स्तरों पर लिंग समानता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि, यह सभी क्षेत्रों और देश के आय समूहों या अलग-अलग देशों के स्तर पर सत्य नहीं है। केवल 66% देशों ने प्राथमिक शिक्षा में, 45% ने निम्न माध्यमिक शिक्षा में और 25% ने उच्च माध्यमिक शिक्षा में स्त्री-पुरुष समानता हासिल कर ली है।

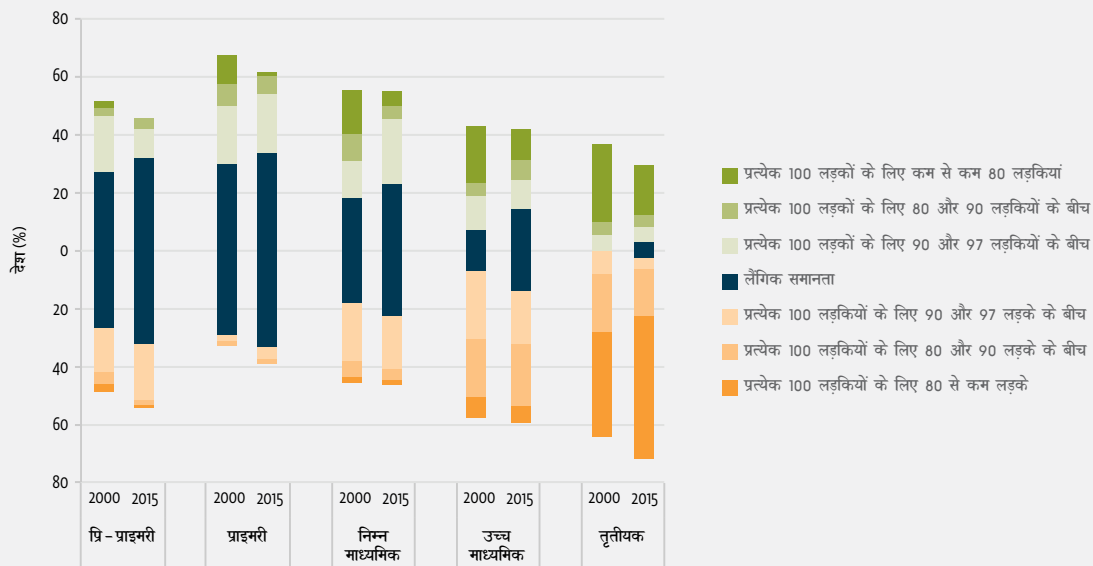
शिक्षा में स्त्री-पुरुष के बीच असमानता से समय के साथ प्रायः विषयों में पढ़ाने की पद्धति की भिन्नता का पता चलता है। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका और कॅरेबियन में और उप-सहारा अफ्रीका में कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्राथमिक विद्यालय के पूरा होने पर लड़कियों के लिए गणित के क्षेत्र में आगे को संभावनाएं नहीं हैं। निचले माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, देशों में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता औसत है, यद्यपि अलग-अलग देशों में शिक्षा का आकलन अलग-अलग प्रतीत होता है।

शैक्षिक प्रबंधन पदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। जापान में, निम्न माध्यमिक स्कूलों में 39% शिक्षक महिलाएं हैं, जिनमें से केवल 6% प्रधान शिक्षक हैं। जहाँ विभिन्न स्तरों के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहाँ नेतृत्व की भूमिका के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी स्तर के बढ़ने से घट जाती है: आस्ट्रिया में, प्राथमिक विद्यालय की 79% महिलाएं प्रमुख हैं, जबकि निम्न माध्यमिक विद्यालय केवल 32% महिलाएं प्रमुख हैं।

स्थान और संपत्ति दो महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके आधार पर गहन जांच की जाती है। 2010-2015 में, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न

चित्र 12:

देश बड़ी तेजी से स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से उच्च शिक्षा के स्तर पर चुनौती बनी हुई है। 2000 और 2015 के दौरान, सकल दारिद्र्य अनुपात के संबंध में स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक स्तर और शिक्षा स्तर के आधार पर देशों का प्रतिशत



स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रत्येक 75 किशोरों की तुलना में 100 शहरी किशोरों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। समानता सूचकांक के अनुसार गरीबों की हालत काफी खराब है: विश्व स्तर पर, सबसे गरीब पांच परिवारों में से 61 बच्चों ने निम्न माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी की थी जबकि सबसे अमीर ने 100 बच्चों ने ऐसा किया था। निम्न मध्य आय वाले देशों में और कम आय वाले देशों में प्रत्येक 100 बच्चों के लिए यह आंकड़ा 54 है और निम्न मध्य आय वाले देशों में यह आंकड़ा प्रत्येक 100 बच्चों के लिए 14 है। जबकि विश्व स्तर पर शिक्षा को पूरा करने की दर 69% थी, जिसमें से निम्न माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में केवल 12% सबसे गरीब पुरुष और सबसे गरीब महिलाएं 8% थीं।

इसके अलावा, घरेलू सर्वेक्षण में कई उपेक्षित वर्गों जैसे मौसमी मजदूर, बेघर लोग, शरणार्थी और संघर्ष वाले इलाकों में रहने वाली आबादी शामिल नहीं है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में 250 मिलियन लोग सर्वेक्षण की रूपरेखा के कारण छूट जाते हैं, और अन्य 100 मिलियन का प्रतिनिधित्व कम होता है, जिनमें गंदी बस्तियां भी शामिल हैं।

सभी देशों में भाषा की विशेषताओं की आसानी से तुलना नहीं की जा सकती लेकिन इसका समानता पर गहरा असर पड़ता है। कम से कम छह वर्षों तक छात्रों को पहली भाषा में दिए गए निर्देश से उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 21 देशों के नीति संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा से पता चलता है कि अधिकांश देश द्विभाषी शिक्षा नीति को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रेड 4 या 5 तक एक या अधिक स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाता है। लेकिन नीतियों को प्रायः संसाधनों की कमी या मुख्यतः शिक्षकों और अभिभावकों के विरोध की वजह से अक्सर लागू नहीं किया जाता है।

इस रिपोर्ट के नए विश्लेषण में छात्रों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा के प्रतिशत के अनुसार पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को वर्गीकृत करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या के आँकड़े, भाषा जनसांख्यिकी और भाषा संबंधी नीतियां शामिल हैं। विश्लेषण से यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रूनोई दारुससलाम और इंडोनेशिया में, 25% से कम बच्चों को उनके घर में बोली जाने वाली भाषा में शिक्षा उपलब्ध थी, जबकि वियतनाम में लगभग 90% को यह सुविधा प्राप्त थी।

विविध राष्ट्रों में शिक्षा का जायजा लेने से भाषा की समस्या का समाधान करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन (टीआईएमएसएस) में 2015 के रूज़ान से पता चला है कि भाग लेने वाले देशों में चौथी कक्षा के 78% छात्रों ने हमेशा या लगभग हमेशा घर पर बोली जाने वाली भाषा में बात की है।

विकलांगता के संबंध में, दोहरी चुनौती जनसंख्या में व्याप्त असमानता और संबंधित शैक्षिक नुकसान का आकलन करना है। दो जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में, अनुमान के अनुसार विकलांगता दर (कंबोडिया में 2.1% और मालदीव में 9.7%) में व्याप्त व्यापक अंतर को भी स्कूल उपस्थिति में विकलांगता के प्रभाव का अलग से अनुमान लगाने के लिए परिलक्षित किया गया था: मालदीव में विकलांग बच्चों की प्राथमिक उपस्थिति दर 85% थी, जबकि दूसरों की 94% थी, जबकि कंबोडिया में संबंधित दर क्रमशः 43% और 93% थी।

## वंचित समूहों की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता।

*हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा*, एसडीजी के बुनियादी दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि 'सभी लोग, चाहे उनका लिंग, आयु, जाति या नस्ल कुछ भी हो, और विकलांग, प्रवासियों, स्वदेशी लोगों को 'आजीवन सीखने के अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए। देशों को एसडीजी की प्रगति की निगरानी करने के लिए आंकड़े जमा करने चाहिए, तथा साथ ही उन्होंने जो सुधार किया है, में मानव अधिकार सम्मेलनों का अनुपालन करना चाहिए। व्यवहार में, हालांकि, देशों द्वारा काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं और उपेक्षित जनसंख्या द्वारा चिंता भी व्यक्त की गई है।

उपेक्षित समूहों के आंकड़ों का संग्रह करने से निजता का उल्लंघन हो सकता है। आंकड़ा सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत जातीय और धार्मिक संबंधों की जानकारी को संवेदनशीलता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वीडन सहित कुछ देश जातीयता पर आंकड़े एकत्र नहीं करते यद्यपि इसमें कुछ भी प्रतिबंधित करने लायक नहीं है। अन्य लोग व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य आंकड़ों का संग्रह नहीं करते, बल्कि अज्ञात स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के संग्रह को मान्यता देते हैं। एक-तिहाई से अधिक जनगणना प्रश्नावली में जातीय वर्गीकरण का कोई फार्म शामिल नहीं है।

जातीय अल्पसंख्यक आंकड़ों का आबादी को अलग करने में खास तौर पर दुरुपयोग किया गया है, उपेक्षित समूह स्वयं अपने आंकड़े प्रदान करने में अनिच्छुक हो सकता है। भेदभाव के डर से, यूरोप में रोमा लोग अक्सर जनगणना पर विश्वास नहीं करते। विकलांग लोग कलंक लगने के डर से दोषारोपण अपनी रिपोर्ट नहीं देते। इसके अलावा, सरकारें इस बात से चिंतित होकर आंकड़े एकत्र करने से बचती हैं कि इसके परिणाम उनकी नीतियों की कमियों को प्रतिबिंबित करेंगे या इससे जनसंख्या में तनाव पैदा होगा।

“  
दुनिया भर में 250 मिलियन लोग सर्वेक्षण की रूपरेखा के कारण छूट जाते हैं, और अन्य 100 मिलियन का प्रतिनिधित्व कम होता है  
”

विकलांगता, धर्म और अन्य श्रेणियों की कई परिभाषाओं को देखते हुए नुकसान का जायजा लेना बहुत कठिन है। अधिकांश अलग-अलग श्रेणियां, जिनमें नस्लीय और जातीय लोग भी शामिल हैं, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण या विकास के अनुसार विकसित होती हैं, जिसके कारण समय के साथ परिणामों की तुलना करना कठिन हो जाता है। यद्यपि आंकड़े एकत्रित करते समय जातीय समस्याओं को हल करने के लिए नुकसान की खुद जायजा लेना लाभदायक होता है, लेकिन व्यक्ति सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते। नुकसान का ऊपरी दृष्टि से जायजा लेने से भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं क्योंकि ये देखने वाले के एकतरफा दृष्टिकोण पर आधारित हो सकती हैं।



## साक्षरता और संख्यात्मकता

2000 और 2015 के बीच, प्रौढ़ साक्षरता दर 81.5% से बढ़कर 86% हो गई, हालांकि उप-सहारा अफ्रीका में यह 64% बनी हुई है तथा निम्न आय वाले देशों से यह मात्र 60% से कम है। साक्षरता कौशल के बिना वयस्कों की संख्या में मात्र 4% घटकर 753 मिलियन रह गई है।

इसके विपरीत, बिना साक्षरता कौशल वाले युवाओं की संख्या में 27% तक की गिरावट आई है। फिर भी, ऐसे 100 मिलियन से अधिक युवा लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, जबकि उप-सहारा अफ्रीका और निम्न आय वाले देशों में चार में से एक से अधिक युवा शामिल हैं।

“  
**ऐसे 100 मिलियन से अधिक  
 युवा हैं जो पढ़ नहीं सकते**  
 ”

घरेलू भाषा और पढ़ाई के माध्यम एक न होने से उप-सहारा अफ्रीका में साक्षरता कौशल गति धीमी होने में निर्णायक भूमिका अदा की है। इस रिपोर्ट के नए विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 36 देशों में, स्कूल में कक्षा पांच तक के केवल आधे वयस्क ही पूरा वाक्य पढ़ सकते थे। हालांकि, जिन वयस्कों की शिक्षा का माध्यम उनकी घरेलू भाषा में था, उनमें से 69% वयस्क वाक्य पढ़ पाए थे, जबकि औपनिवेशिक या मिश्रित भाषा प्रणाली में यह प्रतिशत केवल 41% था।

पारंपरिक, बड़े पैमाने पर स्वयं रिपोर्ट करने, विरोधाभासी साक्षरता को बदलने के तमाम प्रयास करने के बावजूद, अधिक उपयुक्त, सीधे प्राप्त, साक्षरता के दक्षता स्तरों की सूक्ष्म अवधारणा वाला नया दृष्टिकोण, जो लक्ष्य 4.6 के लिए वैश्विक संकेतक पर रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक है, ने कुछ उच्च आय वाले देशों को छोड़कर अभी तक अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई है। एक अनुमान के अनुसार ओईसीडी के पीआईएएसी सर्वेक्षण में भाग लेने वाले देशों के 19% वयस्कों ने साक्षरता में न्यूनतम प्रवीणता का स्तर प्राप्त नहीं किया था।

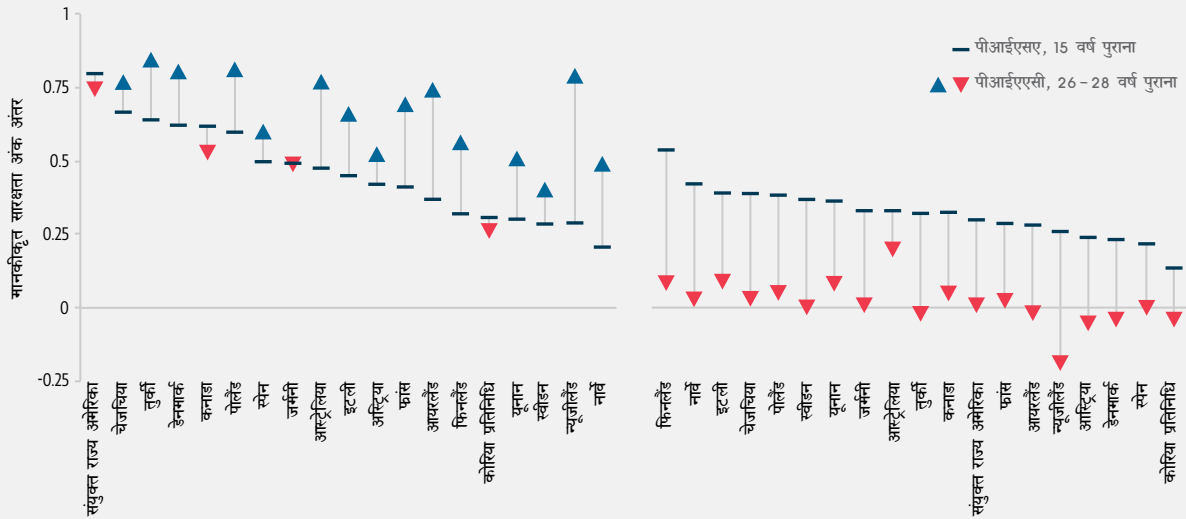
सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से साक्षरता और संख्यात्मक प्रवीणता में असमानता हर जगह व्याप्त है। उदाहरण के लिए, पीआईएएसी में भाग लेने वाले ओईसीडी देशों में ऐसी संभावना है कि ऐसे वयस्क, जिसके माता-पिता ने ऊपरी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, के उन वयस्कों की तुलना में संख्यात्मक प्रवीणता स्तर से नीचे गिरने की दर तीन गुणा से अधिक होगी जिनके माता-पिता को उच्च स्तरीय शिक्षा (33% बनाम 3%) प्राप्त थी। चेजेचिया और स्लोवाकिया में यह अंतर दस गुणा अधिक था (29% बनाम 3%)।

कुछ प्रकार की असमानता विकसित हो रही है। 15 साल की उम्र में किए गए पीआईएएसी सर्वेक्षण की 12 साल बाद पीआईएएसी सर्वेक्षण से तुलना करने पर युवा वयस्कता में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई दिया। सामाजिक-आर्थिक असमानता तुलना किए गए 20 देशों में 75% बढ़ गई और यह 15 साल की आयु वाले खराब प्रदर्शन करने वाले लोगों तक ही के बीच केंद्रित थी। इसके विपरीत, लैंगिक अंतर लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। हालांकि, पीआईएएसी सर्वेक्षण से 16 साल की उम्र में लिंग असमानता के कम होने का पता चला है, जो यह दर्शाता है कि इस परिवर्तन के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें दो सर्वेक्षण किए गए हैं (चित्र 13)।



**चित्र 13:**

जहां एक ओर 15 वर्ष की आयु में सामाजिक-आर्थिक साक्षरता में अंतर अगले 12 वर्षों में बढ़ गया था, वहीं दूसरी ओर लैंगिक असमानता समाप्त हो गई थी। पीआईएसए के अनुसार, चुनिंदा देशों में 15 साल की उम्र में तथा पीआईएसए के अनुसार 26 से 28 साल की उम्र में 2000-2003 से 2011-2014 के बीच मानकीकृत साक्षरता के बीच अंतर



स्रोत: बोरगोनीवी और अन्य (2017)।



## स्थाई विकास और वैश्विक नागरिकता

मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ज्ञान सहयोग और शांति एवं शिक्षा से संबंधित 1974 की सिफारिश के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को लक्ष्य 4.7 के लिए संकेतक पर प्रगति की निगरानी के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, नीति के कार्यान्वयन का स्व-मूल्यांकन नीति के उद्देश्यों के लिए वस्तुपरक विश्वसनीय या सूक्ष्म नहीं होना चाहिए तथा इनसे नीतियों को कार्यान्वित किया गया है का पता नहीं लगाया जा सकेगा। यूनेस्को राष्ट्रीय रिपोर्टों को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता को मान्यता देता है ताकि वह वैश्विक संकेतों की निगरानी की आवश्यकता को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

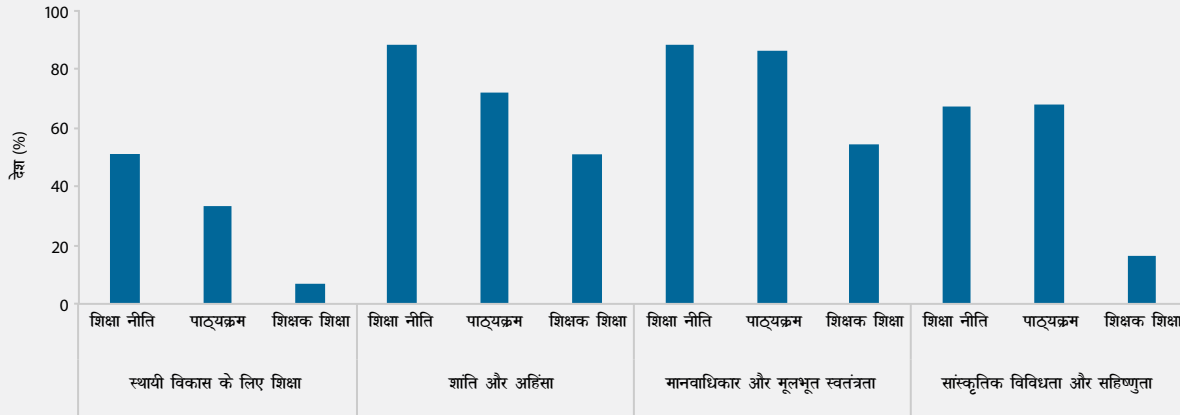
1974 के दौरान 51% से अधिक देशों में शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता की सूचना दी, लेकिन केवल 85 प्रतिशत ने नीति में स्थाई विकास हेतु तथा 33% ने पाठ्यक्रमों की सूचना दी। शिक्षक शिक्षा में लगभग आधे देशों ने शांति, अहिंसा, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को शामिल किया, 16% ने सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता को तथा केवल 7% ने स्थाई विकास के लिए शिक्षा को शामिल किया। (चित्र 14)।

कई देशों में शिक्षक लक्ष्य 4.7 से संबंधित विषय को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। शिक्षकों के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो गए हैं लेकिन इसके प्रयास संगठित नहीं हैं। आयरलैंड जमाइका ने प्रगति की है जिसमें प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा में स्थिरता और वैश्विक नागरिकता शामिल है। सतत व्यावसायिक विकास अधिक बार होने वाला शिक्षक सहायक टूल है लेकिन इसे शायद ही व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराया जाता है।

**चित्र 14:**

उत्तर प्रदेश में शिक्षा को शिक्षक शिक्षा में स्थाई विकास के लिए शामिल किया।

1974 के 5वें परामर्श की सिफारिश की सूचना देने वाले देशों का प्रतिशत, जिन्होंने शिक्षा नीति पाठ्यक्रम तथा शिक्षक शिक्षा 2012 में चयनित छात्रों की सूचना दी।



स्रोत: मेकएन्वोएय (2017)

लैंगिक पावर संबंधों से निपटने के लिए व्यापक स्कूल आधारित यौन शिक्षा कार्यक्रम को चलाने से यौन संचारित रोगों तथा अवांछित गर्भधारण की संभावना को कम किया जा सकता है। वर्ष 2015 में 48 देशों की समीक्षा से पाया गया कि लगभग 80% की नीतियां व्यापक एवं शिक्षा का समर्थन कर रही थीं, यद्यपि इनका हमेशा पालन नहीं किया गया था।

अभी भी इस बात पर सहमति नहीं हुई है कि स्थाई विकास और वैश्विक नागरिकता शिक्षक के लिए क्या किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर विज्ञान ज्ञान का आकलन एक सीधा सा विकल्प है। 2015 टीआईएसएस चरण में कोई आईईसीडी देशों में 15 वर्ष की आयु के 21.5% बच्चों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष संतोष क्षेत्र में न्यूनतम दक्षता स्तर के नीचे कार्य-निष्पादन किया। टीआईएसएस से पता चला कि 15 देशों में 2011 और 2015 के बीच प्राथमिक स्कूलों के छात्रों में पृथ्वी विज्ञान जानकारी में सुधार हुआ था, जबकि इसमें 9 देशों में गिरावट आई तथा 16 देशों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ।

छात्रों के मौजूदा उपकरणों की उपलब्धता केवल मूल शिक्षा तक ही थी। 2014-2016 की प्रायोगिक स्थाई साक्षरता परीक्षा से उच्च शिक्षा छात्रों और व्यक्तियों में स्थाई विकास पर ज्ञान का पता चला। भागीदारों ने परीक्षा में 54% में तथा 7% ने शिक्षा प्रणाली में मुख्य प्रश्नों के सही उत्तर दिए (घर पर और पर्यवेक्षक)। उन्होंने मानवाधिकारों तथा पर्यावरण मुद्दों पर अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया।

## पाठ्यपुस्तकों विविधता सहिष्णुता और शांति के एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण होती हैं

पाठ्यपुस्तकों न केवल विषय बल्कि सामाजिक मूल्य राजनीतिक पहचान इतिहास और दुनिया को समझने पर ज्ञान देती हैं। फिर भी, कई देशों में अभी भी सामाजिक सौहार्द राजनीतिक स्थिरता और धारती के भविष्य की महत्वपूर्ण अवधारणाओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करती।

“

1980 के दशक में 13% की तुलना में वर्ष 2000-2008 दुनिया भर में 25% पाठ्यपुस्तकों, अपने व्यवहार से बचने, समाधान निकालने और समायोजन करने पर चर्चा करनी चाहिए

”

वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य मानवाधिकारों लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। 1980 के दशक में 13% की तुलना में वर्ष 2000-2008 दुनिया भर में 25% पाठ्यपुस्तकों, अपने व्यवहार से बचने, समाधान निकालने और समायोजन करने पर चर्चा करनी चाहिए। कई पाठ्यपुस्तकें आज भी सैन्यवाद और युद्ध का महिमामण्डन करती हैं।

विविधता को कवर करना मुश्किल है: चार माध्यमिक सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकों में से केवल एक ने 2000-2011 में जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में उनका उल्लेख किया था। आप्रवासी और शरणार्थी अधिकारों का दायरा बढ़ गया है लेकिन अभी भी कुछ पाठ्यपुस्तकों में आज भी उन्हें पलायन और पलायनवादियों को शामिल किया गया है।

2010-2011 में 33% पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं के अधिकारों की बात की जबकि 1946 वर्ष 1969 में यह 15% थी। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव 16% से बढ़कर 30% हो गया है। तथापि, कई पाठ्यपुस्तकों में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। कई पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को शामिल नहीं करते या उन्हें विनम्र पारंपरिक भूमिका में दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कारकों ने सुधारों में सहायता करने में मदद की है। यूनेस्को ने विशेष रूप से मानदंडों और मानकों की स्थापना की है तथा बदलाव लाने में देशों की मदद की है। संघर्ष के बाद वाले देशों में ट्रांजिशनल न्याय पहल पेरू की तरह बदलाव ला सकता है जहां सत्य आयोग ने ऐसी पाठ्यपुस्तकों को बढ़ावा दिया है जो विविधता और मानवाधिकारों का सम्मान करती हैं। सिविल सोसाइटी कारक सरकार द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक कारक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण होते हैं।



## शिक्षा सुविधाएं और शिक्षा का वातावरण

स्कूलों के ढांचे का जायजा लेना जटिल है क्योंकि इसमें कई आयाम शामिल होते हैं। तथापि, स्कूलों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भौतिक ढांचे की स्थिति प्रायः सभी आय स्तरों, विशेषकर समाजिक आर्थिक उपेक्षित स्कूलों में बाधा पहुंचाती है। लेटिन अमेरिका के 2013 का तृतीय क्षेत्रीय तुलनात्मक और स्पष्टीकरण अध्ययन ने दर्शाया है कि सबसे अमीर ग्रेड के 4/5 से अधिक छात्रों ने पर्याप्त जल और स्वच्छता सुविधाओं के साथ आए जबकि सबसे गरीब छात्रों में से केवल एक तिहाई ही ऐसा कर पाए थे।

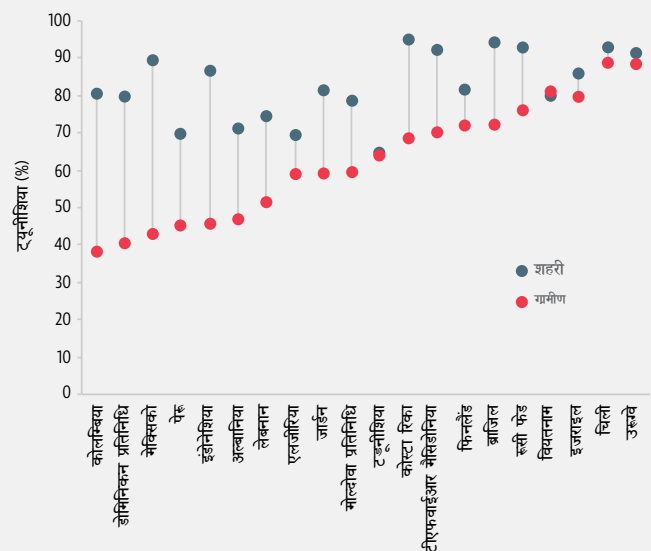
कई गरीब देशों में प्राथमिक स्कूलों में बिजली नहीं थी। उप-सहारा अफ्रीका में केवल 20% प्राथमिक स्कूलों में बिजली थी। देशों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट उपलब्धि में भी असमानता थी, जबकि ग्रामीण स्कूलों के शहरी स्कूलों से संबंध रहने की कम संभावना थी (चित्र 15)।

पेयजल की सुविधा वाले प्राथमिक स्कूलों का प्रतिशत 75% से कम था जो 148 देशों में से 72 था। उप-सहारा अफ्रीका में 17 देशों सहित 137 देशों में से 24 को बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो 30% से कम था।

विकलांग छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे उपकरण के आने-जाने का अभाव, गलत ढंग से डिजाइन की गई इमारतें, शिक्षण सहायक उपकरणों का अभाव तथा अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका तथा तुर्की सहित देशों में 35% से अधिक स्कूल संस्थान कमी से प्रभावित होते हैं।

चित्र 15:

ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की उपयोगिता की संभावना कम थी। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का स्थान चयनित विदेशों 2015 के अनुसार प्रतिशत



स्रोत: ओईसीडी (2016)

2004 के बाद से स्कूलों पर हमले में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे दक्षिण एशिया और उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशियाई प्रभावित हुआ है। वर्ष 2005 और 2015 के बीच सेना और सशस्त्र समूह में कम से कम 26 देशों ने सैन्य प्रयोगों के लिए वैश्विक संस्थान का प्रयोग किया।

## स्कूल से संबंधित जेंडर आधारित हिंसा से निपटना महत्वपूर्ण है।

स्कूल से संबंधित जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी कानून और नीतियों उपयुक्त, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री, शिक्षा क्षेत्र और अन्य कारकों के बीच शिक्षकों का प्रशिक्षण और सहायता पर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

देशों को ऐसा कानूनी ढांचा बनाने की जरूरत है जो स्पष्ट तौर पर छात्रों को वयस्क से बच्चों को और शिक्षकों के बीच हिंसा से बचाएँ और जवाबदेही सुनिश्चित करें। चिली, फिजी, फिनलैंड, पेरू और स्वीडन ऐसे देश हैं जिन्होंने कानून को विशेष रूप से स्कूली हिंसा का संदर्भ लेते हुए बनाया है। शिक्षकों की आचार संहिता में स्पष्ट रूप से हिंसा और उत्पीड़न का उल्लेख होना चाहिए था। इसमें कानूनी ढांचे के अनुरूप दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।

“ वर्ष 2005 और 2015 के बीच सेना और सशस्त्र समूह में कम से कम 26 देशों ने सैन्य प्रयोगों के लिए वैश्विक संस्थान का प्रयोग किया ”

कानून और नीतियां प्रायः अमल में नहीं लाई जातीं। कई देश नीतियों को लागू करने, पर्याप्त संसाधनों को आवंटित करने का मुख्य कार्य को कैसे पुलिस से सहायता सुनिश्चित कराने में असफल रहे हैं। प्रयास स्थानीय लोगों में अधिकारों और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता का अभाव होता है।

सूचना प्रदान करने वाली प्रणाली को विश्वसनीयता के रूप में देखा जाना चाहिए और पीड़ित की गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों द्वारा घटना की रिपोर्ट को सुनने उन्हें सहायता देने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मालावी में प्रशिक्षण के बाद स्कूल में होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति शिक्षकों की जागरूकता

पीड़ित कन्या के संबंध में 30% से 80% और पीड़ित लड़के के संदर्भ में 26% से 64% बढ़ गई। फिर भी स्कूल स्टाफ प्रायः सही ढंग से कार्यवाही नहीं करता। अमेरिका में एक-तिहाई से कम समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर ट्रांस सेक्सुअल या इंटरनेट छात्रों ने उत्पीड़न की सूचना दी थी, ने समस्या का समाधान किया था।

यौन विविधता से निपटने के लिए यौन शिक्षा तथा जेंडर पहचान अभिव्यक्ति नीदरलैंड की तरह स्कूल के वातावरण में सुधार कर सकती है। प्रायः यौन शिक्षा कार्यक्रम जेंडर गतिशीलता से निपटने के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से आगे कार्यवाही करने में असफल रहते हैं।

लड़का और युवाओं में जेंडर व्यवहार और मानकों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में भारत सहित हिंसा को समझने और उनके व्यवहार में सुधार करने तथा घटनाओं को कम करने के आशा जनक परिणाम प्राप्त हुए हैं जैसे स्कूल आधारित क्लब और खेल जेंडर के बारे में सकारात्मक संदेश देने के लिए कक्षाओं में निर्देश दिए जा सकते हैं।



## छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति पर वैश्विक संकेतक सहायता कार्यक्रम डेटा पर आधारित है। यह कई कारणों से अधूरा है क्योंकि कई दाता सहायता कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति शामिल नहीं होती। जो दाता ऐसा कर रहे थे, उनका खर्च 2010 में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2015 में 1.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे क्या या शिक्षा संहिता में समग्र कमी के समकक्ष 4% रह गया (चित्र 16)। आस्ट्रेलिया 23 प्रतिशत फ्रांस 14% और यूरोपीय संघ संस्थान 15% संपूर्ण छात्रवृत्ति सहायता का आधे से अधिक खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त, दाता अनुमानित छात्र लागत की सूचना देते हैं जो 2015 में 176 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी।

किसी देश द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति 33% में लगभग 423 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं दिए जा सकते जबकि कम विकसित देशों के छात्र 151 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करते हैं।

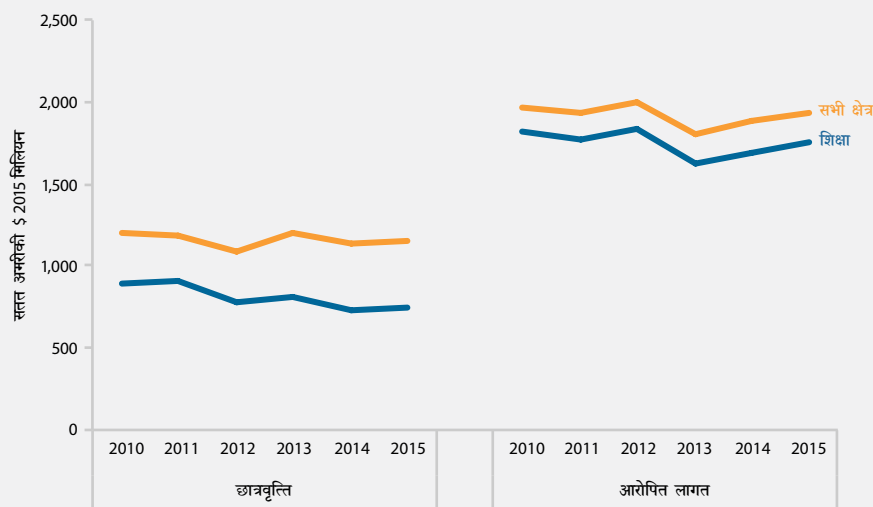
2016 जीईएम रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि छात्रवृत्ति डाटा निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान नहीं थी या उस तक पहुंचना कठिन था या उन्होंने लक्ष्य 4.2 पर रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र नहीं की थी। इस रिपोर्ट के लिए 5 देशों पर किए गए एक प्रायोगिक अध्ययन में मूल्यांकन किया कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम द्वारा तीन छात्रवृत्ति प्रबंधन एजेंसियों, 3 छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा 1 वित्त पोषण संगठन द्वारा आंकड़े कैसे एकत्रित किए गए थे। सूचित न करने पर भी डाटा इस तरह से प्राप्त हुआ कि जिसने लक्ष्य 4. ख की निगरानी करने में मदद की। छात्रवृत्ति की संख्या का प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए डेटा प्वाइंट का मानकीकरण करने क्षमता निर्माण करने तथा डाटा प्रबंधन में सहयोग विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी।

“ छात्रवृत्ति की संख्या का प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए डेटा प्वाइंट का मानकीकरण करने, क्षमता निर्माण करने तथा सहयोग करने के लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी ”

चित्र 16:

वर्ष 2010 से छात्रवृत्ति में सहायता लगभग उसी स्तर पर है।

छात्रवृत्ति पर सरकारी विकास सहायता वितरण तथा अनुमानित छात्र लागत 2010-2015 पर सरकारी विकास सहायता वितरण



स्रोत: ओईसीडी डीएसी लेनदार रिपोर्टिंग प्रभावी डाटा पर आधारित जीईएम रिपोर्ट टीम विश्लेषण



## शिक्षक

इस बात का डाटा सीमित है कि कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय मानव द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। वैश्विक रूप से 86% प्राथमिक स्कूल शिक्षक प्रशिक्षित हैं; यह अनुपात दक्षिण एशिया 70% कैरेबियन 70% और उप-सहारा अफ्रीका का 62% में कम है।

“

वैश्विक रूप से 86%  
प्राथमिक स्कूल शिक्षक  
प्रशिक्षित हैं

”

यह आश्चर्यजनक है कि हालांकि कई उपसंहार अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में हमेशा से सकारात्मक रुझान रहा है लेकिन ईरिशिया, घाना और नाइजर जैसे देशों में प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत 2000 से घटा है (चित्र 17)।

एसडीजी लक्ष्य से आशय योग्य शिक्षक कौन से हैं जबकि वैश्विक संकेतक प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित होते हैं जो कुछ कम चलाते हैं। योग्य शिक्षक वह होते हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं जबकि प्रशिक्षित शिक्षकों के पास व्यवसायिक प्रशिक्षण होता है। कुछ देशों में शिक्षकों की तैयारी में आवश्यकता के बीच अंतर के कारण इन दोनों के बीच असमानता है। बिहार अंतर नियम और निम्न मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक है उदाहरण के लिए जमाइका में 15% माध्यमिक स्कूल शिक्षक योग्य हैं जबकि 85% प्रशिक्षित हैं।

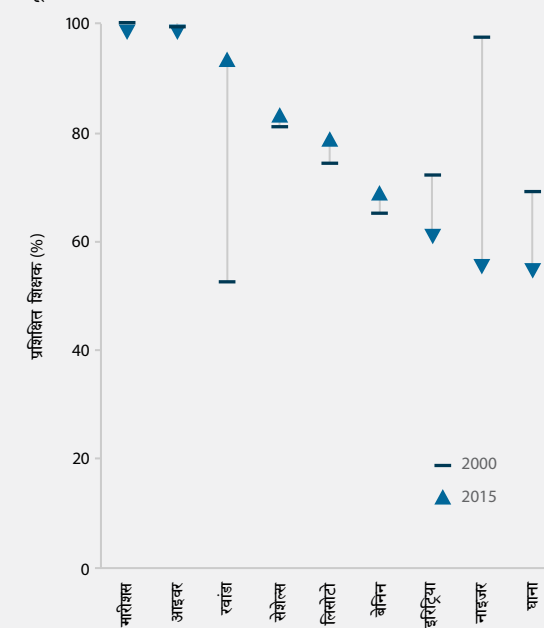
प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई तुलनात्मक परिभाषा बनाना काफी कठिन है और शिक्षकों का वैश्विक वर्गीकरण बनाने की वर्षों तक विकसित होने की संभावना नहीं है। राष्ट्रों के बीच सर्वेक्षण एक विकल्प हो सकते हैं क्योंकि वह शिक्षक की विशेषताओं पर सूचना दर्ज करते हैं। उदाहरण के लिए कि टीआईएमएस से पता चला है कि योग्य और प्रशिक्षित गणित शिक्षकों द्वारा बनाए गए कक्षा 4 के छात्रों का प्रतिशत 2007 और 2015 के बीच 89 प्रतिशत से घटकर 14% रह गया लेकिन डेनमार्क में 18 प्रतिशत से बढ़कर 35% हो गया।

विश्व स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात गरीब देशों में अधिक है लेकिन प्राथमिक शिक्षा के छात्रों के प्रति शिक्षक संख्या 2000 से घटी है।

शिक्षकों के वेतन व्यावसायिक विकास और स्कूल छोड़ने की दर पर सूचना कम है। ओईसीडी देशों में शिक्षक समान योग्यता होने पर भी अन्य कामगारों से कम कमाते हैं। टीएलआईएस सर्वेक्षण में लगभग 88% निम्न माध्यमिक शिक्षकों ने 2013 में व्यावसायिक विकास में भाग लिया था।

चित्र 17:

कुछ उप-सहारा अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत घटा है।  
चुनिंदा उप-सहारा अफ्रीकी देशों में 2000 वर्ष 2015 में प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का प्रतिशत



स्रोत: यूआईएस डेटाबेस

# शिक्षा और अन्य एसडीजी

शिक्षा अनेक एसडीजी में परिणाम प्राप्त करने का निर्णायक प्रयोग है जिस में स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा शामिल है।

## शिक्षा गैर-संचारी रोगों को रोकने में मदद कर सकती है

2012 में कैंसर मधुमेह चिरकालिक सांस की बीमारियां तथा हृदय रोगों सहित गैर संचारी रोग दुनिया भर में 68% है और इनमें से तीन चौथाई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में थे। शिक्षा इन लोगों की व्याप्तगता को कम करके व्यवहार में परिवर्तन लाकर मदद कर सकती है।

तंबाकू के सेवन से 2015 में 6.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। गरीब और अमीर दोनों देशों में अधिक पढ़े लिखे लोगों के तंबाकू का सेवन करने की संभावना कम थी। निम्न औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुषों की संख्या 1.75 के बीच थी जिनके द्वारा धूम्रपान किए जाने की संभावना थी क्योंकि इनके न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों में धूम्रपान करने की संभावना 6.5 गुणा थी। अमेरिका में उच्च स्कूल छोड़ने वालों में कॉलेज स्नातक की तुलना में धूम्रपान करने की संभावना अधिक थी।

औपचारिक शिक्षा के अलावा, मास मीडिया अभियान धूम्रपान को हतोत्साहित करने में प्रभावी हो सकते हैं। तथापि, यह कुछ सामाजिक आर्थिक चर्चा रखने वाली आबादी के लिए अधिक प्रभावी होता है इससे धूम्रपान करने वालों में असमानता बढ़ सकती है। इनकी रूपरेखा बेहतर ढंग से बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि संवेदनशील आबादी को लक्षित किया जा सके।

दुनिया भर में 1980 और 2014 के बीच मोटापा दुगने से अधिक हो गया है। शिक्षा प्राप्ति और मोटापे के बीच संबंध देश की आर्थिक विकास दर तथा मोटापे की समग्र व्याप्तता पर निर्भर करता है। कम आय वाले देशों, जहां मोटापे की व्याप्तता कम है, वहां अधिक शिक्षित महिलाओं के मोटे होने की अधिक संभावना रहती है। जबकि उच्च आय वाले देशों में उच्च स्तरीय शिक्षा में इसकी कम संभावना रहती है।

माता पिता की शिक्षा का बाल्यावस्था पर प्रभाव पड़ता है जिनका प्रभाव पुनः आर्थिक विकास दर पर निर्भर करता है। केन्या में शिक्षित माता-पिता के बच्चों के अधिक मोटा होने की संभावना थी लेकिन उनके ब्राजील में अधिक मोटा होने की संभावना कम थी।

स्कूलों में बेहतर पोषण को प्रोत्साहित करने से आजीवन अच्छी बातें सीखने में मदद मिलती है। सेइनाजोकी, फिनलैंड में शिक्षा नीति में स्वास्थ्य से जुड़े एक कार्यक्रम को 2009 और 2015 के बीच 5 वर्ष के बच्चों में मोटापे को 17% से घटाकर 10% करने का श्रेय दिया जाता है।

## शिक्षा एसडीजी कार्यनीतियां लागू करने के लिए क्षमता निर्माण करने में मदद करती है

कुशल पेशेवरों को स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एसडीजी 3 के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2013 में विश्व स्तर पर 17.4 मिलियन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी का अनुमान लगाया था और यह अनुमान भी लगाया था कि यह 2030 में 14.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें सबसे गरीब उप-सहारा अफ्रीकी देशों में आवश्यकता आधरित अत्यधिक कमी होगी। अफ्रीकी, एशियाई और कैरेबियन डाक्टरों और नर्सों के उच्च अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता का अर्थ है कि कम आय वाले देश पेशेवरों को खो देंगे और उन्हें उच्च वित्तीय बोनस का सामना करना पड़ेगा। अमीर देशों को चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना चाहिए, जो उनकी जनता की सेवा करते हैं, भले ही वे कहीं भी प्रशिक्षित हुए थे।

संस्थागत और अनुदेशात्मक कमियों से समानता चुनौतियां पैदा होती हैं: उप सहारा में 26 देशों में 2008 में एक या कोई चिकित्सा स्कूल नहीं था। देशों में, शहरी समुदाय चिकित्सा लाभ लेने में सबसे आगे है, जिससे ग्रामीण आबादी अल्पसेवित रह जाती है। क्षमता में सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए स्कूल से लेकर रोजगार दिलाने तक, युवा प्रशिक्षण और सतत व्यावसायिक विकास, अस्पताल और विश्वविद्यालय आधारित प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए मानव संसाधन नियोजन को बेहतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों से जोड़ा जाना चाहिए।

एसडीजी 6 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में मानव क्षमता के मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सर्वेक्षण किए गए 94 देशों में से, 15% से कम देशों ने कम से कम प्रत्येक दो साल बाद अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा की। धन की कमी और कुशल स्नातकों और कुशल श्रमिकों की ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की अनिच्छा के कारण क्षमता विकास रूका है।

“ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्तर पर 2030 में 14.5 मिलियन स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की कमी का अनुमान लगाया है ”

खाद्य सुरक्षा पर एसडीजी 2 लक्ष्य हासिल करने के लिए, शिक्षा और क्षमता निर्माण जरूरी है। अधिक शिक्षित किसान, अधिक उत्पादक होते हैं और वे जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए अधिक उपाय करते हैं। पाकिस्तान में, शिक्षित किसानों द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके पानी के उन्नत पंपों का उपयोग करने की अधिक संभावना थी, क्योंकि उन्हें नई खोज और उसके उपयोग की बेहतर जानकारी थी।

स्वास्थ्य, कृषि, जल और स्वच्छता क्षेत्रों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में लागू करने पर जोर देना चाहिए। एसडीजी की प्रगति के लिए लक्षित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है जो क्षमता निर्माण में इक्विटी समस्याओं, कुशल कामगार वितरण और जन जागरूकता अभियान को प्राथमिकता देती है।

## वित्त

शिक्षा के वित्तपोषण में प्रमुख योगदान सरकारों, दानदाता और परिवारों का होता है। शिक्षा के वर्तमान वित्त-पोषण का स्तर अपर्याप्त हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण भिन्न है कि किसे अधिक भुगतान करना चाहिए।

### सरकारी व्यय

2015 में, मध्यम वैश्विक सार्वजनिक शिक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% था, जो शिक्षा 2030 कार्य फ्रेमवर्क द्वारा प्रस्तावित 4% से 6% के भीतर था। कम आय वाले देशों में व्यय 3.7% से लेकर उच्च आय वाले देशों में 5.1% था। हालांकि, 2014 में सार्वजनिक शिक्षा व्यय, कुल सार्वजनिक शिक्षा व्यय का 14.1% था, जो फ्रेमवर्क द्वारा प्रस्तावित 15% से 20% से कम था। कम से कम 34 देशों - गरीब और अमीर, दोनों - में से कोई भी इन शिक्षा वित्तपोषण मानकों को पूरा नहीं करते (चित्र 18)।

चित्र 18:

कम से कम 33 देश किसी भी शिक्षा वित्तपोषण मानक को पूरा नहीं करते

सकल घरेलू उत्पाद के एक भाग के रूप में और कुल सार्वजनिक व्यय 2015 या सबसे हाल के वर्षों के एक भाग के रूप में सार्वजनिक शिक्षा खर्च



स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।



## सहायता व्यय

एसडीजी 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए, निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में शिक्षा के लिए सहायता 2012 के स्तर से छह गुणा होनी चाहिए। जबकि, 2015 में शिक्षा के लिए कुल सहायता 2010 के स्तर से 4% नीचे थी, यद्यपि इस अवधि के दौरान कुल सरकारी विकास सहायता में 24% की वृद्धि हुई थी। दानदाता अपनी प्राथमिकताओं में शिक्षा को तरजीह नहीं दे रहे हैं। कुल सहायता में उनकी हिस्सेदारी (ऋण राहत को छोड़कर) में पिछले लगातार छह वर्षों से गिरावट आई है जो 2009 में 10% से घटकर 2015 में 6.9% रह गई है।

प्राप्तकर्ता देशों के वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए लक्षित आवश्यकताओं में सुधार करने की आवश्यकता है। कम आय वाले देशों को 2015 में शिक्षा के लिए कुल सहायता का 19% और बुनियादी शिक्षा के लिए 23% प्राप्त हुआ, जबकि 2014 में यह क्रमशः 21% और 29% था (चित्र 19)। क्षेत्रीय रूप से, उप-सहारा अफ्रीका, जहां दुनिया के स्कूल न जाने वाले लगभग आधे बच्चे हैं, 2015 में 26% बुनियादी शिक्षा सहायता प्राप्त की, जो 2002 के स्तर के आधे से कम है।

2016 में शिक्षा के लिए मानवीय सहायता में 50% से अधिक अर्थात् अमेरिका 303 अमेरिकी मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, लेकिन आपात स्थिति में शिक्षा के लिए वित्त-पोषण अपर्याप्त है जो कुल का 2.7% है।

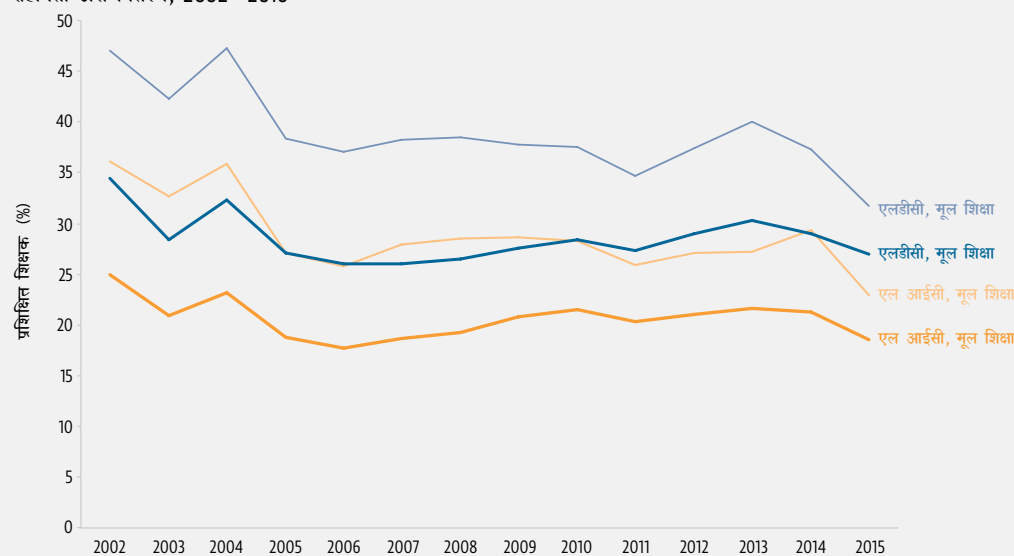
शिक्षा के लिए सहायता के मौजूदा स्तर के आवश्यकता से काफी अधिक कम रहने पर जरूरत इस बात की है कि एसडीजी के प्रमुख 4 लक्ष्यों, मौजूदा और संभावित उभरते कार्यक्रमों को प्राप्त किया जाए ताकि शेष योग्यता आधारित कमियों को पूरा करने में मदद मिल सके। वैश्विक शिक्षा भागीदारी के 2018 के शुरू में अपना प्रतिपूर्ति अभियान पूरा करने की उम्मीद है, जो - यदि सफल रहता है - तो वार्षिक वितरण स्तर में चार गुना की वृद्धि होगी।

प्रारंभ में वित्त-पोषण वैश्विक शिक्षा अवसर पर अंतरराष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त सुविधा की स्थापना को बढ़ावा मिला था, जिसे तब बढ़ावा मिला था जब इसके संदर्भ को हैम्बर्ग में जुलाई 2017 शिखर सम्मेलन में जी-20 नेताओं ने घोषणा को शामिल किया था। इसका उद्देश्य निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए विकास बैंकों को उधार देने की क्षमता का विस्तार करना है।

अंत में, यूनिसेफ द्वारा आयोजित, शिक्षा प्रतीक्षा नहीं कर सकती, का लक्ष्य आपात स्थिति में शिक्षा प्रदानगी को बदलने के लिए न केवल तेजी से निधियां उपलब्ध करना था, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण रूप से, मानवीय और विकास सहायता के बीच की खाई को भी पाटना था। दाताओं को संगठित और समन्वित तरीके से यह सुनिश्चित करना था कि ये तीन पहलें एक दूसरे के पूरक हों और इनमें अनावश्यक प्रशासनिक खर्च न जुड़े या प्रयासों का दोहरापन न हो।

चित्र 19:

निम्न आय वाले देशों को बुनियादी शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता के अंश में 2015 में तेजी से गिरावट आई निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) और न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) का शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा के लिए कुल सहायता अंश वितरण, 2002-2015



स्रोत: ओईसीडी-डीएसी ऋणदाता रिपोर्टिंग प्रणाली पर आधारित जीईएम रिपोर्ट टीम का विश्लेषण।

## घरेलू खर्च

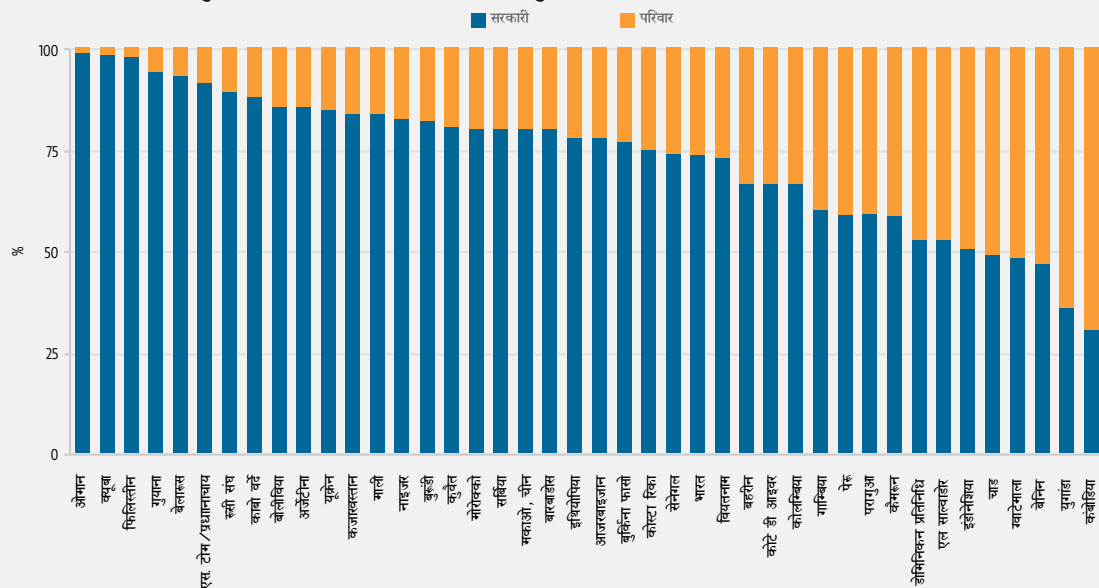
शिक्षा की लागत, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में परिवारों के लिए एक प्रमुख बाधा थी, को अपर्याप्त माना जाता है। कई मंत्रालय सार्वजनिक और निजी खर्च का समग्र रूप से आकलन करने में असफल रहे हैं। इसके अलावा, घरेलू सर्वेक्षणों के मानकीकरण के अभाव का अर्थ है कि अनुमान कुल घरेलू खर्च से अधिक या कम बताया गया हो सकता है। यूनेस्को, ओईसीडी और यूरोस्टेट ने एक मानक बनाया है, लेकिन इसने अभी तक सर्वेक्षण डिजाइन को प्रभावित नहीं किया है।

घरेलू खर्च को शामिल करने से शिक्षा के क्षेत्र में देशों के निवेश करने की समझ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अल साल्वाडोर की सरकार फ्रांस की तुलना में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत अंक खर्च करती है, लेकिन अल साल्वाडोर समग्र रूप से अधिक खर्च करता है क्योंकि परिवार शिक्षा को सकल घरेलू उत्पाद का तीन से अधिक प्रतिशत अंक आवंटित करते हैं। सामान्य तौर पर, परिवारों द्वारा शिक्षा पर व्यय की गई कुल शिक्षा हिस्सेदारी, उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम आय वाले देशों में अधिक है।

जिन देशों का डेटा उपलब्ध है, उनमें कुल शिक्षा व्यय में परिवारों की हिस्सेदारी उच्च आय वाले देशों में 15%, मध्यम आय वाले देशों में 25% तथा निम्न आय वाले देशों में 32% है। यूरोपीय संघ और ओईसीडी के सदस्य देशों को छोड़कर, तीन देशों में एक से अधिक परिवारों की हिस्सेदारी कुल का कम से कम 30% थी। कंबोडिया में, 2011 में शेयर 69% था (चित्र 20)।

चित्र 20:

एक-तिहाई देशों में, परिवार कुल शिक्षा लागत में कम से कम एक-तिहाई का योगदान देते हैं  
वित्त-पोषण के स्रोत द्वारा चुनिंदा देशों, 2005-2015 तक के दौरान कुल शिक्षा व्यय का वितरण



टिप्पणी: आंकड़ों में यूरोपीय संघ और ओईसीडी देशों को छोड़कर इस अवधि के दौरान डेटा सहित सभी देश शामिल हैं।  
स्रोत: यूआईएस डेटाबेस।

## स्वास्थ्य के क्षेत्र से सबक लेते हुए राष्ट्रीय शिक्षा खाते खोलना

वैश्विक शिक्षा भागीदारी, यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान और यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान द्वारा समर्थित राष्ट्रीय शिक्षा लेखा ढांचा देशों में सार्वजनिक और घरेलू स्रोतों से शिक्षा व्यय की तुलना करने का एक माध्यम है। इसका लक्ष्य व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित प्री-प्राइमरी से उच्च स्तरीय शिक्षा तक के सभी शिक्षा स्तरों की निगरानी करना, और सभी प्रदाताओं और वित्त-पोषण के स्रोतों को कवर करना है।

अपने पिछले कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता प्रणाली से सबक लेते हुए शिक्षा लेखा ढांचा लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य खाता खोलने की प्रणाली पर 2000 में सहमति हुई थी और इसमें 2011 में संशोधन किया गया था, और 112 देशों ने उस ढांचे के आधार पर खातों को रखा था। फिर भी, बहुत अधिक

देशों ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया है, और इसकी दाता आधारित परियोजना के रूप में आलोचना हुई है। क्षमता की कमी का अर्थ है कि खातों ने कभी-कभार अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों पर भरोसा किया और क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए यह प्रक्रिया हमेशा देश से जुड़ी नहीं रही है। शिक्षा खातों के लिए, डेटा को विशेष रूप से बजट के लिए, राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी बनाया जाना चाहिए, तथा संसाधनों को इसकी उपयोगिता को सूचित करने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा लेखा प्रायोगिक परियोजना, जो 2016 में समाप्त हो गई थी, से वित्तपोषण प्रणाली का मूल्यांकन करने, इसकी रूपरेखा को फिर से बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने की योग्यता की संभावना का पता चलता है। अगला चरण शिक्षा व्यय डेटा संग्रह के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्य बल बनाना तथा ज्ञान एवं चुनौतियों को साझा करने के लिए देशों को सक्षम बनाने हेतु एक मंच स्थापित करना होना चाहिए।

“ शिक्षा व्यय आंकड़ा जुटाने में अंतरराष्ट्रीय कार्यबल के साथ-साथ एक मंच बनाया जाना चाहिए, ताकि देश जानकारी और चुनौतियों को परस्पर साझा कर सकें। ”

## सिफारिशें

समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने की वैश्विक आम प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सभी के लिए एक स्पष्ट जवाबदेही प्रणाली होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में सभी दृष्टिकोणों को दर्शाया गया है जिनमें ऐसे देश, जहां जवाबदेही की अवधारणा मालूम नहीं है, और शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन को कोई चुनौती नहीं दी जाती, से लेकर ऐसे देश शामिल हैं, जहां जवाबदेही शिक्षा में सुधार करने की बजाय स्वतः समाप्त हो गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही सरकारों से प्रारंभ होती है, जिनका प्राथमिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। दुनिया के हर देश ने कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय संधि करके शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाते हुए पुष्टि की है। हालांकि, केवल 55% देशों में शिक्षा का अधिकार न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को कानूनी रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वे शिक्षा प्रणाली में विफलताओं को चुनौती दें। नागरिक समाज संगठन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शिक्षा का अधिकार की हिमायत करनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में इस अधिकार को न्यायोचित बनाना शामिल है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून केवल तभी शक्तिशाली हैं, जब उन्हें लागू किया जाए। प्रभावी जवाबदेही के लिए सरकारों को कानूनों को लागू करने के लिए ठोस प्रणालियां बनानी होंगी। इसलिए इस रिपोर्ट में सरकारों - तथा अन्य लोगों, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में हिस्सेदारी है - ताकि वे ठोस जवाबदेही प्रणाली की रूपरेखा बनाकर उसे लागू कर सकें।

### एक ठोस जवाबदेही प्रणाली को डिजाइन करना

- सरकारों को सभी शिक्षा प्रदायकों - सभी सरकारी स्तरों और विभागों, वैधानिक और न्यायिक प्राधिकारियों, स्वायत्त संस्थानों, स्कूलों, शिक्षकों, माता-पिता, छात्रों, नागरिक समाज, शिक्षकों की यूनियनों, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों - में विश्वास कायम करने के लिए सार्थक और चुनिंदा कार्य करने और संबंधित जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इन उपायों में निम्नलिखित कदम शामिल होंगे:
  - बहु हितधारकों, विशेषकर जो सरकार से बाहर बैठे हैं, के बीच सार्थक बातचीत के लिए औपचारिक मंच उपलब्ध कराना।
  - नियमित समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने तथा अपने सदस्यों की क्षमता का निर्माण करके विधानमंडल की शिक्षा समितियों की भूमिका को सुदृढ़ बनाना।
  - एक वार्षिक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट का प्रकाशन करना जिसमें की गई कार्रवाई तथा परिणामों का उल्लेख हो, जिसमें उन्होंने जनता के लाभ के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में अपना योगदान दिया है।
- सरकारों को विश्वसनीय शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं और जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए तथा निष्ठापूर्वक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा प्रणाली के द्वारा पारदर्शी बजट बनाना चाहिए। मूल रूप से, सरकारी प्रदायकों को तब तक जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक यह स्पष्ट न हो कि वे किसके लिए जिम्मेदार हैं। बजट दस्तावेज पारदर्शिता से यह स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि विशेषकर विधानमंडल में महत्वपूर्ण समीक्षा के लिए यह आवश्यक जानकारी दी जाए कि धनराशि कब और कहाँ जारी की जाती है।
- जब मानकों का पालन न किया जा रहा हो तो सरकारों को विश्वसनीय और कुशल विनियम और निगरानी प्रणाली बनाते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए तथा प्रतिबंध लगाने चाहिए। इनमें सार्वजनिक और निजी शिक्षा दोनों तथा संबद्ध सहायक सेवाओं के प्रदाताओं को शामिल करना चाहिए। पंजीकरण और मान्यता या बोली और करार की प्रक्रियाएं स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन नियमों में भी शिक्षा में समानता और गुणवत्ता पहलुओं का समाधान किया जाना चाहिए।
- सरकारों को स्कूल और शिक्षक जवाबदेही प्रणालियों की रूपरेखा बनानी चाहिए जो सहायक और रचनात्मक हों, और इनमें ऐसी दंडात्मक प्रणाली, विशेषकर संकीर्ण प्रदर्शन उपायों पर आधारित प्रकारों से बचना चाहिए। स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने या शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों की परीक्षा के अंकों का उपयोग करने से एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आधारित वातावरण बनेगा, इससे पाठ्यक्रम का दायरा कम होगा, शिक्षा परीक्षा तक सीमित हो जाएगी, शिक्षक और कमजोर छात्र हतोत्साहित होंगे, जिनका समग्र शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

5. सरकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा की निगरानी करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए स्वतंत्र संस्थान स्थापित करने की जरूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सरकार में नागरिकों की आस्था को बढ़ाते हैं और मतदाता प्रतिस्पर्धा से निर्वाचित सदस्य नागरिकों की मांगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सकते हैं। मीडिया विशेष रूप से जनसंख्या समूहों, जिनकी पहुंच सीमित होती है, के बारे में आसानी से समझने योग्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान कर सकते हैं। लोकपाल कार्यालय नागरिक शिकायतों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर सकता है, जब तक कि राजनीतिक प्रोत्साहनों को इन शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता के साथ जोड़ा नहीं जाता।

## एक ठोस जवाबदेही प्रणाली लागू करना

रूपरेखा के बावजूद, यदि सरकारों और अन्य प्रमुख हितधारकों में वास्तविक प्रतिबद्धता और उचित जानकारी, संसाधन और क्षमता की कमी है, तो जवाबदेही प्रणालियों को लागू करना काफी मुश्किल होता है।

1. **सूचना: निर्णय लेने वालों को पारदर्शी, प्रासंगिक और समय पर डेटा उपलब्ध कराया जाए।**
  - क. सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसी सूचना में निवेश करें जिससे शिक्षा प्रणाली की खूबियों और कमियों को जानने-समझने में सुधार हो तथा एक प्रभावी जवाबदेही प्रणाली बनाने में मदद मिले।
  - ख. इसके साथ-साथ, उन्हें इस डेटा का सोच-समझकर उपयोग करना चाहिए। जानकारी का अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए और संग्रह की लागत देश की क्षमता से मेल खानी चाहिए ताकि इस पर कार्रवाई हो सके।
  - ग. शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए कार्य की रिपोर्टिंग केवल प्रक्रियात्मक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे शिक्षा में सुधार करने से जोड़ा जाना चाहिए।
2. **संसाधन: शिक्षा प्रणाली के वित्त-पोषण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए।**
  - क. सरकारों को शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 4% खर्च करने या कुल सरकारी व्यय का 15% आवंटित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए।
  - ख. दाता देशों को सहायता के लिए राष्ट्रीय आय का 0.7% प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए। इसमें से, 10% का आवंटन बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उन्हें परिणाम आधारित प्रणाली के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे उन देशों को जोखिम हो सकता है जो इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं।
3. **क्षमता: प्रदायकों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।**
  - क. सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुदृढ़ संस्थान स्थापित हों, जिनमें पुलिस, न्यायिक और लेखा परीक्षा कार्य करने वाले शामिल हों, जिनमें शिक्षा में भ्रष्टाचार को रोकने, उसका पता लगाने और छानबीन करने में मदद करने की क्षमता हो।
  - ख. सरकारों को शिक्षकों को पेशेवर मानना चाहिए। सरकार को शिक्षकों को आवश्यक प्रारंभिक और सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने और स्वायत्तता प्रदान करके उनकी व्यावसायिकता का निर्माण करने में मदद करनी चाहिए। इसके बदले में, शिक्षक यूनियनों को आचार संहिता के माध्यम से व्यावसायिकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सदस्यों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए तथा ऐसी उन लोगों में दक्षता बढ़ानी चाहिए जिन्हें ऐसी आंतरिक जवाबदेही प्रणाली के जरिए निम्नलिखित कार्य सौंपा गया है।
  - ग. सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक मूल्यांकनकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे शिक्षकों का सहायता प्रदान करने और उन्हें न्यायसंगत, उच्च गुणवत्ता वाले और समावेशी निर्देश देने के लिए योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
  - घ. सरकारों को अपने प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि वे सक्रिय रूप से भाग ले सकें और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के काम की निगरानी कर सकें। इसके बदले में, अंतरराष्ट्रीय संगठन समावेशी और पारदर्शी होने चाहिए तथा उन्हें अपने सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए।











# शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही:

अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (जीईएम रिपोर्ट) का दूसरा संस्करण संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के शिक्षा लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति पर अद्यतन साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

करोड़ों लोग अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कई लोग न्यूनतम कौशल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शिक्षा प्रणाली अपने वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पटरी से उतर चुकी है। वर्तमान में उपेक्षित वर्ग सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन यदि नीति निर्माता उनकी जरूरतों की ओर पर्याप्त ध्यान दें तो उन्हें इसका सबसे अधिक लाभ हो सकता है। इन चुनौतियों और बजट की कमी से जूझते हुए तथा पैसे के परिणाम आधारित मूल्य पर अधिक बल देते हुए, देश समाधान खोज रहे हैं। जवाबदेही का बढ़ना प्रायः सूची में सबसे ऊपर होता है।

2017/8 जीईएम रिपोर्ट के इस सार में शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में सभी दृष्टिकोणों को दर्शाया गया है जिनमें ऐसे देश, जहां जवाबदेही की अवधारणा मालूम नहीं है, और शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन को कोई चुनौती नहीं दी जाती, से लेकर ऐसे देश शामिल हैं, जहां जवाबदेही शिक्षा में सुधार करने की बजाय स्वतः समाप्त हो गई है।

रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा एक साझी जिम्मेदारी है। हालांकि शिक्षा सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, सभी प्रदायक - स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र प्रदाताओं, नागरिक समाज और मीडिया - की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में भूमिका होती है। रिपोर्ट में पारदर्शिता के महत्व और जानकारी की उपलब्धता के महत्व पर जोर दिया गया है लेकिन इसमें यह सावधानी बरती जाती है कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाए। यह परिभाषित परिणामों और दंडात्मक प्रतिबंध लगाने से बाल-बाल बचने के लिए असंगत तरीके से जवाबदेही से बचने का मामला है। अनेक प्रकार के जवाबदेही उपायों के युग में, यह रिपोर्ट उन लोगों पर से स्पष्ट रूप से पर्दा उठाती है कि कौन काम कर रहे हैं और कौन नहीं।

